GOVERNMENT BILL

The Citizenship Amendment (Bill), 2019

MR. CHAIRMAN: The Citizenship (Amendment) Bill, 2019. Shri Amit Shah to move a Motion for consideration of the Citizenship (Amendment) Bill, 2019.

गृह मंत्री (श्री अमित शाह): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ:-

"कि नागरिकता अधिनियम, 1955 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर, लोक सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाए।"

MR. CHAIRMAN: Motion moved. There are four amendments by Shri K.K. Ragesh, Shri Husain Dalwai, Shri Binoy Viswam and Shri Elamaram Kareem for reference of the Citizenship (Amendment) Bill, 2019, as passed by the Lok Sabha, to a Select Committee of the Rajya Sabha. Members may move the amendments at this stage without any speech. While moving the amendments, these Members — they have given some names — they have to give the names also.

So, Mr. K.K. Ragesh, are you moving the Amendment?

SHRI K.K. RAGESH (Kerala): Sir, I move:

"That the Bill further to amend the Citizenship Act 1955, as passed by Lok Sabha, be referred to a Select Committee of the Rajya Sabha, consisting of the following Members:-

1. Shri K. K. Ragesh
2. Shri B. K. Hariprasad
3. Shri Tiruchi Siva
4. Shri Elamaram Kareem
5. Shri Binoy Viswam
6. Prof. Manoj Kumar Jha
7. Shri Sanjay Singh

with instructions to report by the last day of the first week of the next Session of the Rajya Sabha".

MR. CHAIRMAN: Shri Hussain Dalwai, are you moving the Amendment?

SHRI HUSAIN DALWAI (Maharashtra): Sir, I move:

"That the Bill further to amend the Citizenship Act 1955, as passed by Lok Sabha, be referred to a Select Committee of the Rajya Sabha, consisting of the following Members:-

1. Shri Husain Dalwai
2. Shrimati Viplove Thakur
3. Shri B. K. Hariprasad
4. Prof. Manoj Kumar Jha
5. Shri Tiruchi Siva
6. Shri Satish Chandra Misra
7. Dr. K. Keshava Rao
8. Dr. Amee Yajnik
9. Shri Sanjay Singh
10. Shri Praful Patel

with instructions to report by the last day of the first week of the next Session of the Rajya Sabha".

MR. CHAIRMAN: Shri Binoy Viswam. Are you moving the amendment?

SHRI BINOY VISWAM (Kerala): Sir, I move:

"That the Bill further to amend the Citizenship Act, 1955, as passed by Lok Sabha, be referred to a Select Committee of the Rajya Sabha, consisting of the following Members:-

1. Shri K. Somaprasad
2. Prof. M.V. Rajeev Gowda
3. Prof. Manoj Kumar Jha

4. Shri Sanjay Singh

5. Ch. Sukhram Singh Yadav

6. Shri K.K. Ragesh

7. Shri T.K. Elangovan

8. Shri Binoy Viswam

with instructions to report by the last day of the next Session of the Rajya Sabha".

MR. CHAIRMAN: Shri Elamaram Kareem, are you moving the Amendment?

SHRI ELAMARAM KAREEM (Kerala): Sir, I move:

"That the Bill further to amend the Citizenship Act 1955, as passed by Lok Sabha, be referred to a Select Committee of the Rajya Sabha, consisting of the following Members:-

1. Shri Abdul Wahab

2. Shri K.K. Ragesh

3. Shri T.K. Rangarajan

4. Shri M. Shanmugam

5. Shri Tiruchi Siva

6. Shri Binoy Viswam

7. Prof. Ram Gopal Yadav

with instructions to report by the last day of the first week of the next Session of the Rajya Sabha".

MR. CHAIRMAN: The Motion for consideration of the Citizenship (Amendment) Bill, 2019, as passed by Lok Sabha, and the amendments moved thereto are now open for discussion. ...*(Interruptions)*... Yes, Mr. Minister, if you want to say ...*(Interruptions)*... One minute. Amitji, one minute. ...*(Interruptions)*...

SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY (West Bengal): Sir, under Rule 230 of the Rules and Procedures of Rajya Sabha, I have given notice that there is no nexus. The debate should be adjourned because there is no nexus, reasonable nexus, between the Statement of Objects and Reasons and the Bill because in the Statement of Objects and Reasons, it has been stated in Paragraph 2, I may read with your kind permission only one line, that 'The Constitutions of Pakistan, Afghanistan and Bangladesh provide for a specific State religion.

As a result, many persons belonging to Hindu, Sikh, Buddhist, Jain, Parsi and Christian communities have faced persecution on grounds of religion.' But, Sir, in the Bill, nowhere, it has been mentioned that the citizenship will be granted to those who have fallen victim of religious persecution.

MR. CHAIRMAN: Right.

SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY: There is no reasonable nexus between the Statement of Objects and Reasons and the Bill. Therefore, this Bill is defective and the debate should be adjourned till such period the Bill is rectified.

MR. CHAIRMAN: Right. I have heard your argument and I have gone through the Rules of Procedures also. The Lok Sabha has discussed it, approved it and then I have received the Bill. I have gone through the Bill and then I have given permission after getting myself fully satisfied that this Bill is in order. There is no ground made out for seeking any adjournment of the debate on the Bill under Rule 230 on the paras of SOR which do not form part of the Bill, which is under consideration of the House. ...*(Interruptions)*...

SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY: Sir, I walk out.

(At this stage the hon. Member left the Chamber)

SHRI T.K. RANGARAJAN (Tamil Nadu): Sir, ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Therefore, the motion appears to attract sub-rule 2 of Rule 230 being an abuse of Rules of Council. ...*(Interruptions)*... I have given a ruling. Now the discussion is on. Yes, Mr. Minister. ...*(Interruptions)*... You will get the time.

श्री अमित शाह: सभापति महोदय, आज मैं इस गरिमामयी सदन के सामने एक ऐतिहासिक बिल लेकर उपस्थित हुआ हूं। मान्यवर, इस बिल के जो प्रावधान हैं, वे लाखों-करोड़ों लोग, जो कई सालों से यातना का जीवन जी रहे हैं, नर्क की यातना का जीवन जी रहे हैं, उन सबको एक नई आशा की किरण दिखाने वाला यह बिल है।

मान्यवर, मैं थोड़ा पृष्ठभूमि में जाना चाहूंगा। विभाजन के बाद एक हम सबकी कल्पना थी कि जो अल्पसंख्यक नागरिक यहां पर रहते हैं और पड़ोसी देशों में भी जो अल्पसंख्यक रहते हैं, वे सब अपने-अपने नागरिक अधिकारों के साथ सम्मानपूर्ण जीवन जी पाएंगे।

महोदय, अपने धर्म का, अपनी परम्पराओं का सम्मान के साथ पालन कर पाएंगे। अपने परिवार के स्वाभिमान का और विशेषकर परिवार की स्त्रियों के सम्मान की वे रक्षा भी कर पाएंगे और उन्हें रक्षण करने का अधिकार भी है। परन्तु कई दशकों के बाद, जब इस ओर मुड़कर देखते हैं, तो कटु सच्चाई सामने यह आई है कि चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे पाकिस्तान हो और चाहे समय-समय पर बंगलादेश हो, जो अल्पसंख्यक वहां रहते थे, उनके अधिकारों की सुरक्षा नही हुई। उन्हें समानता का अधिकार नही मिला। जब पूर्वी पाकिस्तान से बंगलादेश बना, बंगबंधु मुज़ीबुर्रहमान साहब ने इसे सुधारने का प्रयास किया, मगर दुर्भाग्य से उनकी हत्या हो गई और एक लम्बा काल खंड, अभी का शासन आने से पहले वहां ऐसा आया कि वहां उन्हें घोर प्रताड़ना का सामना करना पड़ा।

मान्यवर, मैं इस बारे में आंकड़े बाद में, जवाब देते समय लेकर आऊंगा। मगर मैं कहना चाहता हूं कि दोनों पाकिस्तानों में- पूर्वी और पश्चिमी, मतलब कि आज के बंगलादेश और पाकिस्तान में, अल्पसंख्यकों की आबादी में लगभग 20-20 प्रतिशत की कटौती हुई है और कमी हुई है। कहां गए ये लोग? या तो उन्हें किसी न किसी रूप में मार दिया गया, या उनका धर्म परिवर्तन हो गया या, तो वे शरणार्थी बनकर, अपने धर्म और सम्मान को बचाने के लिए वे भारत में आए।

मान्यवर, भारत में आए, उन्हें यहां संरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन सालों तक नही मिला। उन्हें न नागरिकता मिली, न घर खरीदने का अधिकार मिला, न नौकरी, न स्वास्थ्य और शिक्षा की सुविधाएं मिली और वे लोग आज अपने ही देश के अंदर दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। यह बिल ऐसे सभी प्रताड़ित लोगों को जो धर्म के आधार पर प्रताड़ना सह करके भारत में आए हैं, उन सभी लोगों को नागरिकता का अधिकार देने हेतु यह बिल लाया गया है। इस बिल के अंदर कुछ विशेष रियायतें भी इन निश्चित वर्ग के लोगों के लिए हमने सोची हैं। उन पर मैं बाद में आऊंगा।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इस सदन का और सदन के माध्यम से पूरे देश की जनता का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि वर्ष 2019 में, जब आम चुनाव हुए, तो आम चुनाव के

[श्री अमित शाह]

बाद, अभी जो पार्टी सत्ता में है, वह भारतीय जनता पार्टी और हमारे साथी दल, सबने मिलकर भारतीय जनता पार्टी का एक घोषणापत्र घोषित किया था और उसे हमने देश की जनता के सामने रखा था।

सभापति महोदय, मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम में, पार्लियामेंटरी डेमोक्रेटिक सिस्टम में इस घोषणापत्र में, जो सरकार बनने वाली है, उसकी नीतियों की उद्घोषणा होती है। इसके आधार पर प्रचार होता है। देश की जनता इसके आधार पर अपना मत व्यक्त करती है और किसी एक दल को चुनकर, जिसका मेनिफेस्टो अच्छा लगे, उसे शासन करने का अधिकार देती है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणापत्र के अंदर असंदिग्ध तरीके से इस बात की घोषणा की थी। मैं यह बात इसलिए कहना चाहता हूं कि जो लोग कह रहे हैं कि आप वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं या यह कर रहे हैं या वह कर रहे हैं, मैं उन सभी साथियों से कहना चाहता हूं कि हमने चुनाव से पहले ही, एक इरादा, देश की जनता के सामने रखा था, जिसे देश की जनता ने जनसमर्थन दिया है और देश की जनता ने शासन करने का अधिकार दिया है।

मान्यवर, लोकतंत्र के अंदर जनादेश से बड़ी कोई बात नही हो सकती। हमने इस घोषणापत्र के अंदर लिखा था कि हम पड़ोसी देशों से प्रताड़ित धार्मिक अल्पसंख्यकों के संरक्षण के लिए सिटिज़नशिप अमेंडमेंट बिल को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और उसे लागू करेंगे। इसके साथ ही हमने यह भी कहा था कि हम पूर्वोत्तर राज्यों में उन वर्गों के लिए सभी मुद्दों को स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे, जिन्होंने कानून के बारे में आशंका व्यक्त की है और पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों की भाषायी, सांस्कृतिक और सामाजिक रक्षा के लिए भी हम अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हैं। जो नॉर्थ-ईस्ट का कंसर्न है, हम उसको एड्रेस करेंगे, वह भी हमने कहा था।

मान्यवर, मुझे आनंद है कि नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में यह सरकार चल रही है और आज मोदी जी के नेतृत्व में मैं जो बिल लेकर इस सदन के सामने उपस्थित हुआ हूं, इसमें आज हम हमारी इन दोनों घोषणाओं को कानूनी जामा पहनाने जा रहे हैं। हम हमारे तीनों पड़ोसी देशों के धार्मिक अल्पसंख्यकों को संरक्षण देकर उनको नागरिक बनाने की प्रक्रिया का अमेंडमेंट लेकर आए हैं और जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं, उनके अधिकारों को, उनकी भाषा को, उनकी संस्कृति को और उनकी सामाजिक पहचान को प्रिज़र्व करने के लिए, उनको संरक्षित करने के लिए भी हम चिंता करते हुए इसके अंदर प्रावधान लेकर आए हैं। मैं बिल के डिटेल्ड प्रावधान पर बाद में जाऊंगा, लेकिन सरल भाषा में कहूंगा - क्योंकि देश की जनता भी इस सदन में हो रही बहस को बड़ी curiosity से देख रही है, सबके मन में स्पष्ट हो जाए, इसलिए मैं सरल भाषा में यह बताना चाहता हूं कि यह बिल

क्या है। पाकिस्तान, बंगलादेश और अफ़गानिस्तान, इन तीन देशों की जो सीमाएं भारत को छूती हैं, उन तीनों देशों में हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई और पारसी, वहाँ की लघुमती के लोग, जो भारत में आए हैं, वे किसी भी समय आए हों, उनको नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान इस बिल में है। इसका मतलब आज़ादी के बाद बंगलादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से जो भी जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई, पारसी और हिंदू धर्म का अनुसरण करने वाले उन तीन देशों की माइनॉरिटी के लोग, जो यहाँ आए हैं, हम उनको नागरिकता देंगे।

दूसरा, हमने पूरे नॉर्थ-ईस्ट के अंदर अलग-अलग प्रकार से नॉर्थ-ईस्ट के लोगों के हितों की चिंता भी की है, मैं इसको बाद में बताऊंगा।

मान्यवर, लोक सभा में चर्चा चली। मैंने कुछ अखबारों के आर्टिकल्स भी पढ़े हैं, मैं यह कहना चाहूंगा कि एक बहुत बड़ी भ्रांति फैलाई जा रही है कि यह बिल माइनॉरिटी के खिलाफ है, यह बिल विशेषकर मुस्लिम समुदाय के खिलाफ है। मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि जो इस देश के मुसलमान हैं, उनके लिए इस देश के अंदर किसी चिंता की चर्चा का सवाल ही नही है, क्योंकि वे नागरिक हैं, नागरिक रहेंगे, उन्हें कोई प्रताड़ित नही कर सकता। मगर आप चिंता किसकी कर रहे हैं? क्या पाकिस्तान की चिंता है? क्या आप चाहते हैं कि पाकिस्तान से भी जो अवैध प्रवासी मुसलमान यहाँ आएं, हम उनको भी नागरिक बना दें, बंगलादेश से जो अवैध प्रवासी मुसलमान यहाँ आएं, उनको भी नागरिक बना दें, अफगानिस्तान से भी जो अवैध प्रवासी मुसलमान यहाँ आएं, उनको भी नागरिक बना दें? आप क्या कहना चाहते हैं? पूरी दुनिया से जो भी अवैध प्रवासी मुसलमान यहाँ आएगा, क्या हम उसको यहाँ की नागरिकता दे देंगे? किस तरह से देंगे? देश कैसे चलेगा? ऐसे नही चल सकता है। यह उन निश्चित वर्गों के लिए है, जिनके धर्म के अनुसरण के लिए इन तीन राज्यों में अनुकूलता नही है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। इसमें उन तीन देशों के अल्पसंख्यकों को ही नागरिकता देने का प्रावधान है। आज जो लोग इस बिल का विरोध कर रहे हैं, मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं, कृपया आप मुझे यह बताइए - मैं जब जवाब देने के लिए खड़ा होऊंगा तब पूरी चीज़ें डिटेल में बताऊंगा, मैं आपकी जो एक-एक शंका है, आपके जो सवाल हैं, आप जो एक-एक स्पष्टीकरण मांगेंगे, वे सब स्पष्टीकरण दूंगा, मगर मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि जिन लाखों, करोड़ों लोगों पर प्रताड़ना हुई है, वे लोग जाएं कहाँ? वे कहाँ जाएँ? क्या उन्हें जीने का अधिकार है या नही है? हम उन्हें अधिकार देना चाहते हैं या नही देना चाहते हैं? वे किसी देश के नागरिक बनने चाहिए या नही बनने चाहिए? इसमें धार्मिक प्रताड़ना के आधार पर जो लोग आए हैं, उनको नागरिकता देने का सवाल है। यहाँ के minority और विशेषकर किसी भी मुसलमान को चिंता करने की जरूरत नही है, यह मैं स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूँ। किसी को भी चिंता करने की जरूरत नही है। कोई आपको बरगलाए, कोई डराए, आप डरिए मत, यह नरेन्द्र मोदी सरकार है और संविधान की spirit के साथ चल रही है, minority को पूरी protection मिलेगी। इसमें किसी को डरने की जरूरत नही है। ...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: Please. ...*(Interruptions)*... आप सुनिए, जब आपको बाद में मौका मिलेगा, तब आप बोलिएगा।

श्री अमित शाह: मान्यवर, विपक्ष के सभी माननीय सदस्य, जो बैठे-बैठे बोल रहे हैं, मेरी उनको चुनौती है कि जब आपको बोलने का मौका मिले, तो मुद्दे के साथ point उपस्थित करिएगा, मैं हरेक चीज का जवाब देने के लिए बाध्य भी हूँ, तैयार भी हूँ और दूँगा भी। बशर्ते आप बैठिएगा, चले मत जाइएगा। ...**(व्यवधान)**... आप बैठिएगा। मैं हरेक चीज का जवाब दूँगा।

मान्यवर, मैं इस बिल के कुछ प्रावधानों को बता कर अपना प्रारंभिक भाषण समाप्त करूँगा। इस बिल के अन्दर नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 2 (1) (ख) में जो प्रावधान हैं कि पासपोर्ट, वीजा और ट्रैवल दस्तावेज के बगैर जो प्रवासी भारत में आते हैं, या जिनका पासपोर्ट और वीजा expire कर जाता है, काल बाह्य हो जाता है, उनको ऐसी सूरत में अवैध प्रवासी माना जाता है, अब हम इसके अन्दर सुधार लेकर आए हैं। अब मैंने ये जो 6 वर्ग कहे - हिन्दू, सिख, जैन, पारसी, बौद्ध और ईसाई, जो इन तीन देशों से आते हैं, उनको अवैध प्रवासी नही माना जाएगा। इससे उनको मुक्ति दे दी गई है।

मान्यवर, इसमें नागरिकता अधिनियम की नई धारा 6 (ख) भी लाने का प्रस्ताव है। इसमें प्रस्ताव है कि यदि धार्मिक उत्पीड़न के शिकार उपरोक्त प्रवासी निर्धारित की गईं शर्तों और प्रतिबंधों के तौर-तरीकों को अपना कर रजिस्ट्रेशन या देशीकरण कराते हैं, तो उनके माध्यम से वे भारत की नागरिकता ले पाएँगे। यह प्रावधान भी किया जा रहा है कि ऐसे प्रवासी अगर नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 5 या तीसरे शैड्यूल की शर्तें पूरी करने के उपरांत नागरिकता प्राप्त कर लेते हैं, तो जिस तिथि से वे भारत में आए हैं, उसी तिथि से उनको नागरिकता दे दी जाएगी। इसका मतलब होता है कि मेरे पश्चिमी बंगाल के अन्दर ढेर सारे शरणार्थी आए हुए हैं, अगर वे 1955 में आए, 1960 में आए, 1970 में आए, 1980 में आए, 1990 में आए या 2014 की 31 दिसंबर के पूर्व आए, उन सभी को उसी तिथि से नागरिकता दी जाएगी, जिस तिथि से वे आए है। इससे उनको कोई legal consequence face नही करना पड़ेगा। मान्यवर, अगर ऐसे अल्पसंख्यक प्रवासी के खिलाफ अवैध प्रवास या नागरिकता के बारे में, घुसपैठ या नागरिकता के बारे में कोई भी केस चल रहा है, तो वह केस इस बिल के विशेष प्रावधान से वही पर समाप्त हो जाएगा। वह legal proceeding उसको face नही करना पड़ेगा । इस धारा में यह भी प्रावधान किया गया है कि अगर आवेदक किसी भी प्रकार का अधिकार या privilege ले रहा है, तो इस प्रावधान के तहत वह अधिकार व privilege से वंचित नही कर दिया जाएगा। मान्यवर, कई जगह कुछ जो शरणार्थी आए हैं, उन्होंने छोटी-मोटी दुकान खरीद ली है, वे अपना काम कर रहे हैं। कानून की दृष्टि में हो सकता है कि वह अवैध हो, गैर-कानूनी हो। मगर यह बिल उनको

protect करता है कि उन्होंने भारत में अपने निवास के समय में जो कुछ भी किया है, उसको यह बिल regularize कर देगा। उनकी उस status को कही पर भी वंचित नही करेगा। जैसे किसी की शादी हुई, बच्चे हुए, इन सब चीजों को यह बिल regularize करेगा। उत्तर-पूर्व के सभी राज्यों में जो प्रोटेक्शन दिया गया है, उसी को आगे बढ़ाते हुए, Sixth Schedule में असम, मेघालय, मिज़ोरम, त्रिपुरा जनजातीय इलाकों पर यह बिल लागू नही होगा। इसी तरह Bengal Eastern Frontier Regulation Act, 1973 के तहत Innter Line Permit के इलाके, पूरा मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश, अधिकांश नागालैंड और मणिपुर, जो अब पूरा राज्य नोटिफाई हो चुका है, इन सारे एरियाज़ में भी ये प्रावधान लागू नही होंगे।

मान्यवर, जहां तक असम का सवाल है, मैं आज इस सदन के सामने एक कटु वास्तविकता रखना चाहता हूं। 1985 में असम के अन्दर तत्कालीन प्रधान मंत्री, श्री राजीव गांधी जी ने Assam Accord किया था। Assam Accord के अंदर असम के लोगों को उनकी सांस्कृतिक, सामाजिक और भाषाई पहचान दिए जाने एवं चुने हुए फोरम्स में उनके representation के अधिकार को protection करने के लिए क्लॉज-6 बनाया गया था। क्लॉज-6 के अंदर एक प्रावधान था कि इसके माध्यम से भारत सरकार एक कमिटी गठित करेगी, जो इन सारी चीज़ों को देखेगी, इनकी चिंता करेगी, ताकि असम के जो मूल निवासी हैं, वे अपनी पहचान बना पाएं। श्री राजीव गांधी जी ने बड़ी उदात्त भावना के साथ इस Assam Accord को साइन किया, असम के लोग बहुत खुश हो गए, वहां पटाखे जलाए गए, खुशियां मनाई गईं और फिर वह आन्दोलन वही पर समाप्त हो गया। लेकिन 1985 से लेकर जब तक श्री नरेन्द्र मोदी प्रधान मंत्री बने, तब तक क्लॉज़-6 की वह कमिटी बनी ही नही। ...**(व्यवधान)**... वह कमिटी बनी ही नही। मान्यवर, 35 साल तक किसी को चिंता नही हुई कि असम के लोगों की भाषा की रक्षा, साहित्य की रक्षा, संस्कृति की रक्षा, पूरे सामाजिक परिवेश की रक्षा, उनके political representation का protection, इन सारी चीज़ों के लिए जो करना था, वह हुआ ही नही। ...**(व्यवधान)**... कभी नही हुआ। ...**(व्यवधान)**... आप बोल रहे हैं, तो यह भी बताइए कि कब हुआ? ...**(व्यवधान)**... कभी नही हुआ। वह तब हुआ, जब इस देश ने नरेन्द्र मोदी जी को प्रधान मंत्री बनाया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई।

SHRIMATI RANEE NARAH: *

MR. CHAIRMAN: No, please. ...*(Interruptions)*... This will not go on record. ...*(Interruptions)*... This will not go on record. ...*(Interruptions)*... Madam, I have to name you. This will not go on record. ...*(Interruptions)*...

---

*Not recorded

मैडम, रानी जी, आप बैठ जाइए।...**(व्यवधान)**... This is not the way. I do not know why you are doing this. जब आपका मौका आएगा, तब आप आराम से बोलिएगा।

श्री अमित शाह: मान्यवर, मैं असम के सभी मूल निवासियों को इस सदन के माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूं कि एनडीए की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्लॉज़-6 की कमिटी के माध्यम से आपके सभी हितों की चिंता करेगी, इसमें आप किंचित मात्र भी शंका मत कीजिए। यह जो सरकार है, यह सरकार "सबका साथ, सबका विकास" के आधार पर चलने वाली सरकार है और हम मानते हैं कि असम आन्दोलन के अंदर जो शहीद हुए हैं, उन सारे लोगों की शहादत व्यर्थ नही जानी चाहिए। मान्यवर, अब असम की समस्या का सच्चा समाधान लाने का समय आ गया है, इसीलिए हमने क्लॉज-6 की कमिटी बनाई है, जिसमें AASU भी शामिल है, जिन्होंने आन्दोलन किया था और इसमें हमारे असम गण परिषद के साथी भी सम्मिलित हैं। मैं आपके माध्यम से इन सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि जितनी जल्दी हो सके, कृपया क्लॉज-6 की कमिटी की रिपोर्ट आप भारत सरकार को भेज दीजिए, जिससे भारत सरकार आपके हितों की रक्षा कर पाए।

SHRI RIPUN BORA: *

MR. CHAIRMAN: This is misbehaving. Please sit down. This will not go on record. Nothing should be shown. ...*(Interruptions)*... Mr. Ripun Bora, don't be irresponsible. Please sit down. ...*(Interruptions)*...

श्री अमित शाह: मान्यवर, असम के अन्दर बीटीसी कार्बी आंगलोंग, दीमा हसाओ ...**(व्यवधान)**... CAB से बाहर रखा जाएगा। ...**(व्यवधान)**... मान्यवर, असम के छः समुदाय मोरन, मुटॉक, ताई अहोम, कोच राजबोंगशी, सुतीया को ...**(व्यवधान)**... हम उनके जनजातीय अधिकार देने की दिशा में आगे बढ़ेंगे।

MR. CHAIRMAN: Ghulam Nabiji, please take care of your Members. This is not the way. ...*(Interruptions)*... Then, I will not give any opportunity at all. ...*(Interruptions)*... No media should show this. No report should be made out of these irresponsible utterances without permission. ...*(Interruptions)*...

श्री अमित शाह: बोडो समुदाय के सांस्कृतिक विकास के लिए हमने बोडो म्युज़ियम भाषा तथा सांस्कृतिक अध्ययन केन्द्र स्थापित किया, कोकराझार में वर्तमान के दूरदर्शन और आकाशवाणी केन्द्र का आधुनिकीकरण किया तथा एक सुपरफास्ट ट्रेन का नाम अरोनई एक्सप्रेस किया है। मान्यवर, मैं यहां एक बात और बताना चाहता हूं। मान्यवर, मैं यह बताना चाहता हूँ कि हम

*Not recorded

जब यह बिल लेकर आये हैं, तब स्वाभाविक है कि ढेर सारी शंकाएँ यहाँ के और प्रतिपक्ष के सभी सदस्यों के मन में हैं। मेरा इन सभी से निवेदन है कि वैसे तो लोक सभा में मैंने इसका डिटेल्ड जवाब दिया भी है, मगर फिर भी कुछ ऐसे बिन्दु, पहलू-- या तो लोक सभा में मैंने जो स्पष्टीकरण किया है, वह हो सकता है कि पर्याप्त न हो, तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि आपके मन में जितनी भी शंकाएँ हैं, वे आप कृपया प्वाइंटवाइज़ यहाँ पर रखें। इस बिल पर पक्ष-विपक्ष की राजनीति से ऊपर उठ कर, आप इसकी चर्चा में contribute कीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपकी हरेक शंका का, आपके मन में उठे हरेक सवाल का और आपको जो हरेक स्पष्टता चाहिए, उसका समाधान करने के लिए मैं बाध्य भी हूँ, तैयार भी हूँ और बड़े धीरज के साथ सबको सुनकर मैं उनका समाधान करने के लिए आपके सामने उपस्थित हूँ। मगर कृपया जब लाखों-करोड़ों लोगों को नागरिकता देकर उनके जीवन के अन्दर-- कई दशकों से जो प्रताड़ना वे झेल रहे हैं, जो अपमानित जीवन वे जी रहे हैं, उनको एक नया जीवन देने के लिए प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी आये हैं, उनके लिए यह बिल पारित होते ही कल का सूर्य स्वर्णमय सूरज के रूप में उगने वाला है, उनके जीवन के अन्दर एक नयी आशा की शुरुआत होने वाली है, उनके जीवन के अन्दर एक नयी शुरुआत होने वाली है, इसमें हम सब शामिल हों। ...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: Mr. Ripun Bora, third time, if you rise from your seat, I will have to name you, and you will lose the opportunity to speak both now and in the evening also. ...*(Interruptions)*... You want to have voice or you want to make noise, choice is yours.

श्री अमित शाह: मान्यवर, मैं सभी सवालों का बड़े धैर्यपूर्वक जवाब दूँगा। इतना विश्वास दिला कर, मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ और सभी सदस्यों से कहता हूँ कि आपके मन में जो-जो सवाल हैं, वे कृपया सदन के पटल पर रखें, मैं उनका जवाब दूँगा।

The questions were proposed.

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, the Business Advisory Committee has recommended to allot six hours for this important legislation. Though, in the other House, it was discussed less than this time. But, Rajya Sabha, being the Council of States, and after taking into consideration the suggestion, this time has been fixed. It is a very important legislation. We are all Elders. If there is concern in your heart and in your mind about your State, you have got every right to express it through a system. So, please follow the timings that have been allocated. Every party is given time as per the allocation of their membership in the House. One minute, this

[Mr. Chairman]

way or that way, this is not a big issue. We will be liberal. But, liberal does not mean that you go on speaking. We will be flexible, to the extent, provided everybody cooperates in that effort. Even, the smaller parties also will be given an opportunity. But, they should also keep it in mind that the points which they want to make, they should first make those points, and later, if you get time, then you can add to it. Otherwise, what is happening is that they make other points, and by the time the Chair asks them to conclude, then they say, 'Sir, the original point is still to be made'. So, keep that in mind. Now, I appeal to one and all, the entire country is watching the House, like it was watched on earlier two important occasions. So, please keep that in mind and make best of your efforts to present your point of view. That is my appeal to all of you once again. Now, the next speaker is Shri Anand Sharma. There are six speakers from your party; you might have discussed it already.

SHRI ANAND SHARMA (Himachal Pradesh): Yes, Sir, I know that. We have apportioned it. माननीय उपसभापति महोदय, आपका बोर्ड काम नही कर रहा है।

श्री सभापति: सभापति कहिए।

श्री आनन्द शर्मा: महोदय, मैं गलती की माफी चाहता हूँ। वह बोर्ड काम नही कर रहा है। ...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति: वह काम करेगा। Don't worry.

श्री आनन्द शर्मा: माननीय सभापति महोदय, अपने पहले सम्बोधन के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। उस समय मैं उस बोर्ड की तरफ देख रहा था।

महोदय, गृह मंत्री जी ने अभी सदन में नागरिकता विधेयक में संशोधन लाने का एक प्रस्ताव लाया है। पिछले कुछ साल से इसकी चर्चा रही है। 2016 में भी यह बिल लाया गया था। उस बिल में और इस बिल में काफी अन्तर है। मैंने सरकार के पक्ष को, गृह मंत्री जी को सुना, दूसरे सदन में भी, यह कथन है कि सबसे बातचीत हो चुकी है। इसकी जाँच-परख हो चुकी है, मैं इससे सहमत नही हूँ और न मेरा दल, क्योंकि जो परिवर्तन हुए हैं, उसकी scrutiny होना जरूरी है। आपने कहा कि यह एक ऐतिहासिक बिल है, पर इतिहास इसको किस दृष्टि से देखेगा, वक्त बताएगा। अगर आप बदलाव लाए थे, बेहतर होता, प्रजातंत्र की यह रिवायत है, इसको दोबारा दिखवाते। जल्दीबाजी क्यों? इसको पार्लियामेंट

की कमेटी को भेजते और अगले सत्र में इसको लेकर आते। हमने माँग की थी, पर सरकार अपनी ज़िद पर कायम है, चाहती है कि इसको करें, जैसे कोई बहुत बड़ी विपत्ति भारत के सामने है, ऐसा जो कि पिछले 72 साल में नही देखा गया, इसलिए इसको तुरंत करना जरूरी है। हम इसका विरोध करते हैं। विरोध के कारण राजनीतिक नही हैं, बल्कि संवैधानिक हैं, नैतिक हैं। I am convinced that the Bill that you have brought is an assault on the very foundational values of the Indian Constitution. It is an assault on the Republic of India. It hurts the soul of India. It is against our Constitution; it is against our democracy. It fails the morality test. It is divisive and discriminatory. It is against the very Preamble of the Constitution of our Republic, which talks of liberty, equality and secularism. This is the reason I stand to oppose this Bill. नागरिकता; हिन्दुस्तान की आजादी के बाद देश का बंटवारा हुआ था, नागरिकता की व्याख्या और कानून बनाने की आवश्यकता पर भारत की संविधान सभा ने व्यापक चर्चा की थी, जिसकी अध्यक्षता प्रथम राष्ट्रपति डा. राजेन्द्र प्रसाद जी करते थे, डा. बी. आर. अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे और संविधान की समिति के अध्यक्ष पं. जवाहरलाल नेहरू थे, जिनका एक बहुत बड़ा योगदान और कुर्बानी हिन्दुस्तान की आजादी में है।

पार्टिशन की पीड़ा पूरे देश को थी। उस समय जो लोग नेता थे, जिन पर जिम्मेवारियाँ थी, जिन्होंने हिन्दुस्तान की आजादी की लड़ाई लड़ी थी, महात्मा गाँधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आन्दोलन में हिस्सा लिया था, उनको मालूम था कि बंटवारे के बाद नागरिकता का क्या महत्व है। उसको इन्होंने समझा। पर, सिटिज़नशिप का कॉसेप्ट क्या है? वह भौगोलिक है, territorial है, जन्म से है, स्वयं के जन्म से, माता-पिता के जन्म से और हमारे संविधान निर्माताओं ने तो आगे जाकर ग्रैंड पैरेंट्स के जन्म से भी किया, ओरिजिन से किया, दादा-दादी, नाना-नानी, वे शब्द इस संविधान के अंदर शामिल किए गए, धारा 5 से लेकर धारा 11 तक, यह संविधान के अंदर है। उन्होंने सब कुछ उल्लेख किया है, जो माननीय गृह मंत्री जी ने अभी कहा कि जो विस्थापित थे, बंटवारे के बाद जो पीड़ित थे, क्या संविधान निर्माताओं का यह सम्मान करना है? अगर हम आज 72 साल के बाद 2019 में यह कथन कहें कि उनको कोई समझ नही थी, उन्होंने इस पर गौर नही किया था, कुछ नही सोचा था, यह गलत बात है।

आपने जहाँ तक naturalisation process का जिक्र किया कि लोगों को नागरिकता दी जाए। भारत के संविधान में उसमें कोई भेदभाव नही किया गया, कोई परहेज नही है। हिन्दुस्तान के बंटवारे से उजड़े और उत्पीड़ित लाखों लोग, जो पश्चिम और पूर्वी पाकिस्तान से आए थे, क्या उनको सम्मान नही मिला? दो-दो प्रधान मंत्री भी बने, एक डा. मनमोहन सिंह जी यहाँ बैठे हैं और एक आई. के. गुजराल भी थे। हमें मालूम है, परिवार टूटे थे,

[श्री आनन्द शर्मा]

रक्तपात और नरसंहार हुआ था, गृह मंत्री जी, उनको न्याय दिलाना, बराबरी का अधिकार और समान अधिकार, यह प्रतिबद्धता भारत देश की थी। देश के संविधान निर्माताओं ने यह सुनिश्चित किया था। मैंने बताया कि संविधान में इसका स्पष्ट प्रावधान है, जो आप लेकर आए हैं, यह कोई नई बात नही है। मान्यवर, आर्टिकल-6 में यह लिखा है, मेरे बाद मेरे और साथी भी बोलेंगे, जो कानून के अच्छे अधिवक्ता हैं, वे इसका उल्लेख करेंगे कि सिटिजनशिप एक्ट में नही, संविधान में इसका प्रावधान किया गया है। जहाँ तक सिटिजनशिप एक्ट की बात है, यह 1955 में आया, उसके बाद इसमें नौ बार बदलाव भी हुआ, संशोधन हुआ, पर जो हमारा मूलभूत संविधान है, उसमें किसी संशोधन से कोई परिवर्तन या कोई टकराव कभी नही हुआ। माननीय गृह मंत्री, इतिहास बड़ा महत्व रखता है। मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं उसको सदन में रखूँ। क्योंकि आपने दूसरे सदन में हिन्दुस्तान के बंटवारे का ज़िक्र किया और बंटवारे का दोष उन लोगों पर लगाया, भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस पर और उन नेताओं पर लगाया, जिन्होंने अंग्रेज़ों की जेलों में बरसों गुजारे, कुर्बानियाँ दी और हिन्दुस्तान की आज़ादी के लिए संघर्ष किया। यह न्यायोचित नही है। मैं आपसे यह आग्रह करता हूँ कि अगर आप कहते हैं कि राजनीति नही होनी चाहिए, तो यह राजनीति भी बंद होनी चाहिए। वह महात्मा गाँधी के नेतृत्व में था, उसमें सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, मौलाना आज़ाद, सभी लोग शामिल थे। उन स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष को - आपको उनके मत से, विचारधारा से कोई भी परहेज हो, पर इतिहास में वह अंकित है, उससे इन्कार नही किया जा सकता और अगर आज की सरकार वैसा करती है, तो मैं कहूँगा कि उसको नकारना अन्याय होगा, इतिहास का अपमान होगा। इतिहास को बदला नही जा सकता। दुनिया में यह कोशिश बहुत हुई, कई सरकारें, कई शासकों ने नया इतिहास लिखने का प्रयास किया, पर वे लिख नही पाए, क्योंकि मनुष्य के जीवन में यही है, यही राजनीति और यही प्रजातंत्र की सच्चाई है कि कभी न कभी जब परिवर्तन होता है, तब सच्चाई और इतिहास अपने आप को पुन: प्रचंड रूप में प्रकट करती है।

मान्यवर, एक नज़रिया उन लोगों का भी था, जो गाँधी जी और कॉंग्रेस के मत के विरोधी थे। उसमें मुस्लिम लीग थी, उनके नेता जिन्ना थे, हिन्दू महासभा थी, उनके नेता विनायक सावरकर थे। मान्यवर, जो बंटवारे की two-nation theory है, उसे कॉंग्रेस नही लाई, बल्कि 1937 में अहमदाबाद में हिन्दू महासभा ने प्रस्ताव पारित किया था। उसकी अध्यक्षता सावरकर जी ने की थी। सन् 1938 में, उसके एक साल के बाद मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ, उसमें Partition of India Resolution adopt किया गया। उसे फजलूल हक ने मूव किया, जो बाद में इनके साथी भी बने, बंगाल के मुख्य मंत्री बने और पाकिस्तान के प्रधान मंत्री बने। इसके बाद, आप अंग्रेज़ों की भूमिका की चर्चा क्यों नही करते? लड़ाई तो अंग्रेज़ी हुकूमत के खिलाफ थी। What was the role of the British? They gave power of

veto to the Muslim League and Jinnah after 1938. 1938 और 1943 के घटनाक्रम को हिन्दुस्तान और इतिहास भूल नही सकता। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया था, कॉंग्रेस ने विरोध किया था, 1942 में गाँधी ने भारत छोड़ो का नारा दिया था, कॉंग्रेस का नेतृत्व कैद कर लिया गया था, कोई नेता बाहर नही था, तीन साल तक सारी कॉंग्रेस, कॉंग्रेस को बैन कर दिया गया था, illegal organization कह दिया था, जेलों के अंदर हजारों लोग बंद थे, सूबों में कॉंग्रेस की सरकारें डिस्मिस कर दी गई थी, इस्तीफे हो गए थे, तब यही दो संगठन आगे आए और Viceroy Linlithgow को एक के बाद एक चिट्ठी दी। चाहे वह हिन्दू महासभा थी, चाहे वह मुस्लिम लीग थी, जिन्होंने कहा कि 'We will help in the formation of Governments in the provinces loyal to Her Majesty's Government.' ...*(Interruptions)*... क्या वह सरकार बंगाल में नही बनी?

MR. CHAIRMAN: This will not go on record. ...*(Interruptions)*... Why are you wasting your. ...*(Interruptions)*...

श्री आनन्द शर्मा: क्या वह सरकार पंजाब में नही बनी? ...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: He is speaking. ...*(Interruptions)*... He is speaking. Your leader is speaking. ...*(Interruptions)*... Respect him.

श्री आनन्द शर्मा: माननीय, यह जिक्र क्यों नही आया कि हिन्दुस्तान का बँटवारा, Independence of India Act, जिसे House of Commons, British Parliament ने पास किया था, उसके कारण हुआ? कॉंग्रेस को भी दोष देना गलत है। अगर किसी को नया इतिहास लिखने का प्रोजेक्ट दिया गया है, तो कृपा करके ऐसा अन्याय मत कीजिए, आपसे यह मेरा आग्रह रहेगा। पर, एक चीज़ जरूर है। सन् 1943 में औपचारिक रूप से घोषणा कर दी गई -- सावरकर जी ने -- मैं जो ये सारी बातें कह रहा हूँ, authenticate करके सभा पटल पर रखूँगा, ताकि भविष्य में इस सच्चाई की याद रहे। उन्होंने कहा, "I have no problems with Mr. jinnah's proposal of a two-nation theory." It is on record.

माननीय, अगर मैं आज के परिप्रेक्ष्य में कहूँ, तो Citizenship Act में जो नौ बार संशोधन आए, उनमें से कई महत्वपूर्ण थे, मैं किसी को नगण्य नही मानता। उसके बाद लोगों को नागरिकता दी गई। जब गोवा आज़ाद हुआ, दमण-दीव आज़ाद हुए, पॉंडिचेरी आज़ाद हुआ, तब वहाँ के जो नागरिक थे, उनको नागरिकता दी गई। उसके बाद, जब भारतीय मूल के लोगों को अफ्रीका, केन्या, युगांडा और सीलोन यानी श्रीलंका में तकलीफ हुई, वहाँ से उनको निकाल दिया गया, तो भारत सरकार ने आवाज़ उठाई और अंग्रेज़ी हुकूमत से बात की। उसके बाद, जो लोग यूके में जाकर रहना चाहते थे, उनको वहाँ की नागरिकता मिली और जो हिन्दुस्तान वापस आना चाहते थे, वे यहाँ आए। माननीय गृह मंत्री जी, आपके

[श्री आनन्द शर्मा]

गुजरात में भी ऐसे बहुत-से लोग हैं, जो केन्या से आए हैं, ऐसे बहुत-से लोग हैं जो युगांडा से आए हैं। उनको सम्मान भी मिला, अधिकार भी मिला, नागरिकता भी मिली, ज़मीन भी मिली और कारोबार भी मिला। इसलिए यह कहना कि 72 साल में वे करोड़ों-करोड़ लोग उजड़े, उत्पीड़ित रहे और किसी सरकार ने कुछ सोचा नही -- आप इसको लाने से पहले सोचते, सब सरकारें, हमारी तो गलत रही -- मान्यवर, श्री अटल बिहारी वाजपेयी भी 6 साल देश के प्रधान मंत्री थे, कृपा करिए, वे तीन बार बने थे। आडवाणी जी भी उप-प्रधान मंत्री रहे। इसी सदन में इस पर चर्चा हुई है, आप उसका उल्लेख भी करेंगे।

मैं यह बात कहना चाहता हूँ कि जब भी संशोधन हुए, जब भी नागरिकता दी गई, भारत की सरकार और संसद ने धर्म को कभी भी नागरिकता का आधार नही बनाया। इसलिए हमने कहा, यह हमारे मूलभूत सिद्धांतों से टकराता है। Article 14 guarantees equality before law and equal protection of law. Article 15 prohibits any discrimination on grounds of religion, colour, caste or creed. Given the time constraints, I am not reading it and just referring to these Articles. Therefore, this Bill of yours fails the constitutionality test.भारत ने refugees को, शरणार्थियों को सदैव शरण दी। दुनिया के उत्पीड़ित लोग, जो हिंसा के शिकार थे, जिनका तिरस्कार हुआ, अपमान हुआ, भारत ने सदियों से उनको शरण दी, चाहे वे यहूदी थे, पारसी थे या ईसाई थे।

मान्यवर, मैं एक तारीख, 11 सितम्बर का जिक्र करना आवश्यक समझता हूँ। 9/11, दुनिया आज इस तारीख को अमेरिका पर हुए हमले को याद करके जानती है, पर पिछले 126 बरस में चार घटनाएँ 11 सितम्बर, यानी 9/11 को हुई हैं- एक तो अमेरिका का हमला हुआ, मैंने बताया; एक घटना वर्ष 1973 में हुई थी, वह भी दुखद थी जब चिली में सल्वाडोर अलेंदे को मार दिया गया था और दसियों हज़ार लोग military coup में कत्ल कर दिए गए थे। तीसरा, जो अच्छा था, वह महात्मा गांधी जी का सत्याग्रह था, वह भी 9 सितम्बर, 1906 को Johannesburg, South Africa से शुरू हुआ था, सत्याग्रह से हिन्दुस्तान बाद में आज़ाद हुआ, किंतु मैं जिस 9 सितम्बर का ज़िक्र कर रहा हूं, वह है 9-11-1893, स्वामी विवेकानन्द, आप स्वामी विवेकानन्द जी को मानते हैं, हम सब मानते हैं, पूरे देश को उन पर गर्व है, जो उन्होंने कहा। हम हृदय से उनका सम्मान करते हैं, अधिकांश भारत के लोग, चाहे वे हिन्दू हों या किसी भी धर्म के हों, स्वामी विवेकानन्द जी को दुनिया मानती है। आप शिकागो जाएं तो देखेंगे कि वहां के सिटी हॉल की हर सीढ़ी पर एक-एक पंक्ति उनके उस भाषण की लिखी है, जो उन्होंने World Religion's Conference में दिया था। उसमें लिखा है कि "I am proud to belong to a nation which has sheltered the

persecuted and the refugees of all religions and all nations of the earth. I am proud to tell you that we have gathered in our bosom the purest remnant of the Israelites, who came to Southern India and took refuge with us in the very year in which their holy temple was shattered to pieces by Roman tyranny. I am proud to belong to the religion which has sheltered and is still fostering the remnant of the grand Zoroastrian nation." I will not read beyond but he has talked of religion, no discrimination ever by India.

जिस देश ने यह कहा। आपकी क्या प्राथमिकता होनी चाहिए। हमने संयुक्त राष्ट्र संघ में Human Rights Convention को ratify किया, हम Human Rights Council में भी हिस्सा लेते हैं। यह मानव अधिकार की बात है, मानवता की बात है। मान्यवर, आपने persecuted minorities की बात की है। आपके बिल में उसका उल्लेख नही है, जिसके लिए सुखेन्दु शेखर राय जी कह चुके हैं, मैं उसको दोहराऊंगा नही। अगर आप वाकई उनके लिए लाए हैं तो बिल में ज़िक्र क्यों नही है, उसकी व्याख्या क्यों नही है? अगर आपको इतनी ही चिंता है तो refugees पर कानून क्यों नही है। आप देश के अंदर उसको भी बनाइए। मैं सोचता हूं कि ये प्राथमिकताएं चर्चा के बाद होनी चाहिए। यह बात दलगत राजनीति से ऊपर उठकर होनी चाहिए। गृह मंत्री जी, अगर आपने दिल से यह बात कही है तो आज आप इसको रोक लें, चर्चा करें, ताकि आम सहमति से बात बने।

मैं समझता हूं कि सदन के और पूरे देश की संवेदना उत्पीड़ित मानवता के साथ है, किंतु मुझे नही लगता कि इसका कारण केवल यह है, महोदय, कारण राजनीतिक है। आप भी जानते हैं, स्वीकारेंगे नही, हम भी जानते हैं, क्योंकि संविधान में तो उन लोगों को नागरिकता देने का प्रावधान है। माननीय गृह मंत्री जी, आपने वर्ष 2019 के चुनाव का ज़िक्र किया, बीजेपी के manifesto का ज़िक्र किया। सभापति महोदय, हर राजनैतिक दल को अपना manifesto लिखने का अधिकार है। आपका अनुभव है, पर किसी भी दल का घोषणापत्र भारत के संविधान से नही टकरा सकता और न ही उसके ऊपर जा सकता है, चाहे वह कोई भी हो। जनादेश की बात है तो हम सम्मान करते हैं, आप जीत कर आए हैं, हम हार कर आए हैं, तभी हम यहां बैठे हैं और आप वहां बैठे हैं। हमने आपको कई बार बधाई दी है, किंतु संविधान की शपथ आपने भी ली है, माननीय प्रधान मंत्री जी ने भी ली है और हम सबने ली है, उसका क्या होगा? उसके बारे में चर्चा ज़रूरी है। इसलिए मैं आपसे यह कहूंगा कि जहां तक, हमारे बहुत उदाहरण हैं, मैं उसमें नही जाऊंगा। आपने कहा कि हमने सब समाधान कर दिए, कुछ नही किया। प्रावधान के बारे में जैसा मैंने कहा कि आर्टिकल 6 में भी है, Citizenship Act में भी है, registration से citizenship का भी है, naturalization से भी है। आपने Schedule Three में समय घटा कर 11 साल से 7 साल

[श्री आनन्द शर्मा]

किया है, यह आपका बिल कहता है, मैं नही कहता। एकदम से मिल जाएगा, ऐसा कुछ नही हुआ। आप अपने उत्तर में बताएं कि कितने लाखों-करोड़ों लोगों ने आवेदन पत्र दिए हैं।

मैं दो बातें कहना ज़रूरी समझता हूं। आपने दूसरे सदन में कहा कि हम पूरे देश में एनआरसी लाएंगे, यह असली बात है। असम का क्या अनुभव है, मेरे असम के साथी उस पर बोलेंगे। असम जल रहा है, आपको बोलना पड़ा। वे उत्पीड़ित लोग नही हैं। अगर आप अच्छा कर रहे हैं, तो उनके मन में insecurity क्यों है, असुरक्षा की भावना क्यों है? क्यों बच्चे निकलकर बाहर आ गए हैं? इंदिरा जी के समय में जो AASU आंदोलन हुआ था...**(व्यवधान)**...

सुश्री सरोज पाण्डेय (छत्तीसगढ़): क्योंकि उसके पीछे...**(व्यवधान)**...

श्री आनन्द शर्मा: आप बीच में मत बोलिए।

श्री सभापति: प्लीज़, नही।

श्री आनन्द शर्मा: यह उचित नही है। आप इसको निकाल दीजिए और मेरा समय वापस कर दीजिए। अब मुझे एक बात कहनी है ... सर, मैं दो बातें जरूर कहूंगा और उसके बाद खत्म कर दूंगा। यह मेरे दल की बात है और मेरे दल वाले उसको adjust कर लेंगे। सर, दो बातें हैं, जो मैं समझता हूं कि कहनी जरुरी हैं। पहली तो यह है कि आप जो एन.आर.सी. ला रहे हैं... माननीय गृह मंत्री जी, मैंने इतवार को बी.बी.सी. चैनल पर detention centre पर एक documentary देखी थी। मै चाहता हू कि गृह मंत्री जी सर्वदलीय delegation लेकर जाएं, वहां के हालात देखें कि क्या वह इंसानों के रहने की जगह है? हिंदुस्तान को शर्म आती है कि 21वी सदी के अंदर हमने इस तरह से लोगों को रखा है। माताओं को बच्चों से दूर और बच्चों को माताओं से दूर रखा है। उनके लिए कोई सुविधा नही है। 600 लोग 5 कमरों में रहते हैं, पांच नलके हैं। इससे इंकार करें कि यह वास्तविकता नही है और जो पूरे देश के एन.आर.सी. की बात कह रहे हैं, उसमें असुरक्षा की भावना है। आप इसकी पुष्टि करें या इंकार करें कि देश के कई राज्यों के अंदर जगह ले ली गई है और detention centres बन रहे हैं, जब एन.आर.सी. बनेगा। क्या पूरे भारत में detention centres बनेंगे, जो पिछली शताब्दी की याद दिलाएंगे concentration camps की, जो यूरोप में होते थे। इस देश में यह एक अन्याय होगा। केवल महात्मा गांधी जी और सरदार पटेल का नाम लेना पर्याप्त नही है। मुझे नही पता कि जीवन में क्या होता है। मैंने सिर्फ सुना है कि हमारे धर्म में पुनर्जन्म को मानते हैं। अगर सरदार पटेल आपके प्रधान मंत्री जी को मिलें, तो वे बहुत नाराज़ होंगे, यह मैं कह सकता हूं। गांधी जी तो

दुखी होंगे ही कि मेरे 150 साल मना रहे हो और ऐसा करते हो। गांधी जी का चश्मा केवल विज्ञापन के लिए नही और उनका नाम नही, मेरा आपसे आग्रह है कि उनके चश्मे से हिंदुस्तान को देखिए, समाज को देखिए और मानवता को देखिए। आपका CAB उससे टकराता है। मैं सिर्फ गांधी जी के बारे में कहकर अपनी बात को खत्म करता हूं। सभापति महोदय, जैसा मैंने कहा कि मैं इसको कहना जरुरी समझता हूं। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि: "I do not want my house to be walled in on all sides and my windows to be stuffed. I want the cultures of all lands to be blown about my house as freely as possible. But I refuse to be blown off my feet by any."

अंत में, हिन्दी में, "मैं नही चाहता कि मेरे घर के चारों तरफ दीवारें बनी हों और खिड़कियां बंद हों। मैं चाहता हूं कि सभी देशों की संस्कृतियां मेरे देश में यथासंभव मुक्त रूप से आएं, परंतु मेरी संस्कृति भी अक्षुण्ण रहे।" इनका सम्मान करें। मैं आपका धन्यवाद देता हूं, गृह मंत्री जी, इस पर ग़ौर करें। मेरा आपसे यही आग्रह है कि जल्दबाजी न हो। ऐसी कोई वजह नही है, आप इस राजहठ को छोड़ें, इसको कमेटी को भेजें, सबसे बात करें, ताकि देश में जो भावनाएं हैं, वे केवल शब्दों से नही, आपके एक्शन से खत्म होंगी। हमारे बच्चे सड़कों पर हैं, लोग परेशान हैं... धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत!

MR. CHAIRMAN: Anand Sharmaji, you have taken 24 minutes because you said that the party will take care, so it will be taken care. I can understand smaller parties getting a little extra time, one minute, two minutes; I will accommodate. But, the bigger parties have to adjust within the time that is given because they have been given already a good amount of time. Once again, I repeat my appeal. When a speaker is speaking, making his own submission, others should patiently, respectably hear him, and If you want to cheer also, that should be quietly but not by other means. That has to be understood by one and all. Shri Jagat Prakash Nadda.

श्री जगत प्रकाश नड्डा (हिमाचल प्रदेश): सभापति जी, मैं The Citizenship (Amendment) Bill, 2019 के समर्थन में खड़ा हुआ हूं और इसके समर्थन में बोलने के लिए आज अपने विचारों को आप सबके सामने व्यक्त करना चाहता हूं। सबसे पहले मैं सम्माननीय प्रधान मंत्री जी को बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं जिन्होंने यह इच्छाशक्ति दिखायी। The Citizsenship (Amendment) Bill, 2019 को पहले लोक सभा में पेश किया गया और आज राज्य सभा में यह बिल चर्चा के लिए आया है। | I also want to congratulate the Home Minister who is the architect of this Citizenship Amendment Bill, 2019. जो इसके सूत्रधार हैं, उन्होंने बहुत ही बारीकियों से सारी बातों को समझते हुए उनका इस बिल में समावेश करते हुए देश के अंदर जो लम्बे समय से एक अन्याय के वातावरण में लाखों लोग जी रहे थे,

[श्री जगत प्रकाश नड्डा]

उन्हें सम्मान के साथ जीने का एक रास्ता देने का प्रयास किया है, इसके लिए मैं आदरणीय गृह मंत्री जी को भी बधाई देता हूं और उनका धन्यवाद करता हूं कि वे The Citizenship (Amendment) Bill, 2019 लेकर आए हैं।

अभी मैं आनन्द शर्मा जी का विद्वतापूर्ण वक्तव्य सुन रहा था। उनका भाषण विद्वतापूर्ण था। अकसर वकीलों के पास जब arguments की कमी होती है तो वे अपनी विद्वता का प्रदर्शन करते हुए कई arguments ले आते हैं, जिनका मूल से संबंध कम होता है। ...**(व्यवधान)**...

श्री सुखेन्दु शेखर राय: सर, यह वकीलों के खिलाफ है।

श्री सभापति: चलिए, बोलिए प्लीज़।

श्री जगत प्रकाश नड्डा: जिसका मूल से संबंध कम होता है। इसलिए कई बार ऐसा लगता है कि जो वक्तव्य आया है, उसमें force तो बहुत होता है, उसमें आवाज़ भी बहुत होती है, लेकिन तथ्य कम होता है। मैं record को straight करना चाहता हूं और record straight यह करना चाहता हूं कि हम कभी गांधी जी की बात करें, कभी सावरकर जी की बात करें, कभी हम किसी की बात करें, वह करना ठीक है, लेकिन आज जिस Citizenship (Amendment) Bill के बारे में हम बात कर रहे हैं, उसका आधार सिर्फ एक है कि अफगानिस्तान, बंगलादेश और पाकिस्तान में जिस minority का religious persecution हुआ है, प्रताड़ना हुई है और उन लोगों ने भारत में शरण ली है या शरण लेना चाहते हैं, उन्हें citizenship right देने का अधिकार देने का काम है, यह मूल बात है। This is the essence of this Bill. हम essence से इधर-उधर जाएं तो शायद हम रास्ते से भटक जाएंगे और जो हमारा उद्देश्य है, उसे हम पूरा नही कर सकेंगे।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यह समस्या आज की नही है, यह समस्या उसी समय शुरू हो गयी थी, जब हमें आज़ादी मिली और आज़ादी के साथ-साथ देश का विभाजन हुआ। जब देश का विभाजन हुआ तो यह स्पष्ट था कि वह विभाजन धर्म के आधार पर हुआ। We cannot mince words. This may be uncomfortable but we will have to venture on it. सच्चाई यही थी कि धर्म के आधार पर विभाजन हुआ और इस विभाजन की tragedy - हम में से कई लोग उस समय पैदा भी नही हुए थे, मैं तो पैदा भी नही हुआ था, लेकिन जो मैंने सुना और इतिहास गवाह है कि दुनिया में आज तक इतना बड़ा नरसंहार और इतनी अधिक संख्या में लाखों लोगों का एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर जाना और दूसरे से इधर आना - ऐसा न पहले कभी हुआ और न उसके बाद हुआ है, यह हमें ध्यान में रखना चाहिए। रातों-रात लोगों को अपने घर छोड़कर निकलना पड़ा था, रातों-रात अपनी properties छोड़कर निकलना पड़ा था, law and order situation में उन्हें कोई संरक्षण

1.00 P.M.

मिले, ऐसी कोई परिस्थिति नही रही थी, यह tragedy और यह नरसंहार उस समय लोगों ने देखा था। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इस नरसंहार के समय उस समय के प्रधान मंत्री यह चाहते थे कि दोनों देशों में minorities protect की जाएं, उनकी इच्छा थी कि दोनों countries में minorities protect हों। उस समय बंगलादेश नही था, East Pakistan और West Pakistan था, लेकिन वे protect हों, इस बात की इच्छा उनके मन में थी।

लेकिन इच्छा होना और सच्चाई में धरातल में उतरने में जमीन-आसमान का अंतर होता है। सच्चाई क्या हुई, हम लोग इस विभाजन की जब बात करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि उस समय इंडिया में माइनॉरिटीज़ कौन थे? मुस्लिम्स, सिख, जैन, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन और पारसी माइनॉरिटीज़ थे। उस समय पाकिस्तान में, ईस्ट और वैस्ट पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ कौन थे? Hindu, Sikh, Jain, Buddhist, Christian, Parsis are minorities. They were minorities. यह स्पष्ट था। मैं इसकी clarity इसलिए कर रहा हूं कि यह जो हम हिंदू-मुस्लिम, हिंदू-मुस्लिम की बात करते हैं, we should be clear that the Hindu was in majority in India, and the Hindu was in minority in Pakistan. We should be very clear about this. We should be very clear that the Muslims were in majority in Pakistan and in minority in Hindustan, in India. We should be very clear about this. इसलिए religious आधार की बात करते हैं ...**(व्यवधान)**... माइनॉरिटी को हमें समझना पड़ेगा।

MR. CHAIRMAN: What is this? जो सदस्य बैठकर बोलेंगे, उनको बाद में मौका नही मिलेगा। अगर उनका नाम है और पार्टी ने भी दिया है, तो भी मैं मौका नही दूंगा। ...**(व्यवधान)**... उपसभापति और पैनल वाइस चेयरमैन इसे नोट कीजिए।

श्री जगत प्रकाश नड्डा: जहां पर एक-समान माइनॉरिटी होती है, वह दूसरे देश में मेजॉरिटी होती है और दूसरे देश में जहां माइनॉरिटी होती है, वह इस देश में मेजॉरिटी होती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए जवाहरलाल नेहरू और लियाकत अली खां का पैक्ट हुआ था, जिसको नेहरू-लियाकत पैक्ट कहते हैं। इस पैक्ट के तहत इस बात की चिंता की गई थी कि दोनों ही जगहों पर माइनॉरिटीज़ की चिंता की जाए और माइनॉरिटीज़ को संभालकर रखा जाए और उनकी जनता की हिफाजत की जाए। This was Nehru-Liaquat Pact और इसके तहत यह कार्य हुआ था। लेकिन ऐसा हुआ नही और ऐसा हुआ नही, वह धर्म के आधार पर विभाजन तो हुआ, लेकिन यह जो accord था, यह पेपरों में रह गया, कागजों में रह गया, सच्चाई में नही रहा। हमको यह भी मालूम है कि 1950 में जब इंडिया ने अपना संविधान adopt किया और उसको लागू किया, तो हमने कहा "We, the Socialist, Secular, Republic of India" हमने सेक्युलर होना तय किया और भारत को धर्मनिरपेक्ष देश बनाया, लेकिन पाकिस्तान ने इस्लामिक नेशन पाकिस्तान को घोषित किया, यह

[श्री जगत प्रकाश नड्डा]

हमको मालूम होना चाहिए। Theocratic State बनाई और constitutionally वहां का religion इस्लाम तय हो गया और उसकी दृष्टि को ध्यान में रखकर उन्होंने आगे बढ़ाने का प्रयास किया। यह बात हम आज नही कह रहे हैं, हम जनसंघ के दिनों से कह रहे हैं। मैं अपना 1970 resolution जनसंघ का उद्धृत करना चाहता हूं, जो उस समय की वीभत्स परिस्थितियों के बारे में भी इंगित करता है और अपने आंकड़ों के बारे में भी इंगित करता है कि वहां की परिस्थिति क्या रही। मैं quote करता हूं, "भारत के लिए गर्व का विषय है कि उसने अपने वचन और अल्पसंख्यक मुसलमानों की पूरी तरह रक्षा की है तथा उन्हें बराबरी के अधिकार दिए हैं। भारत में मुसलमानों की तेजी से बढ़ती जनसंख्या इस बात की साक्षी है कि 1961 की जनगणना के अनुसार यह जनसंख्या 5 करोड़ थी, जो अब 6 करोड़ से आगे बढ़ गई है। पाकिस्तान में भी जनसंख्या वृद्धि की गति भारत के समान ही है, लेकिन पाकिस्तान ने भी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए दिए गए आश्वासन का समादर किया होता, तो 1961 की जनगणना में अल्पसंख्यकों की संख्या ढाई करोड़ होनी चाहिए थी, परंतु अल्पसंख्यकों की संख्या घटकर मात्र 90 लाख रह गई है। इन 20 वर्षों में 1 करोड़ अल्पसंख्यकों के मारे जाने तथा उनके विस्थापन का उदाहरण इतिहास में नही मिलेगा। यह हमारा 1970 का resolution है और वहां अल्पसंख्यक की संख्या घट गई, यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। आज अगर हम बात करें, 1947 में पाकिस्तान में minorities were 23 per cent, and in 2017, minorities were 2.3 per cent. This is Pakistan, and this is what we have to understand. हम इधर-उधर की बात न करें, हम मूल पर आएं और मूल यही है, जिसको मैं कह रहा हूं। In 1951, the minorities in India were 9.8 per cent, and in 2010, the minorities in India are 14.23 per cent. पूरे जीने का अधिकार जो मिला है, वह भारत में मिला है और यहां पर माइनॉरिटीज़ फली-फूली हैं और यह हमारी बुलन्दी है, जिसको हम आपके सामने कहना चाहते हैं। महोदय, हमने सबको बराबर देखा है और सबको बराबर समझने का प्रयास किया है। जब मैं वहां, दूसरी तरफ देखता हूं, तो पाता हूं कि galaxy of leaders, galaxy of lawyers और हर तरीके के विद्वान लोग वहां बैठे हैं। कई बार ऐसी स्थिति आती है कि समझते नही हैं, लेकिन राजनीति में ज्यादातर स्थिति ऐसी आती है कि हम समझना चाहते नही हैं। यहां आप समझना चाह नही रहे हैं। You are bringing in Article 14 of the Indian Constitution. You are bringing in right to equality. It has got nothing to do with the right to equality. भारत के किसी भी नागरिक की equlaity पर, इस बिल के पारित होने पर जरा सी भी आंच नही आएगी, इसे आपको समझना चाहिए। It is very clear. साफ शब्दों में है कि कही भी right to equlaity पर कोई असर नही कर रहा है।

महोदय, ये बेचारे बाहर से आए लोग हैं। मैं जब Health Minister था, तब उनसे मिला। आप लोगों में से, मैं नही जानता कि कितने लोगों को आपने देखा है, जो पाकिस्तान से religiously persecute होकर यहां आए हैं। आइए मेरे साथ इंदौर चलिए, आइए मेरे साथ आप कच्छ के बॉर्डर पर चलिए, आइए हम आपको दिखाते हैं वैस्ट बंगाल की तरफ, आप देखेंगे कि डॉक्टर्स की डिग्री वहां से पास कर चुके हैं, but, they are not allowed to practice in India because they don't have the citizenship right there. वे कहां जाएं? उन्होंने medical की परीक्षा पास की है। मैं Health Minister था, लेकिन मैं लाचार था, क्योंकि उन्हें medical की practice करने की permission देने में हमें कानून बाध्य कर रहा था। अब क्या वे यहां 54-55 साल की उम्र में मेडिकल की पढ़ाई करेंगे? वे religiously persecute हो गए। आप उनके वहां जाकर हालात देखिए। अगर आप लोगों में से एक भी नेता उनकी हालत को देखेगा, तो वह तुरन्त ही इस अमेंडमेंट बिल पर मोहर लगाएगा, यह बात मैं आपसे कहना चाहता हूं।

महोदय, मैं बहुत से facts ला सकता हूं। अब मैं आपके सामने अफगानिस्तान की बात करूंगा। मैं आपके सामने जो भी उद्धृत करूंगा, वह उसमें से होगा, जो रिपोर्टिंग हुई है। न्यूयॉर्क टाइम्स, 20 जनवरी, 2002 में लिखता है- "Every Sunday in the late afternoon, the Sikhs and Hindus of Kabul — those few who are left — traverse a circuit of sorrow. Like family members visiting a grave, they go to their five ruined houses of worship, stopping to pray at each one. The temples were on the front line during the factional fighting that devastated Kabul in the early 1990's. Only two survived intact. The temples once held large crowds of worshippers. But the Sikh and Hindu populations of Afghanistan have hemorrhaged over the last decade — from around 50,000 in the early 1990's to 2,000 or fewer today, in cities like Ghazni, Jalalabad and Kandahar. In Kabul, there are exactly 526 Sikhs and Hindus, in 40 Sikh and 10 Hindu families." यह मेरी रिपोर्टिंग नही है, यह न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्टिंग है। मैं एक और रिपोर्टिंग आपको पढ़ाना चाहता हूं। यह गार्डियन की रिपोर्टिंग है- "The collapse of the Soviet-backed regime had left Afghan Sikhs in a vulnerable position. With their black dastar headgear and their neat but untrimmed beards, they stood out the Muslim crowd and became an easily identifiable target for crime and harassment. A community of traders with business contacts stretching from Afghanistan cities to India, Japan and Korea, the Sikhs were perceived as wealthy and this perception in turn made them a key target of kidnapping by the gangs." उनके खिलाफ वहां पर ransom के मामले में उनके कत्ल किए गए। इसमें यह रिपोर्टिंग की गई है। Reuters की रिपोर्टिंग मैं बताना चाहता हूं- "On a bright day in downtown Kabul, Jagtar Singh was

[श्री जगत प्रकाश नड्डा]

in his traditional herb shop when a man turned up, drew a knife and told him to convert to Islam or he would cut his throat. Only bystanders and shopkeepers saved his life." यह रॉयटर्स की रिपोर्टिंग है। मैं ऐसी सारी रिपोर्टिंग यहां रख दूंगा, ताकि वह सदन का पार्ट बन जाए।

महोदय, मैं भावनाओं और उत्तेजनाओं को बढ़ाना नही चाहता था, लेकिन कुछ facts रखना चाहता था कि किस तरीके से इन देशों में minorities के साथ सुलूक किया गया है, वह हमें समझना चाहिए और उसी को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। मैंने पहले भी आर्टिकल 14 का जिक्र किया है। यहां पर किसी के साथ भी, किसी भी प्रकार से किसी के भी अधिकार का हनन नही हो रहा है। यहाँ किसी भी आधार पर आर्टिकल 14 नही आता है। जब persecution religion के आधार पर होगा, तो उत्तर भी religion में ही मिलेगा। मैं यह कहना चाहता हूं कि उसको उसी दृष्टि से देखना चाहिए, इससे ज्यादा नही देखना चाहिए। मैं आदरणीय गृह मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि नॉर्थ-ईस्ट की बात की गई है। He has held more than 100 hours of session. He has met more than 150 delegations, more than 600 people. All issues have been sorted out. और बड़े स्पष्ट शब्दों में कहूंगा, क्योंकि देश के हित में कुछ और होता है, राजनीति के हित में कुछ और होता है, इसलिए मैं चाहूंगा कि राजनीति का हित छोड़ दें और देश के हित का ध्यान रखें, भ्रम को हटाने का प्रयास करें। आपने North-East में भ्रम फैलाने का प्रयास किया है कि North-East वालों के साथ यह हो जाएगा, उनकी sancity खत्म हो जाएगी, उनकी cultural identity खत्म हो जाएगी, उनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। गृह मंत्री जी ने लोक सभा में बड़े विस्तृत रूप में जवाब दिया है कि सबकी आइडेंटिटी बरकरार रहेगी, सबकी entity बरकरार रहेगी, inner line permit बरकरार रहेगा और उनके ऊपर इस Schedule 6 का असर नही पड़ेगा। हम उसको ध्यान में रखकर काम कर रहे हैं। वह इस पर एप्लिकेबल नही होगा, यह बात बड़े स्पष्ट शब्दों में हमारे गृह मंत्री जी ने कही है। इसलिए मैं इन बातों को आपके सामने रखते हुए आपसे इसका निवेदन करना चाहता हूं और एक और बात जरूर कहना चाहता हूं कि कई बार यह होता है कि हम लोग भूल जाते हैं कि हमारी पार्टी का कब, क्या और कैसा स्टैंड रहा है। इसी तरीके मे कई बार क्योंकि सिर्फ जगह बदल जाती है, तो उससे arguments भी बदल जाते हैं, इसलिए मैं चाहूंगा कि this Bill is in the national interest. So, by chanding sides, don't change your arguments. मैं यह इसलिए कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं 18 December को क्वोट करना चाहता हूं। आप आदरणीय डा. मनमोहन सिंह जी का बड़ा आदर करते हैं, आप उनकी कही बातों को मानते हैं, आप उनके कहे हुए रास्ते पर चलने के लिए प्रतिबद्ध हैं, इसलिए मैं 18 दिसंबर, 2003 का, डा. मनमोहन सिंह जी का इसी राज्य सभा में दिया गया वक्तव्य क्वोट करके आपके

ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं। 18 दिसंबर को डा. मनमोहन सिंह जी ने "सिटिजन्स अमेंडमेंट बिल" पर बोलते हुए डिप्टी प्राइम मिनिस्टर श्री एल.के. अडवाणी से कहा था, "While I am on this subject, Madam, उस समय मैडम चेयर पर थीं, "While I am on this subject, Madam, I would like to say something about the treatment of refugees. After the partition of our country, the minorities in countries like Bangladesh have faced persecution, and it is our moral obligation that if circumstances force people, these unfortunate people, to seek refuge in our country, our approach to granting citizenship to these unfortunate persons should be more liberal. I sincerely hope that the hon. Deputy Prime Minister will bear this in mind in charting out the future course of action with regard to the Citizenship Act." यह डा. मनमोहन सिंह जी ने कहा था ...**(व्यवधान)**...

श्री अमित शाह: और उनकी बातों को हम लेकर आए।

श्री जगत प्रकाश नड्डा: हाँ, हम लेकर आए। उनकी बातों को पूरा करते हुए आज हम इस बिल को लेकर आए हैं और इसका समर्थन कर रहे हैं। मैं अंत में सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा कि हम उनके बताए रास्ते पर चलते हुए इसको पूरा कर रहे हैं, जो आप पूरा नहीं कर पाए। आप अपने कार्यालय में भी जिसको पूरा नहीं कर पाए, उसको हम पूरा कर रहे हैं, मैं आपको यह बताना चाहता हूं। मैं अंत में एक बात कहूंगा कि in democracy, we agree to disagree, but we should not always disagree to agree. We should agree sometimes. This Bill is not in the interest of any political party. This is not in the interest of any particular region. This is the call of the nation and this Bill is in the interest of the nation. और भारत ने हमेशा यह साबित किया है कि हमने मानवता के आधार पर सब लोगों को हमेशा आगे बढ़ाया है। आज मैं अपील करूंगा कि हम आपकी विद्धता की तारीफ करते हैं, उसके प्रति नतमस्तक होते हैं, पर मूल को ध्यान में रखो और मूल सिटिज़नशिप अमेंडमेंट बिल में यही है कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बंगलादेश से जो माइनॉरिटीज़ रिलिज़ियस आधार पर वहाँ से पर्सिक्यूट हुई हैं, उनको भारत में सिटिज़नशिप दी जाए और हम उनको देने का समर्थन करते हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ।

SHRI ANAND SHARMA: Sir, I wish to make a small observation.

I thought that I should mention this. Perhaps, it is a coincidence that in such an important debate both the speakers — I myself and Shri Naddaji — are from a small State called Himachal Pradesh.

SHRI JAGAT PRAKASH NADDA: And from the same university.

SHRI ANAND SHARMA: Yes; from the same university.

MR. CHAIRMAN: Himachal is a beautiful State. ...*(Interruptions)*... Please, without the permission of the Chair, nobody has got any business to make any comment by sitting. This is to be understood by all. And, if anybody makes comment either from this side or that side or any side should not go on record. The line is very straight. This has to be understood.

SHRI DEREK O'BRIEN (West Bengal): Sir, I have to make one suggestion. As per the rules of the House, from 1 o' clock to 2 o' clock is lunch break. If we are not going to lunch break, the announcement will have to come from the Chair. Then, we can proceed.

MR. CHAIRMAN: It was, broadly, agreed upon earlier that we should continue with the debate. The debate will continue and the Members who otherwise have problems due to health and all, they can go and have lunch and come back and others will supplement their effort by sitting here continuously.

Now, Shri Derek O' Brien. He will be speaking in Bengali.

SHRI DEREK O'BRIEN: Sir, I will start in Bengali then switchover to English.

* "My Ishwar is Vidyasagar, my Thakur is Rabindranath, my Ram is Rammohan, my Qazi is Nazrul, my Fakir is Lalon. Only a Bengali knows and follows a Bengali's faith.

Sir, why am I saying this today? Because December is an auspicious month for the Bengalis. On 3rd December, Shahid Khudiram Bose was born. On 8th December, another auspicious day, the brave revolutionary Bagha Jotin was born. And who doesn't know about 8th December, 1930? Benoy-Badal-Dinesh, as you all know, attacked Writers' Building without caring about their own lives.

This chapter of history is our pride. And what did the government do at a solemn time like this? They have brought in today an anti-Indian, anti-Bengali Bill.

---

*English translation of the original speech delivered in Bengali

Sir, that is why I want to say, no one should try to teach the Bengalis about patriotism. We have recently seen many have been trying to portray themselves as Bengali-lovers. They come and say even in Parliament that Durga Puja is not being celebrated in Bengal. Sir, thousands of Durga Pujas is celebrated, and Saraswati Pujo is celebrated in every school in Bengal. What do you think? Do you want to know; do you want a proof? Do you want a proof from the great martyr Khudiram Bose? For whom did Benoy-Badal-Dinesh give their lives up? Do they have to furnish proof? For those asking for proof, I would like to tell them to have a look carefully at the list of prisoners in Andaman's Cellular Jail. Seventy per cent of those names were from Bengal. That is why I am telling you, Sir, do not try to teach the Bengalis about patriotism; do not try to teach the Bengalis about citizenship. The British could not break or suppress the will of Bengalis. And do you think you can?"

(MR. DEPUTY CHAIRMAN *in the Chair)*

Sir, the All India Trinamool Congress in that House, along with many other speakers in that House and my colleague, Shri Abhishek Banerjee, and everyone here established that this Bill is unconstitutional. It has been established beyond doubt; we are not going there. There is a view that the Bill from here will go 3.7 kms down to another domed building *i.e.,* the Supreme Court. But, in between, we have a different view. In between, there will be people's movement. There will be sangram. Sir, All India Trinamool Congress is used to this. In 2006, to fight for the land rights, to fight for rights of farmers, Madam Mamata Banerjee sat with people on a 26-day hunger strike. Before it goes to Supreme Court — we respect it a lot — there will be people's movement against this. Sir, sometimes when you prepare for a speech, you get four days, you get four weeks, you get four months. For this one, I had four years to prepare because the All India Trinamool Congress asked me to be on the Committee. So, I would like to make some points from my understanding of this Bill. We are moving from a democracy to a dictatorship. It's not rhetoric; it's a fact. Those who cannot remember the past are condemned to repeat it. I want to go back 84 years ago to two distinct laws that were passed in Nazi Germany. There is an eerie similarity between what we may pass today and those laws. Sir, without any rhetoric, allow me to make my points, citing history.

Basically, what I am trying to prove in the next three minutes or four minutes

[Shri Derek O'brien]

is how we, or the people who have drafted this Bill, have drawn from the Nazi Copybook. One, 1933 — concentration camps; 2018 — detention camps. By the way, sixty per cent of the people in those detention camps are Bengali Hindus. Two, 1935 — the Reich Citizenship Law that protected those with German blood; what do we have today? We have a faulty Citizenship Bill. We are criticizing it because they are trying to define who the true Indian citizens are. We are criticising this Bill as we go along on legitimate grounds. Third, 1935 — the focus back to the Nazis --you needed an identity to prove your lineage. So, what did you have? You were given an ancestral past. What is it today, in 2019? You rely on a piece of paper to prove your Indian citizenship, forget about deemed citizens. 1945 is very interesting. There was a plan to deport the Jews. What did they call it? They called it the Madagascar Plan. What do we have today? We have a Mahaplan, also known as the NRC. Number five, the Germans called it the große Lüge. It was a term coined by Hitler. And, in English, it meant 'big lie'. This is very interesting. This is very interesting, Sir, because if we keep saying lie, lie, lie, it will sound like a truth. What is the lie today? India is under threat. भारत खतरे में है। This is the kind of language that is being used. Sir, that is the big lie. The sixth similarity, it was called the *Lugenpresse.* The *Lugenpresse* was lies and propaganda being pushed against the Jews. And, today, equivalent of the Lügenpresse is the fake news and media being pressurised to push the fake agenda. And, the last one, in the German Copybook they referred to a very interesting word 'Jews' as 'rats'. And, as someone said, once powerful politicians start using dehumanising language, what happens after that, termites! What are we talking about today — termites, cockroaches, vermin. These words are not used by any party worker, but these words are being used by the Prime Minister and sometimes by the Home Minister. ...*(Interruptions)*... सर, यह राजनैतिक दल हक़ और अधिकारों की बात करता है, लेकिन इस दल की नींव तीन 'झ' पर है - 'झूठ', 'झांसा' और 'जुमला'। आप कहते हैं कि घुसपैठिए आ कर आपके अधिकारों को छीन रहे हैं, लेकिन सच यह है कि पांच सालों में हिन्दुस्तान के दो करोड़ लोगों ने अपनी नौकरी खो दी है। सर, जो देश में है, आप उनका ख्याल तो रख नहीं सकते, उनको रोटी, मकान तो दे नहीं सकते और आप अधिकारों की बात कर रहे हैं? सम्मान की बात कर रहे हैं? Now, let us go to the understanding of the link between the CAB and the NRC and they cannot be separated. We warned the Standing Committee

four years ago; we made our point then. What about the NRC, Sir? You could not run NRC in one State. Your percentage of error was seven. If you extrapolate it on the nation, when you do the NRC, where are you going to end up 10 crore people. It did not work in one State. Pilot project did not work, and now you have the gumption to tell Parliament, 27 में होगा, after your pilot project has failed. Let us talk about some numbers from the Standing Committee. The Prime Minister and the Home Minister are using the numbers. Let us look at the numbers. These are not my numbers. When the Director of Intelligence Bureau came before the Standing Committee, these are the numbers he gave. Buddhists -2, Parsis -2, Christians — 55, Sikhs — 5,000 and Hindus — 25,000. In total, the number is 31,000.

श्री अमित शाह: दे दीजिए। ...**(व्यवधान)**... अगर इतना ही कम है, तो दे देना चाहिए। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: प्लीज़। ...**(व्यवधान)**... आप continue कीजिए।

SHRI DEREK O'BRIEN: When the Home Minister is saying, I must be speaking some truth then. How long will this take? How long will the process take? By when will it be completed? Give us the numbers, Sir.

Now, I am coming to the main part of my intervention today. You made some promises. Both of you made some promises. किसी को भी चिन्ता करने का कोई कारण नहीं है। नहीं, सर। मैं आपको समझाऊँगा कि बहुत चिन्ता करने का कारण है, क्योंकि आपने आगे का वादा किया? आपने आगे वादा किया। नवम्बर, 2016 में प्रधान मंत्री जी ने कहा कि मैं सिर्फ 50 दिन माँगता हूँ, 30 दिसम्बर तक मुझे मौका दीजिए, उसके बाद देश जो सजा तय करेगा, वह सजा। I am willing to accept. This is what the hon. Prime Minister said. We all know what happened in demonetisation. In the last two years, the term has not been used. दूसरा, चिन्ता का कारण है, सर चौकीदार के पाँच वर्ष की चौकीदारी में कोई बड़ा धमाका हुआ? चिन्ता का कारण है, क्योंकि 2008-2014, 390 हुआ और last year एक साल में 450 हो गया। तो चिन्ता का कारण है, क्योंकि वादा करते हैं।

Now, I am coming to the last one. I want to assure all my Gorkha brothers and sisters that none will be inconvenienced. The Gorkhas fought strongly and the Bengalis also fought strongly in the freedom movement. चिन्ता का कारण है। Credibility, चिन्ता, again नयी आशा। अब भारत में एक बड़ा लक्ष्य 5 Million Dollar Economy है। ...**(व्यवधान)**... Yes, trillion. ...*(Interruptions)*... Sorry, sorry. मैं तृणमूल का

[Shri Derek O'brien]

हूँ, नम्बर थोड़ा छोटा बोलता हूँ। ...**(व्यवधान)**... It is 5 trillion dollar economy. This Government is very good at making promises. This Government is even better at breaking promises. Who have you left out from this? You have left out Hindus from other States and tribals. The other point is that four months ago, you brought the Jammu and Kashmir Bill. Why? One nation, one tax, one election, one everything. How come today are the rules different? As per your Bill, you have laid down multiple grounds of citizenship for one country. You have. I want to touch upon how you have treated the Hindus and how you have treated the Bengali Hindus. Let me give you a few points. As you know, 60 per cent of the detention camps are of Bengali Hindus. In the NRC, who is excluded? Now, you will give me the argument that because they were excluded in the NRC, now you want to bring them back, the false promise, that Bengali Hindus were left out of the NRC citizenship. Now, when they apply to NRC, they have to prove their Indian citizenship. And now they will have to prove that they were from a neighbouring country. Sir, one crore people came from East Pakistan. This is not about persecution-religious; this was linguistic persecution, linguistic persecution in the 1970s. How many people have lost their documents, poor, poor people? How many millionaires will be missing from this? None. These are poor people who have lost their documents in floods, who lost their documents through ethnic violence. You talk about Mathuaws in Bengal. The Mathuaws have been voting, living, deemed citizens. For the last 50 years, they have been voting in Bengal. What new thing are you giving them? You are packaging it better.

Sir, someone said, I think, yesterday, or the Prime Minister said, may have read it, it was that 'after this, it will be written in golden letters'. Yes, Sir, it will be written in golden letters. I will tell you where it will be written. This great day! It will be written on the Father of the Nation's grave. But which Father of the Nation? In Karachi — Mazare-e-Quaid. That will be written on Jinah's grave; not on our Father of the Nation's grave. ...*(Interruptions)*...

श्री उपसभापति: कृपया शांति रखें।

SHRI DEREK O'BRIEN: Sir, there is this great narrative being built because this is all about perception. There is nothing in this Bill. This is about perception. So, for the next one year, let us create perception. No Durga Puja in Bengal! Do

Durga Puja in Bengal. Come to Bengal. Understand Bengal. Bengal is not the Gujarat Gymkhana. We have our own little way. With all due respect, we love Dhokla, we love the people in Gujarat. But it is not the Gujarat Gymkhana. दुर्गा पूजा carnival होता है, स्कूल में सरस्वती पूजा होती है, सब होता है। And leave Bengal now. You look after anywhere else. Look after anywhere else. You keep bringing अफगानिस्तान में यही हुआ, पाकिस्तान में यही हुआ। 2008 में यूपी में क्या हुआ? गाँधीनगर में क्या हुआ? Eighty temples have been desecrated in Gujarat; in Rajasthan, in 2000 — the figures I have — 104 temples desecrated; Kanpur, Tughlakabad. You are talking about protecting people from all over ...*(Interruptions)*... Sir, today, at least, the Opposition should stop this argument that this is a distraction because economy is there. It is not a distraction. Today we have heard two speakers, the Minister and the speaker. It is not a distraction. This is the agenda. This is the majority view. Who is that majority check? Forty per cent of India, not 60 per cent of India. But majority doesn't mean that you are always right. This much you must allow us. Majority doesn't mean that you are almost right because it is majority on one side — this afternoon --but this side is on morality. And today I appeal to those parties who are sitting here, the JD(U) and the BJD, very humbly, that today is the day for you to stand up and be counted. Not because what you have to answer to your Chairperson in Bihar or Odisha. No. What will you tell to your grandchildren twenty years from now when they ask you which button did you press?

Sir, I have got two more points and then I will conclude. You know I don't take extra time. Sir, you know when we speak about all this Constitution, history, understanding State, but as I move to my conclusion, sometimes, the best stories are the personal stories. They are giving us numbers about how the minorities were lower here and now the minority numbers have increased and in those States, they have come down. This is my personal story. The O'Brien family, Sir, my great grandfather was Irish, Christian, married to a Bengali Hindu. So, if you actually do a DNA test, I don't know but 26 परसेंट रह ही जाएगा। ...*(Interruptions)*... Sir, on a serious note, my grandfather and his youngest brother stayed back in India and the eldest brother was in Pakistan. So, we have the O'Briens of India and the O'Briens of Pakistan, 1947. We are in touch. Now what happened? The O'Briens of Pakistan either left for Canada, England or Australia or they married, they converted to Islam and they have gone. But the O'Briens of India because of the power of our Constitution, we are still standing here, Sir, today because of the ...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you.

SHRI DEREK O'BRIEN: Sir, two minutes; two minutes. Sir, you give me two minutes. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude. ...*(Interruptions)*...

SHRI DEREK O'BRIEN: Sir, one minute. ...*(Interruptions)*...

श्री उपसभापति: कृपया शांति रखें। ...**(व्यवधान)**... Please conclude. ...*(Interruptions)*... कृपया शांति रखें। This is a very important issue. ...*(Interruptions)*...

SHRI DEREK O'BRIEN: Let me make my point, Sir. ...*(Interruptions)*... Sir, 20 Ministers are. ...*(Interruptions)*... Please protect me. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Just conclude. Already one minute has gone. Please conclude. ...*(Interruptions)*...

SHRI DEREK O'BRIEN: Sir, please understand, that is precisely why we are opposing this Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you.

SHRI DEREK O'BRIEN: Not 'thank you', Sir. Give me two minutes.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Not two minutes; you have already taken one minute. Please conclude within one minute. ...*(Interruptions)*...

SHRI T.K. RANGARAJAN: Sir, even the hon. Chairman had agreed to two minutes. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please take your seat. Don't talk from there. Mr. Derek, I am giving you one minute. Please conclude. You know the. ...*(Interruptions)*...

SHRI DEREK O'BRIEN: Sir, I know the rules.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Not the rules, but you know the art of concluding within the time-limit. ...*(Interruptions)*...

SHRI DEREK O'BRIEN: Sir, let me make my point. We do not have even a

single other speaker from our Party. We are the third largest Party in Rajya Sabha. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Eighteen minutes. ...*(Interruptions)*...

SHRI DEREK O'BRIEN: No, Sir; I do not want to bargain for one minute. Give me time to speak.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude within one minute. ...*(Interruptions)*...

SHRI DEREK O'BRIEN: Sir, I would conclude with two points. That is precisely the point I was trying to make. Words of advice from Shri C. Ramakrishna — jatho math thatho path; as there are number of beliefs, there are number of ways. Sir, on a winter in November. ...(Time-bell rings)... Sir, four lines.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude. It is already two minutes. ...*(Interruptions)*...

SHRI DEREK O'BRIEN: Sir, I am the Leader of the third largest Opposition Party in Rajya Sabha and I have to beg for one minute! ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That is why I have given you two minutes. Just conclude. You have already spoken for two minutes. ...*(Interruptions)*... Don't speak like that, sitting there. You have no right. ...*(Interruptions)*...

SHRI TIRUCHI SIVA (Tamil Nadu): Sir, this is a very important issue. Kindly allow... ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please. ...*(Interruptions)*... You have got no business talking from there! ...*(Interruptions)*... just conclude. ...*(Interruptions)*... Please take your seat. Nothing is going on record. ...*(Interruptions)*... Mr. Derek, please finish in one minute.

SHRI DEREK O'BRIEN: Sir, my last seven lines — One, on a winter November evening in 2016, you separated the poor people of this country from their money. Two, months later, through a hasty GST, you separated businesses from profit. Three, in August this year, you separated the people of Jammu and Kashmir from their State. With this Bill today, the CAB-NRC combined, you want to separate genuine Indian citizens from their own homeland.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude. Three. ...*(Interruptions)*...

SHRI DEREK O'BRIEN: Sir, I said seven. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You have taken three minutes. ...*(Interruptions)*...

SHRI DEREK O'BRIEN: NRC haube naa. CAB haube naa. We all know it will not happen in Bengal, but we will not let it happen anywhere in India. Jai Hind, Vande Mataram, Jai Bangla! ....*(Interruptions)*...

SHRI SWAPAN DASGUPTA: *

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please take your seat, Shri Swapan Dasgupta. ...*(Interruptions)*... Nothing is going on record. ...*(Interruptions)*... Now, Shri A. Navaneethakrishnan. Your Party has 15 minutes; there are three speakers; so, five minutes each.

SHRI A. NAVANEETHAKRISHNAN (Tamil Nadu): Sir, from my Party, Shri S.R. Banasubramonian would speak first. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Time has been decided in the BAC ...*(Interruptions)*... Shri S.R. Balasubramoniyan; five minutes only. ...*(Interruptions)*...

SHRI S.R. BALASUBRAMONIYAN (Tamil Nadu): Sir, this Bill is called the Citizenship (Amendment) Bill, 2019. Here, it has been made clear as to who are entitled to be the citizens of India. It says, "Provided that any person belonging to Hindu, Sikh, Buddhist, Jain, Parsi or Christian community from Afghanistan, Bangladesh or Pakistan, who entered into India on or before the 31st day of December, 2014 and who has been exempted by the Central Government by or under clause (c) of sub-section (2) of section 3 of the Passport (Entry into India) Act, 1920 or from the application of the provisions of the Foreigners Act, 1946 or any rule or order made thereunder, shall not be treated as illegal migrant for the purposes of this Act".

श्री उपसभापति: यह महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है। ...**(व्यवधान)**... देश देख रहा है। अपनी-अपनी जगह शांति से बैठें। ...**(व्यवधान)**...

---

*Not recorded

SHRI S.R. BALASUBRAMONIYAN: It is very clear that people, who have entered India as migrants or refugees from these three countries, are entitled to become the citizens of India. At the same time, what is puzzling is that certain areas have been left out. For example, Sri Lankan refugees, who came to India, particularly to Tamil Nadu, and have been living here for many years, are not entitled to become the citizens of this country. Hindus, Buddhists, Christians or refugees from any other community, more particularly, refugees from Sri Lanka including Muslims, are left out. The State has been left out; people have been left out. My friend, Shri Derek O'Brien was referring to East Bengal. Some years ago, there were one crore people — he did not mention the figure — as refugees in India. They were given asylum. We fed them for one year. They were allowed to stay here for one year. But after the Bangladesh war, they went back to Bangladesh. When the then Prime Minister of the country Indira Gandhi was in Calcutta, Pakistan forced a war on the western frontier in Punjab. When she came to know that, she wanted to fly back to Delhi immediately. She was advised not to leave Calcutta and go to Delhi because there was a complete blackout in Delhi. But she said, "No. It is not proper for me. Being the Prime Minister, I must be present in Delhi. Delhi is the Capital of India; I am going back." When she entered Delhi's airspace, there was a complete blackout. Some lights were lit on the runway to enable the aircraft to land in Delhi. She landed in Delhi and met the Service Chiefs on the airport itself. She had a discussion there and they went into action immediately. Within fifteen days, Bangladesh was liberated and most of the people left India and went back to Bangladesh. There were Muslims; they were given asylum. They stayed here for more than a year. After that, they went back to the present day Bangladesh, which was earlier East Pakistan. Some of them are in India now because not all of them left at that time. Some people are in India and they are Hindus, Muslims, Christians and from other communities. Are you aware of this or not? I want to know this from the Government because their names have also been left out. Who are refugees? Refugees are people who are forced to flee from their countries because of threat to their lives for reasons of race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion. So, they belong to a particular opinion. They were against Pakistan; they were Muslims. Don't forget it. Among one crore, there were thousands of people belonging to other communities also. Among one crore, some of them stayed back.

[Shri S.R. Balasubramoniyan]

Are they not entitled to become the citizens of this country? This is my question. Will they find a place here?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: There are two more speakers from your Party. ...*(Interruptions)*...

SHRI S.R. BALASUBRAMONIYAN: Sir, I am concluding in one minute.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That much time will be reduced for others. Please keep it in mind.

SHRI S.R. BALASUBRAMONIYAN: I appeal to the hon. Home Minister and the hon. Prime Minister to revisit and rethink it and add the names of Muslims also. But, of course, we are supporting the Bill.

श्री उपसभापति: माननीय सदस्यगण, मैं आपको बताना चाहूंगा कि Business Advisory Committee में सर्वसम्मति से इस विषय के महत्व को देखते हुए 6 घण्टे बहस का टाइम निर्धारित हुआ है। इसमें 48 स्पीकर्स के नाम हैं। We have to follow time at any cost. Number one, कृपया आप सीट पर बैठ कर बीच में न बोला करें।

दूसरी बात यह बताना चाहूंगा कि नियमत: rules and procedure के अनुसार बहस शुरू होने के आधे घण्टे पहले तक सूचना दें। अभी तक 5-7 लोग अपना नाम भेज रहे हैं। इसलिए ये नाम include नही होंगे। ऑलरेडी 48 स्पीकर्स हैं। श्री जावेद अली खान, आपके पास 12 मिनट हैं।

श्री जावेद अली खान (उत्तर प्रदेश): महोदय, 3 मिनट थे, कल मैंने चार्ट देखा था।

† **جناب جاوید علی خان:** مہودے، تیرہ منٹ تھے، کل میں نے چارٹ دیکھا تھا۔

श्री उपसभापति: यहां 12 मिनट लिखा हुआ है। मैं चार्ट देखकर बोल रहा हूं।

श्री जावेद अली खान: माननीय उपसभापति महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण और संवेदनशील बिल पर बोलने का अवसर दिया। इस बिल पर सदन के अंदर चर्चा हो रही है, दूसरे सदन में चर्चा हो चुकी है और देश भर में यह बिल चर्चा का विषय बना हुआ है। कई सारे बयान आए, कई सारी बातें हुई, मैं नही समझ

†Transliteration in Urdu Script.

पा रहा था कि अपनी बात कहां से शुरू करूं। गृह मंत्री जी चले गए, वरना मैं अपनी बात उनसे शुरू करता। मैं पीठ के एक कमेंट से अपनी बात शुरू करना चाहता हूं, क्योंकि पीठ हमारी संरक्षक है, पीठ हमारे लिए आदर्श है। इस महीने की 4 तारीख को, मैं किसी का नाम नही लूंगा, एक सदस्य ने एक प्रश्न पूछते हुए हमारे सदन के अंदर एक धर्म विशेष का नाम ले लिया। पीठ को आपत्ति हुई, यह स्वाभाविक है। चेयरमैन साहब ने, पीठ ने क्या कहा, आप इस पर ग़ौर कीजिए। "Why do you speak? What you speak will not go on record. You can't make general commentary and defame the country. Don't defame the country and don't bring community in the House." सदस्य बोले, "I am just stating the fact." Chair ने कहा, "Everything is a fact. Don't argue with Chair. Please sit down. Please sit down. कृपया आप बैठ जाइए।" हो सकता है, उन सदस्य को बुरा लगा हो, उनके साथियों को बुरा लगा हो, किंतु मुझे रत्ती भर भी बुरा नही लगा कि एक धर्म के नाम के आधार पर यदि कोई साथी कोई प्रश्न पूछना चाहते थे, तो चेयर ने उनको रोका, बल्कि मेरे लिए इस देश की परम्परा, इस सदन की परम्परा और इस देश के संविधान के लिए और ज्यादा मान मेरी नज़र में बढ़ गया कि मैं एक ऐसे सदन का सदस्य हूं, जहां धर्म के आधार पर न अनुराग होगा, न द्वेष होगा। लेकिन यह जो बिल आया है, जैसा हमारे साथियों ने बताया और जब कानून के विद्वान बोलेंगे, हमारे सदन में कई सारे विद्वान हैं। यह बिल आर्टिकल 14 और दूसरे संविधान के अनुच्छेदों का किस प्रकार उल्लंघन करता है, उसके बारे में वे बताएंगे, लेकिन एक बात स्पष्ट है, हमारे उद्देश्यों और कारणों में भी लिखा गया है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बंगलादेश के संविधान में विनिर्दिष्ट राज्य धर्म का उपबंध किया गया है, परिणामस्वरूप हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के बहुत से व्यक्तियों को इन देशों में धर्म के आधार पर अत्याचारों का सामना करना पड़ा है। यानी धर्म शासित राज्य में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार होंगे, यह बात हम मान रहे हैं और यह माना भी जाना चाहिए कि धर्म शासित राज्य कितना भी अच्छा हो theocratic state, वह अंत में अल्पसंख्यकों के साथ दुर्व्यवहार करती है। असली वाले अध्यक्ष जी तो नही हैं, लेकिन यहां रूलिंग पार्टी के कार्यवाहक अध्यक्ष बैठे हुए हैं, इसलिए मैं उनसे आश्वासन चाहता हूं कि धर्म शासित राज्य, चूंकि अल्पसंख्यकों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, इसलिए हमारे देश में यदि कोई दल, संगठन, कोई व्यक्ति आदि भारत को धर्म शासित राज्य, चाहे इस्लामी राष्ट्र हो, चाहे खालिस्तान हो, चाहे हिन्दू राष्ट्र बनाने की वकालत करे, उसका खण्डन कीजिए और भारतीय जनता पार्टी को खुले तौर पर ऐलान करना चाहिए कि चूंकि धर्म शासित राज्य अपने नागरिकों के साथ अत्याचार करता है, इसलिए हम किसी प्रकार के धर्म शासित राज्य का समर्थन नही करेंगे, बल्कि उन लोगों को रोकेंगे। सर, मैं जानता हूं कि CAB एक अलग कानून है, एन.आर.सी. अभी पाइपलाइन में है, वह हमारी सरकार की मंशा है। मैं चाहता था कि ये दोनों विषय अलग-अलग रहने चाहिए थे। कई

[श्री जावेद अली खान]

बार माननीय गृह मंत्री जी के भाषण चुनाव में सुने और बाद में भी सुने और उनके वक्तव्य भी सुने। उन्होंने कहा कि इन दोनों चीज़ों को मिलाकर देखिए। जब वे बंगाल के लोगों को संबोधित करते हैं, तब तो बहुत ज्यादा ही इसको मिला देते हैं। मैं इस विषय में दो-तीन बातें कहना चाहता हूं। हमारे देश का बंटवारा हुआ था, Two Nation Theory, जिसे हम द्वि-राष्ट्र का सिद्धांत कहते हैं। सावरकर जी मानते होंगे कि हिंदू एक राष्ट्र है, जिन्ना मानते होंगे कि मुसलमान एक राष्ट्र है, लेकिन मैं पूरे होशोहवास में कह रहा हूं कि मैं नही मानता कि राष्ट्र, धर्म के आधार पर बन सकता है। हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है, Two Nation Theory का मतलब क्या है, इस्लामी राष्ट्र का मतलब क्या है? इनका मतलब यही है कि आए दिन हम कई लोगों के भाषणों में सुनते रहते हैं... मैं किसी नेता या मंत्री का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन इनके सहयोगियों का भाषण, कि हम हिंदुस्तान को मुस्लिम मुक्त बनाएंगे। कई लोग तो तारीख़ तक बता देते हैं कि 2021 तक मुस्लिम मुक्त बनाएंगे, 2024 तक मुस्लिम मुक्त बनाएंगे...**(व्यवधान)**... मैंने किसी का भी नाम नही लिया है। ...**(व्यवधान)**... लेकिन आपके कई सहयोगियों ने इस तरीके के वक्तव्य दिए हैं, जो आज पब्लिक डोमेन में हैं। मान्यवर, अगर मैं नियमों से हटूंगा ...**(व्यवधान)**...

† **جناب جاوید علی خان (اتّر پردیش)** : مانّنے اپ سبھا پتی مہودے، میں آپ کا دھنیواد کرتا ہوں کہ آپ مجھے اس اہم اور سنویدن شیل بل پر بولنے کا موقع دیا۔ اس بل پر سدن کے اندر چرچا ہو رہی ہے، دوسرے سدن میں چرچا ہو چکی ہے اور دیش بھر میں یہ بل چرچا کا موضوع بنا ہوا ہے۔ کئی سارے بیان آئے، کئی ساری باتیں ہوئیں، میں نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ اپنی بات کہاں سے شروع کروں۔ گرہ منتری جی چلے گئے، ورنہ میں اپنی بات ان سے شروع کرتا۔ میں پیٹھہ کے ایک کمینٹ سے اپنی بات شروع کرتا ہوں، کیوں پیٹھہ ہماری سنرکشک ہے، پیٹھہ ہمارے لئے آدرش ہے۔ اس مہینے کی چار تاریخ کو، میں کسی کا نام نہیں لوں گا، ایک ممبر نے ایک سوال پوچھتے ہوئے ہمارے سدن کے اندر ایک دھرم وشیش کا نام لے لیا۔ پیٹھہ کو آپتّی ہوئی، یہ سوابھاوک ہے۔

†Transliteration in Urdu script.

چیئرمین صاحب نے، بیٹھہ میں کیا کہا، آپ اس پر غور کیجئے۔ "Why do you speak? What you speak will not go on record. You can't make general commentary and defame the country. Don't defame the country and don't bring community in the House." سدسئے بولے۔ "I am just stating the fact." چیئر نے کہا۔ "Everything is a fact. Don't argue with Chair. Please sit down. Please sit down. کرپیہ آپ بیٹھہ جائیے"۔ ہو سکتا ہے، ان ممبر کو برا لگا ہو، ان کے ساتھیوں کو برا لگا ہو، چونکہ مجھے رتّی بھر بھی برا نہیں لگا کہ ایک دھرم کے نام کے آدھار پر اگر کوئی ساتھی کوئی سوال پوچھنا چاہتے تھے، تو چیئر نے ان کو روکا، بلکہ میرے لئے اس دیش کی پرمپرا، اس سدن کی پرمپرا اور اس دیش کے سنودھان کے لئے اور زیادہ مان میری نظر میں بڑھہ گیا کہ میں ایک ایسے سدن کا ممبر ہوں، جہاں دھرم کے آدھار پر نہ انوراگ ہوگا، نہ دویش ہوگا۔ لیکن یہ جو بل آیا ہے، جیسا ہمارے ساتھیوں نے بتایا اور جب قانون کے ودوان بولیں گے، ہمارے سدن میں کئی سارے ودوان ہیں۔ یہ بل آرٹیکل 14 اور دوسرے سنودھان کے دفعات کا کس طرح اُلّنگھن کرتا ہے، اس کے بارے میں وہ بتائیں گے، لیکن ایک بات صاف ہے، ہمارے اڈیشوں اور کارنوں میں بھی لکھا گیا ہے کہ پاکستان، افغانستان اور بنگلہ دیش کے سنودھان میں ونردشٹ راجیہ دھرم کا اپبندھہ کیا گیا ہے، جس کے نتیجے میں ہندو، سکھہ، بودھہ، جین، پارسی اور عیسائی طبقے کے بہت سے لوگوں کو ان دیشوں میں دھرم کے آدھار پر اتیاچاروں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ یعنی دھرم شاست راجیہ میں اقلیتوں پر اتیاچار ہوں گے، یہ بات ہم مان رہے ہیں اور یہ مانا بھی جانا چاہئے کہ دھرم شاست راجیہ کتنا بھی اچھا ہو,theocratic state وہ آخر میں اقلیتوں کے ساتھہ برا سلوک کرتی ہے۔ اصلی والے ادھیکش جی تو نہیں ہے، لیکن یہاں رولنگ پارٹی کے کارئے واہک ادھیکش بیٹھے

[श्री जावेद अली खान]

ہوئے ہیں، اس لئے میں ان سے آشواسن چاہتا ہوں کہ دھرم شاست راجیہ، چونکہ اقلیتوں کے ساتھہ برا سلوک کرتے ہیں، اس لئے ہمارے دیش میں اگر کوئی دل، سنگھٹن، کوئی آدمی وغیرہ بھارت کو دھرم شاست راجیہ چاہے اسلامی راشٹر ہو، چاہے خالصتان ہوں، چاہے ہندو راشٹر بنانے کی وکالت کرے، اس کا کھنڈن کیجئے اور بھارتیہ جنتا پارٹی کو کھلے طور پر اعلان کرنا چاہئے کہ چونکہ دھرم شاست راجیہ اپنے ناگرکوں کے ساتھہ برا سلوک کرتا ہے، اس لئے ہم کسی طرح کے دھرم شاست راجیہ کا سمرتھن نہیں کریں گے، بلکہ ان لوگوں کو روکیں گے۔

سر، میں جانتا ہوں کہ سی اے بی ایک الگ قانون ہے، این آر سی ابھی پائپ لائن میں ہے، وہ ہماری سرکار کی منشا ہے۔ میں چاہتا تھا کہ یہ دونوں موضوع الگ الگ رہنے چاہیئے تھے۔ کئی بار مانیئے گرہ منتری جی کے بھاشن چناؤ میں سنے اور بعد میں بھی سنے اور ان کے بیانات بھی سنے۔ انہوں نے کہا کہ ان دونوں چیزوں کو ملاکر دیکھئے۔ جب وہ بنگال کے لوگوں کو مخاطب کرتے ہیں، تب تو بہت زیادہ ہی اس کو ملادیتے ہیں۔ میں اس موضوع میں دو تین باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ ہمارے دیش کا بٹوارہ ہوا تھا، ٹو نیشن تھیوری، جسے ہم دو راشٹر کا سدّانت کہتے ہیں۔ ساورکر جی مانتے ہونگے کہ ہندو ایک راشٹر ہے، جناح مانتے ہونگے کہ مسلمان ایک راشٹر ہے، لیکن میں پورے ہوش و ہواس میں کہہ رہا ہوں کہ میں نہیں مانتا کہ راشٹر، دھرم کے آدھار پر بن سکتا ہے۔ ہندو راشٹر کا مطلب کیا ہے، ٹو نیشن تھیوری کا مطلب کیا ہے۔ اسلامی راشٹر کا مطلب کیا ہے؟ ان کا مطلب یہی ہے کہ آئے دن ہم کئی لوگوں کے بھاشنوں میں سنتے رہتے ہیں... میں کسی نیتا یا منتری کا نام نہیں لے رہا ہوں، لیکن ان کے سہیوگیوں کا بھاشن، کہ ہم ہندستان کو مسلم مکت بنائیں گے۔ کئی لوگ تو تاریخ تک بتا دیتے ہیں کہ 2021 تک مسلم مکت بنائیں گے، 2024 تک مسلم مکت بنائیں گے ...(مداخلت)... میں

نے کسی کا بھی نام نہیں لیا ہے۔ ...(مداخلت)... لیکن آپ کے کئی سہیوگیوں نے اس طریقے کے بیانات دئیے ہیں، جو آج پبلک ڈومین میں ہیں۔ مانیور، اگر میں اصولوں سے ہٹونگا ...(مداخلت)...

श्री उपसभापति: कृपया शांत हो जाइए। जावेद जी आप बोलिए। कृपया शांत हो जाइए।

श्री जावेद अली खान: और Two Nation Theory के तहत इस्लामी राष्ट्र का क्या मतलब था कि पाकिस्तान हिंदू मुक्त होगा? मैं बड़े दुख के साथ इस बात को कह रहा हूं कि जो ख्वाब मोहम्मद अली जिन्ना का 1947 में बंटवारे के वक्त पूरा नही हो पाया कि हिंदुस्तान मुस्लिम मुक्त हो और पाकिस्तान हिंदू मुक्त हो, तो इस एन.आर.सी. और सी.ए.बी. के आने के बाद हमारे देश की सरकार जिन्ना का ख्वाब पूरा करने जा रही है, यह बात मैं कहना चाहता हूं। जब हमारा संविधान बना, तो बहुत से लोग यह कहते हैं कि secularism को सन् 1976 में घुसा दिया गया। सर, secularism को सन् 1976 में नही, secularism संविधान सभा के अंदर ही था। सरदार पटेल जी हमारे पहले गृह मंत्री, आज़ादी के आंदोलन के बड़े सिपाही, बड़े नेता रहे। आज आप उनकी कितनी बड़ी मूर्ति बना लीजिए, लेकिन सरदार पटेल के कद को उस मूर्ति की ऊंचाई छू नही सकती है, यह मै बता रहा हूं। वे इतने बड़े नेता थे। संविधान सभा की बहस के दौरान सरदार पटेल ने क्या कहा? मई 1949 में जब संविधान सभा की बैठक चल रही थी, तो उन्होंने कहा "We are laying the foundation of a truly secular democracy in India." फिर 5 जून, 1949 की बैठक में क्या कहते हैं "The healthy secular outlook is the foundation of a true deomcracy." लेकिन आज हमारी सरकार कानून के या संविधान के साथ जिस तरीके का व्यवहार कर रही है, हिंदू, मुसलमान के नाम पर यहां लोगों की शिनाख़्त करके, उन्हें कुछ सहायता या मदद देने की बात करती है। मान्यवर, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि यह स्थिति कानून की नज़र में, संविधान में नज़र में बहुत अच्छी नही है। यह किसलिए नही है... और एक दूसरी बात, माननीय गृह मंत्री जी ने कई बार कहा इस कानून का मुसलमानों से कोई लेना-देना नही है। मैं exact शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं, जो लोक सभा के अंदर माननीय गृह मंत्री जी ने जवाब देते हुए कहा। यहां लेना-देना शब्द इस्तेमाल नही किया है। ...**(व्यवधान)**...

† **جناب جاوید علی خان:** اور ٹونیشن تھیوری کے تحت اسلامی راشٹر کا کیا مطلب تھا کہ پاکستان ہندو مُکت ہوگا؟ میں بڑے دکھ کے ساتھ اس بات کو کہہ رہا ہوں کہ جو خواب محمد علی جناح کا 1947 میں بٹوارے کے وقت پورا نہیں ہوپایا کہ ہندوستان مسلم مکت ہو اور پاکستان ہندو مکت ہو، تو اس این آر سی اور سی اے بی کے آنے کے بعد ہمارے دیش کی سرکار جناح کا خواب پورا کرنے جارہی ہے، یہ بات میں کہنا چاہتا ہوں۔ جب ہمارا سمودھان بنا، تو بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ سیکولرزم کو سن 1976 میں گھسادیا گیا، سیکولرزم کو سن 1976 میں نہیں، سیکولرزم سمودھان سبھا کے اندر ہی تھا۔ سردار پٹیل جی ہمارے پہلے گرہ منتری، آزادی کے آندولن کے بڑے سپاہی، بڑے نیتا رہے۔ آج آپ ان کی کتنی بڑی مورتی بنالیجئے، لیکن سردار پٹیل کے قد کو اس مورتی کی اونچائی چھو نہیں سکتی ہے، یہ میں بتارہا ہوں۔ وہ اتنے بڑے نیتا تھے۔ سمودھان سبھا کی

†Transliteration in Urdu script.

[श्री जावेद अली खान]

بحث کے دوران سردار پٹیل نے کیا کہا؟ منی 1949 میں جب سمودھان سبھا کی بیٹھک چل رہی تھی، تو انہوں نے کہا† "We are laying the foundation of a truly secular democracy in India." پھر 5 جون، 1949 کی بیٹھک میں کیا کہتے ہیں

"The healthy secular outlook is the foundation of a true democracy."

لیکن آج ہماری سرکار قانون کے یا سنودھان کے ساتھ جس طریقے کا ویوہار کر رہی ہے، ہندو، مسلمان کے نام پر یہاں لوگوں کی شناخت کرکے، انہیں کچھ سہائتہ یا مدد دینے کی بات کرتی ہے۔ مانیور، میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ حالت قانون کی نظر میں، سنودھان کی نظر میں بہت اچھی نہیں ہے۔ یہ کس لئے نہیں ہے --- اور ایک دوسری بات، مانّنے گرہ منتری جی نے کئی بار کہا اس قانون کا مسلمانوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ میں exact شبدوں کا استعمال کر رہا ہوں، جو لوک سبھا کے اندر مانّنے گرہ منتری جی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ یہاں لینا دینا شبد استعمال نہیں کیا ہے ---(مداخلت)---

श्री उपसभापति: संजय जी, कृपया बैठकर मत बोलिए। ...**(व्यवधान)**...

श्री जावेद अली खान: यह कहा गया कि इस कानून से इस देश के मुसलमानों का कोई लेना-देना नही है। क्यों साहब,हम इस देश के नागरिक नही हैं, मुसलमान इस देश के बाशिंदे नही हैं? देश के preamble को घायल कर दिया जाए, इस देश के articles, अनुच्छेदों को घायल कर दिया जाए और संविधान का जो secular foundation है, उसकी जड़ों को हिला दिया जाए और फिर कहो कि इस कानून से मुसलमानों का कुछ लेना-देना नही है। इसलिए मुसलमानो, तुम अपने घर में रहो - क्या हम दो नम्बर के शहरी हैं? क्या मुसलमान दूसरे दर्जे के नागरिक हैं? यह दूसरे दर्जे के नागरिक होने की बात के संबंध में मैं यह कहना चाहता हूं, सर, क्योंकि आप विद्वान हैं और चीज़ों को समझते हैं - एक किताब है, 'We or Our Nationhood Defined' by Shri M.S. Golwalkar. यह किताब 1939 में लिखी गयी थी। गोलवलकर साहब जब इसमें पांचवां chapter लिखते हैं तो उसमें व्याख्या करते हैं कि इस देश में दूसरे लोगों की, जो हिन्दुओं के अलावा होंगे, उनकी क्या स्थिति होगी। वे खुद ही सवाल पूछते हैं - "If, as is indisputably proved, Hindustan is the land of the Hindus and is the terra firma for the Hindu nation alone to flourish upon, what is to be the fate of all those, who, today, happen to live upon the land, though not belonging to the Hindu Race, Religion and Culture?" उनके साथ आप क्या करेंगे? तो गोलवलकर साहब बताते हैं - यह उन्ही की किताब का है, मैं इसे authenticate भी कर दूंगा, उसमें कोई परेशानी नही है - "At the outset, we must bear in mind that so far as 'nation' is concerned, all those, who fall outside the five-fold

†Transliteration in Urdu script.

limits of that idea, can have no place in the national life, unless they abandon their differences, adopt the religion, culture and language of the Nation and completely merge themselves in the National Race." यह है कार्यक्रम, यह आज का नही है, बहुत पुराना कार्यक्रम है, एक खास विचार के लोगों का, हिन्दुस्तान के अल्पसंख्यकों के साथ वे सत्ता में आने के बाद किस तरीके का व्यवहार करेंगे - 1939 में गोलवलकर साहब ने इस बात को लिख दिया था। ...**(समय की घंटी)**... सर, मैं एक दूसरी बात कहना चाहता हूं।

جناب جاوید علی خان: یہ کہا گیا کہ اس قانون سے اس دیش کے مسلمانوں کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ کیوں صاحب، ہم اس دیش کے ناگرک نہیں ہیں، مسلمان اس دیش کے باشندے نہیں ہیں؟ دیش کے پریمبل کو زخمی کر دیا جائے، اس دیش کے آرٹیکلس، دفعات کو زخمی کر دیا جائے اور سنودھان کا جو سیکولر فاؤنڈیشن ہے، اس کی جڑوں کو ہلا دیا جائے اور پھر کہو کہ اس قانون سے مسلمانوں کا کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ اس لئے مسلمانوں، تم اپنے گھر میں رہو – کیا ہم دو نمبر کے شہری ہیں؟ کیا مسلمان دوسرے درجے کے ناگرک ہیں؟ یہ دوسرے درجے کے ناگرک ہونے کی بات کے سمبندھ میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں، سر، کیوں کہ آپ ودوان ہیں اور چیزوں کو سمجھتے ہیں – ایک کتاب ہے 'We or Our Nationhood Defined' by Shri M.S. Golwalkar. یہ کتاب 1939 میں لکھی گئی تھی۔ گولوالکر صاحب جب اس میں پانچواں چیپٹر لکھتے ہیں تو اس میں ویاکھیہ کرتے ہیں کہ اس دیش میں دوسرے لوگوں کی، جو ہندوؤں کے علاوہ ہوں گے، ان کی کیا استھتی ہوگی۔ وہ خود ہی سوال پوچھتے ہیں - "If, as is indisputably proved, Hindustan is the land of the Hindus and is the terra firma for the Hindu nation alone to flourish upon, what is to be the fate of all those, who, today, happen to live upon the land, though not belonging to the Hindu Race, Religion and Culture?" تو ان کے ساتھ آپ کیا کریں گے؟ تو گولوالکر صاحب بتاتے ہیں۔ یہ انہیں کی کتاب کا ہے، میں اسے authenticate بھی کر

†Transliteration in Urdu script.

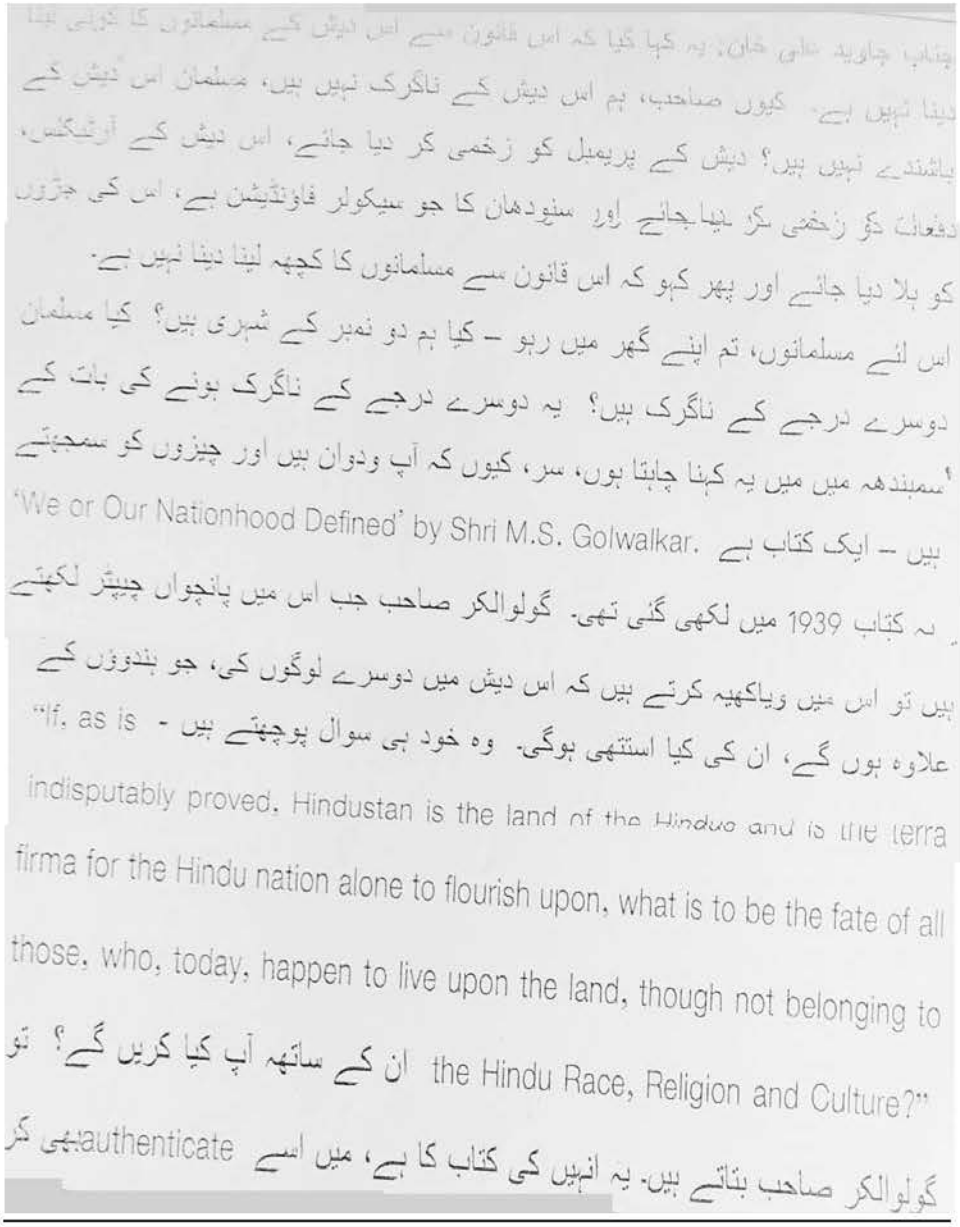

"At the outset, we must bear in mind that دوں گا، اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ so far as 'nation' is concerned, all those, who fall outside the five-fold limits of that idea, can have no place in the national life, unless they abandon their differences, adopt the religion, culture and language of the Nation and یہ ہے کارنے کرم، یہ آج completely merge themselves in the National Race." کا نہیں ہے، بہت پرانا کارنے کرم ہے، ایک خاص وچار کے لوگوں کا، ہندوستان کی اقلیتوں کے ساتھہ وہ ستّہ میں آنے کے بعد کس طریقے کا ویوہار کریں گے – 1939 میں گولوالکر صاحب نے اس بات کو لکھہ دیا تھا ...(وقت کی گھنٹی)... سر، میں ایک دوسری بات کہنا چاہتا ہوں۔

श्री उपसभापति: अब समाप्त करें।

श्री जावेद अली खान: सर, आज थोड़ा सा liberal हो जाइए।

†جناب جاوید علی خان : سر، آج تھوڑا سا لبرل ہو جائیے۔

श्री उपसभापति: मैं liberal हूं। आपको बताया है कि 6 घंटे का समय है, उसमें हमें conclude करना है। अब आप जल्दी समाप्त करें, ताकि मैं अगले स्पीकर को बुलाऊं।

श्री जावेद अली खान: दूसरी बात मैं आपको यह कहना चाहता हूं ...(**व्यवधान**)...

† جناب جاوید علی خان : دوسری بات میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں ...(مداخلت)...

एक माननीय सदस्या: सर, दो मिनट में समाप्त हो जाएगा।

श्री उपसभापति: कृपया सीट पर बैठकर निर्देश न दें।

श्री जावेद अली खान: कई बार यह कहा जा रहा है कि लाखों-करोड़ों लोगों को हम इस विधेयक के बाद नागरिकता देंगे। कितने लोग नागरिकता मांग रहे हैं - उनकी संख्या 35 हज़ार है। मैं यह जानना चाहता हूं कि जब आप इस Act में यह लिख रहे हैं कि 31 दिसम्बर, 2014 के पहले जो आया, उसको हम नागरिक मान लेंगे, तो माननीय उपसभापति जी, मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या कोई इलहाम हुआ है या किसी गुप्तचर संस्था की रिपोर्ट आयी है कि 31 दिसम्बर, 2014 के बाद वहां धार्मिक प्रताड़ना बंद हो गयी है? क्या वहां के States secular हो गये हैं, अब वहां कोई प्रताड़ना नही हो रही है? अगर आप वाकई धार्मिक अल्पसंख्यकों को इन धर्मशासित राज्यों की सहायता देना चाहते हैं, ...(**समय की घंटी**)... मदद देना चाहते हैं तो इसको open-ended रखिए।

†Transliteration in Urdu script.

†**جناب جاوید علی خان :** کئی بار یہ کہا جا رہا ہے کہ لاکھوں کروڑوں لوگوں کو ہم اس ودھیک کے بعد ناگرکتا دیں گے۔ کتنے لوگ ناگرکتا مانگ رہے ہیں۔ ان کی تعداد 35 ہزار ہے۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جب آپ اس ایکٹ میں یہ لکھہ رہے ہیں کہ 31 دسمبر، 2014 کے پہلے جو آیا، اس کو ہم ناگرک مان لیں گے، تو مانّنے اپ سبھا پتی جی، میں سرکار سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا کوئی الہام ہوا ہے یا کسی خفیہ ایجنسی کی رپورٹ آئی ہے کہ 31 دسمبر 2014 کے بعد وہاں دھارمک پرتاڑنا بند ہو گئی ہے؟ کیا وہاں کے اسٹیٹس سیکولر ہو گئے ہیں، اب وہاں کوئی پرتاڑنا نہیں ہو رہی ہے؟ اگر آپ واقعی دھارمک اقلیتوں کو ان دھرم شاست راجیوں کی سہائتہ دینا چاہتے ہیں ---(وقت کی گھنٹی)--- مدد دینا چاہتے ہیں تو اس کو اوپن-اینڈڈ رکھئے۔

श्री उपसभापति: धन्यवाद, जावेद अली खान जी।

श्री जावेद अली खान: सर, conclude करते हुए आखिरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि सब इस बिल का समर्थन करते, अगर आप अपनी राजनैतिक महत्वाकांक्षा को पूरा करने से थोड़ा पीछे हट जाएं और सिर्फ दो amendments कर दें कि पाकिस्तान, बंगलादेश और अफगानिस्तान की जगह आप 'neighbouring conutries' लिख दें और हिन्दू, सिख वगैरह गरह जो लिखा है, इसकी जगह 'religous minority' लिख दें तो बड़े शानदार तरीके से यह बिल पास हो जाता। ...**(समय की घंटी)**...

†**جناب جاوید علی خان :** سر، کنکلوڈ کرتے ہوئے آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سب اس بل کا سمرتھن کرتے، اگر آپ اپنی راجنیتک مہتّو کانشا کو پورا کرنے سے تھوڑا پیچھے ہٹ جائیں اور صرف دو امینڈمینٹس پر دیں کہ پاکستان، بنگلہ دیش اور افغانستان کی جگہ آپ 'نیبرنگ کنٹریز' لکھہ دیں اور ہندو، سکھہ وغیرہ جو لکھا ہے، اس کی جگہ 'ریلیجئن مائنارٹی' لکھہ دیں تو بڑے شاندار طریقے سے یہ بل پاس ہو جاتا ---(وقت کی گھنٹی)---

श्री उपसभापति: धन्यवाद। श्री राम चन्द्र प्रसाद सिंह ।

श्री जावेद अली खान: लेकिन क्योंकि करनी राजनीति है, तो राजनीतिक लाभ की वजह से आप यह सब काम कर रहे हैं, बहुत-बहुत धन्यवाद।

†**جناب جاوید علی خان :** لیکن کیوں کہ کرنی راجنیتی ہے، تو راجنیتک لابھہ کی وجہ سے آپ یہ سب کام کر رہے ہیں، بہت بہت دھنیواد۔

श्री उपसभापति: श्री राम चन्द्र प्रसाद सिंह।

श्री राम चन्द्र प्रसाद सिंह (बिहार): उपसभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। मैं एक तरह से बहुत ही विस्मय की स्थिति में था कि बिल

†Transliteration in Urdu script.

[श्री राम चन्द्र प्रसाद सिंह]

किस चीज़ पर है और चर्चा किन-किन चीज़ों की हो गयी है। यह बिल बहुत ही स्पष्ट है। जावेद अली खान साहब कह रहे थे कि जो तीन हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, वहां की जो religious minorities हैं, जिनके साथ religion के आधार पर persecution हुआ है और उन्होंने हमारे देश में आकर शरण ली हुई है, उनको नागरिकता देने की व्यवस्था है। सीधे-सीधे इतना ही है, लेकिन बातें क्या हो रही हैं? बात हो रही है कि हिंदुस्तान में जो हमारे अल्पसंख्यक समाज के भाई लोग हैं, उनके बारे में चर्चा हो रही है और हमारे साथी चर्चा क्या कर रहे हैं कि साहब Preamble का violation हो रहा है। सब बड़े-बड़े वकील हैं, लेकिन हम लोग भी पढ़े-लिखे लोग हैं। हमने Preamble में पढ़ा है, उसमें लिखा हुआ है कि किसको दिया जाएगा, जो सिटिज़न है। यह तो सिटिज़न बिल की भी बात हो रही है। आनन्द शर्मा जी आर्टिकल 5 की बात कह रहे थे। आर्टिकल 15, सिर्फ और सिर्फ जो हिंदुस्तान का नागरिक है, वह ही उसको avail करता है। आर्टिकल 14 की बात है, तो उसमें सब जानते हैं कि reasonable classification जो है, जिसमें intelligible differentia है, जो substantial distinction है, उसका बहुत ही स्पष्ट मतलब है और उसी के आधार पर देश में बहुत कानून बने हैं और यह कानून बना। इसलिए हमारी पार्टी इसका समर्थन करती है। हमारे देरेक ओब्राईन साहब ने morality की बात कही। मैं जरा उस पर आना चाहंगा। मैं भी इतिहास का विद्यार्थी रहा हूं। वे बात कर रहे थे - नाज़ी का, जर्मनी का, तो जो Concentration Camp था, वह उसी देश में था। कोई बाहर से लोग नही आ रहे थे और यहां ऐसी कोई बात हो ही नही सकती। हमारा देश एक रिपब्लिक है। हमारे नड्डा साहब जो figure दे रहे थे, आप figure को देखिए न। हमारे देश में जितने भी नागरिक हैं, सबको समान अधिकार हैं, सबको आगे बढ़ने का अधिकार है और यही कारण है कि इस देश में एक नही तीन-तीन राष्ट्रपति माइनॉरिटी समाज से हुए और चीफ़ भी जस्टिस हुए। आप बगल के देशों में देख लीजिए, तो हिंदुस्तान के लोगों के मन में कही से भी भय क्यों डालते हैं? हिंदुस्तान की अपनी एक संस्कृति रही है। आप हमारे यहां किस चीज़ से डर रहे हैं? बार-बार बोल रहे हैं, चर्चा कर देते हैं, NRC. आप C से जरा आगे भी बढ़िये। C के आगे D होता है, तो हम लोगों का एजेंडा होगा - National Register of Development और development किस के लिए करेंगे, जो इस देश के नागरिक हैं। जो इस देश का नागरिक नही है, उस के लिए क्या development करना है। जहां तक morality की बात है, देरेक ओब्राईन साहब, आपने एक बात कही, उसको बुरा मत मानिएगा। आपकी नेता बहुत संघर्षशील हैं, बहुत agitation करती हैं, लेकिन हम बिहार के लोग उनका एक agitation बराबर याद रखते हैं। वह तब, जब हमारे हाज़ीपुर में रेलवे का ज़ोन बन रहा था और मुगलसराय को लिया जा रहा था, तो आपकी नेता क्या कर रही थी? आप जरा देख लीजिए ईस्टर्न रेलवे, कोलकाता में आपका कितना ज़ोन था। जब वहां पर आ रहा था, कितना विरोध किया गया। हमारे ग्रामीण इलाके में जो स्टेशन होते थे, वहां कौन कर्मचारी होते थे? यहां पर सभी लोग अपने लिए और अपने प्रदेश के लिए agitation करते हैं, करना चाहिए।

दूसरी बात, आपको मैं बता दूं कि आज 14 साल से, बीच में 20 महीने छोड़ दीजिए, बिहार में एनडीए की सरकार है, आप जाकर देख लीजिए, पता कर लीजिए और खासकर अल्पसंख्यक इलाकों में जाइए, वे यही बोलेंगे कि यहां नीतीश बाबू के नेतृत्व में एनडीए सरकार काम करे और आगे भी काम करती रहे। वे ऐसा क्यों बोलते हैं? इस संबंध में मैं आपके सामने दो-तीन बातें रख देना चाहता हूं, चूंकि आपने हमारी morality को question किया है। क्या आप मदरसे के बारे में जानते हैं? 1924 में मदरसे का institution शुरू हुआ। 2005 में हमारी सरकार बनी, जब हम लोग एनडीए में साथ में आए। आपने 81 सालों में सिर्फ 1,128 मदरसे बनाए और एनडीए की सरकार ने एक कलम से एक बार में 2,460 मदरसे बनाए। जो मदरसे के टीचर थे, आपकी सरकारें वहां थी, कितने पैसे देते थे - दो से तीन हजार रुपये। आज आप देख लीजिए एनडीए की सरकार है, वहां सातवां वेतन आयोग दे रहे हैं, 50 से 60 हजार रुपये। वहां पर क्या था, आप किस प्रकार से डराते थे? उनके जो पूरे के पूरे कब्रिस्तान थे, उनका क्या हाल बना रखा था? महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि आप पता कर लीजिए कि 6,000 से ज्यादा कब्रिस्तानों की घेराबन्दी कराई जा चुकी है। जो कब्रिस्तानों की सुरक्षा करे, वह तो कम्युनल और जो सुरक्षा न करे, वह आपकी नजर में हो गया सेक्युलर। आप यह भी जान लीजिए कि ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करना चाहता हूं कि कृपया वे अपनी सीटों पर बैठकर न बोलें।

श्री राम चन्द्र प्रसाद सिंह: आप यह भी जान लीजिए, morality की बात हो रही है, जो पहले की सरकारें थी, उनका अल्पसंख्यक कल्याण का बजट देख लीजिए। उनका बजट उस समय मात्र 2.75 करोड़ रुपए था, जो अब बढ़कर 900 करोड़ से ज्यादा है। हमें क्या morality अदेखनी है। वहां हमारी एनडीए की सरकार 14 साल से चल रही है, एक भी घटना बता दीजिए जहां पर कि जाति या धर्म के नाम पर कोई इस तरह की बात हुई हो?

महोदय, अभी BPSC का रिज़ल्ट देखिए और दो टर्म पहले का जो हुआ है, उसके बारे में पता कर लीजिए कि हमारे कितने अल्पसंख्यक बच्चे सलेक्ट हुए हैं? मैं एक और बात बताना चाहता हूं कि केन्द्र में भी जरा पता कर लीजिए कि कितने बच्चे सलेक्ट हुए हैं? मैं वर्ष 1984 के IAS के बैच का अफसर रहा हूं, उस समय मेरे बैच में 146 लोग सलेक्ट हुए। मैं किसी धर्म का नाम नही लेना चाहता था, लेकिन यहां लेना पड़ रहा है कि उस बैच में मात्र एक मुस्लिम IAS में सलेक्ट हुआ था। अब आप वर्ष 2014, 2015, 20116, 2017 और वर्ष 2018 के बैचेज़ के रिजल्ट आ गए हैं, आप पता कर लीजिए कि कितने बच्चे सलेक्ट हुए हैं। फिर क्यों आप इस देश को डरा रहे हैं कि यहां पर उनके लिए कोई जगह नही है? उनके लिए पूरी जगह है। उनके पास मेरिट है, तो वे किसी भी स्थान को प्राप्त कर सकते हैं।

महोदय, आज युनाइटेड नेशन्स में कश्मीर का मुद्दा उठता है, तो वहां हमारा केस कौन प्लीड करता है? किस समाज का वह अफसर है, जो वहां हमारा केस प्लीड करता

[श्री राम चन्द्र प्रसाद सिंह]

है? इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हम लोग इस देश में किस तरह की चर्चा कर रहे हैं और इससे क्या narrative बना रहे हैं? Narrative यह होना चाहिए कि आज हमारा देश कैसे 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी हो। यह एजेंडा होना चाहिए और इसके लिए देश के पूरे के पूरे समाज में किस तरह से भाईचारा रहे, लोगों में बंधुत्व रहे और सब लोग आगे मिलकर के चलें, इससे ही हमारा देश आगे बढ़ेगा।

महोदय, मैं पुनः कहना चाहता हूं कि इस बिल में ऐसी कोई बात नही है जिससे किसी को कोई नुकसान पहुंचे। मैं सबको आश्वस्त करना चाहता हूं और मैं तो बिहार से हूं, मैं जरूर इस बात को सुनिश्चित कराना चाहूंगा कि इस देश में धर्म के नाम पर किसी के साथ, किसी भी प्रकार का अन्याय होगा, तो हम लोग क्या कोई पीछे रहने वाले हैं, कभी नही। यही इस देश की खासियत है और इस देश का बहुत बड़ा गौरवशाली इतिहास है। हम सब लोगों को मिलकर चलना है और इस देश के जो 130 करोड़ लोग हैं, वे सब हिन्दुस्तानी हैं और सबको बराबर का अधिकार है, सबको आगे बढ़ने का बराबर का अधिकार है और सबको बराबर का हक मिलेगा। इन्ही शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, बहुत-बहुत धन्यवाद।

DR. K. KESHAVA RAO (Andhra Pradesh): Sir, after Mr. Derek, I thought Ram Chandra Prasad ji was bringing us back on the track to speak on the Bill instead of speaking on many other things which he complained or alleged that we were doing instead of speaking on the Bill. But strangely I saw that he was himself talking about graveyards to the NRC becoming the NRD and what not. Let us understand that this is an emotive issue.

I will start with the high moral ground which the Home Minister took while he was speaking on the Bill. The moral ground he took was that they were elected to rule. Yes, nobody doubts that they have come back to power. They can administer and they can govern. But they can't break the Constitution. Because that is the basic structure. Mr. Derek rightly reminded them about it. You have the right to administer. You have the right to govern. You have the right to sit on the benches right there. But remember with only 40 per cent people voting on your side. When you are trying to talk about the people and in the name of the people, it should be nearly about hundred per cent. That is what you call national consensus. Whenever an issue comes which concerns the nation, which concerns our Constitution, which concerns our ethos, which concerns our ideals and which concerns our philosophy, we go to seek the help of other people and seek their views also. That is what exactly the moment today is all about.

We have a Bill before us which is challenging the very idea of India. I am not trying to quote all the things. Sri Aurobindo spoke about spiritual India. The idea of India is something which is more than what we really see in the print of the Constitution. Be it pluralism or be it inclusiveness or we may call it civilisational ethos or call it our commitment to peace, harmony and brotherhood, all of this our founding fathers thought of when they were writing this Constitution. We cannot belittle the Preamble. The Preamble is the very basis on which we have built the edifice. The Preamble that we have taken up is based on Vasudhaiva Kutumbakam as we all know. It is universalism. I am not trying to quote Vivekananda or Rabindranath Tagore or Mahatma Gandhi's saying that let the wind flow from all sides or Vivekananda's saying that it is an ocean of humanity. All these are known to you. I will not repeat them because these are repeatedly said here. So, all these great saints and seers, whom you remember day and night, have reminded you one kind of ethos and one kind of civilization ethos. I call them civilization ethos because your developmental civilization ethos were based on that. When we are trying to touch them and when there is an onslaught on them, then we really search our own conscience to see that it does not bleed. Sir, to safeguard our own selves and our own identity as Indians, we talk about this. So, today, this Bill has two faces. One is essentially Constitution and constitutional legality and the other is constitutional morality. Constitutional morality comes when you try to understand your own Constitution, the words and the laws which you have brought in. When you look into the Bill, you see that it negates every ideal and every idea of justice that undercomes the Constitution. Right next to you, Shri Prasad, an Advocate-General is sitting. Please ask him that whenever we interpret a law, we always interpret the law by the idea from where that emanates. This idea of India, this idea of pluralism, this idea of inclusiveness and this idea of love and peace are there. So, let us keep that in mind.

Now, the second thing our Home Minister said is, after all, this country was divided on the basis of religion; so, why talk about religion bias and why have a grouse over religion. I have my own theory. I don't believe that this country was divided at all on religion. There was a big country — British India and also independent Princely States. Some sections wanted to secede from it and we allowed them to secede. They have seceded and they have become a nation. It became a theocratic state and wanted Islam as its State religion. We need not. We said 'no', saying that we don't agree to that; we are secular. We stand by the ideals on which we were born and on which we fought for our freedom. So, the point is, to say

[Dr. K. Keshva Rao]

that the country was divided on the basis of religion and we have no right to talk about religion at this particular point of time should be negated and it should be rejected. That is my argument. Then, what exactly is this Constitution Amendment Bill all about? I would not like to quote but there is the case of Kesavananda Bharati. They have said that secularism is the basic structure. I would rather go to another very important judgment — Valsamma Paul vs. University of Cochin. There is a very interesting thing. I would quote one sentence from the judgement. Pluralism is the keynote of Indian culture. Pluralism is the keynote to Indian culture and and religious tolerance is the bedrock of Indian secularism. It is based on the belief that all religions are equally good and efficacious pathways to perfection or God-realisation. This is the judgment coming from the Supreme Court which says that this should be the basis for your laws. Now, we have a Bill here for citizenship. Shri Ram Chandra Prasad Singh was right when he asked as to where discrimination in this is. We oppose this Bill because it is marginalising the Muslims. We oppose this Bill because it is anti-Muslims. Why? It has to be read along with NRC. You can't just separate it saying this is something else and that is something else. Its lengthening shadows are on NRC. Go and see there. I don't want to go into details because it has been detailed by Shri Derek and others as far as Assam situation is concerned. Today, why is the Assam situation getting worse? It is because the fear is that it will make somebody a citizen and somebody else a non-citizen within one million. Immunisation to those people who are Hindus even if they are illegal immigrants and if they are Muslims and they go out. This kind of discrimination! That means we have some kind of, what we call, multifaceted, multidimensional, multiple grounds for citizenship, which is not correct at all. That is why Dr. Ambedkarji said that the one Clause that proved a headache to the entire members of the Constituent Assembly is the Citizenship Clause, Articles 5 to 11. He said that they had a headache as everything had to be read into it because tomorrow they were going to become the torch-bearers of the nation. ...*(Time-bell rings)*... That is why, let us not take it.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Keshava Raoji, please conclude now.

DR. K. KESHAVA RAO: Sir, as I said, we are trying to say, I am just coming to only answering the questions, that we totally agree with you that there is a persecution. You must help them, take them, give them more relief. Nobody has any objection but here you are dividing the migrants as such. What you are trying to

do is this. A migrant, who is a Hindu, has all the relief from you. If it is some Muslim, then, 'no'. And your reason or rationale is, it is because they are coming from a State which is an Islamic State.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Dr. Keshava Rao, please conclude now. Already, eight minutes are over.

DR. K. KESHAVA RAO: Sir, I will complete this sentence.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude.

DR. K. KESHAVA RAO: They are from theocratic society. But, there is Sri Lanka. There are religious persecutions in Pakistan, Ahmadiyyas are there. Rohingyas are there in Myanmar and Sri Lankan Tamils are there who are already there in Tamil Nadu. So, the question today is this. The kind of discrimination we clearly see in the Bill is breaking the very Constitution, our ethos, our ideals, all that we have stood for. I am a senior Member here. I think, all that we have stood for, the onslaught is so severe that there would be no Constitution as such for me to rely on or fall back upon. So, thank you very much, Sir. I tell you that this Bill should be withdrawn and not sent here or there. Have a second look because let us not bring a new ugly dimension to our thinking, our civilizational ethos wherein we are dividing the nation into two.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you. Shri T.K. Rangarajan, your Party has seven minutes and two speakers, so, you decide.

SHRI T.K. RANGARAJAN: Sir, the Citizenship (Amendment) Bill is anti-Constitution, illegal and immoral. On behalf of the Communist Party of India (Marxist), I oppose the Bill tooth and nail.

It was sent to a Joint Parliamentary Committee and was there for three years. It was a farce. Shri Derek was also a Member of that. They never visited either Bengal, Tripura, Jharkhand, Odisha or Andamans. They have never visited. The CAB's stated objective - to give shelter and protection to persecuted minorities - is laudable. The text of the Bill, however, not only undermines that objective but also rends the plural fabric of the Indian Constitution. In its careful listing of protected communities, it explicitly and intentionally leave out Muslims. The message is, discrimination, exclusion and second class citizenship based on religion. This justification is faulty. Pakistan, Bangladesh and Afghanistan are Muslim majority

[Shri T.K. Rangarajan]

countries, by definition, where Muslims cannot be persecuted. This is false. The Home Minister must understand that it is false. The Ahmadiyya community in Pakistan has been subjected to continuous discrimination and violence. They have come here. Now, you also exclude them. There are a number of countries surrounding India that have unleashed terrible violence upon minorities, say, against the Rohingya Muslim minorities, ethnic cleansing and genocide in Myanmar. Sri Lanka does the same. It is a Buddhist State, please remember. How the Sri Lankan Government treats Tamils? Why our Prime Minister or Foreign Minister go there for a discussion when new President was elected? Why are the Tamils afraid there? In 24 districts in Tamil Nadu, 2,000 camps are there for the past 35 years. Another 3-4 camps are in Odisha. They have their own grandchildren there. That is a pathetic thing. Still, they are in the camps. Sir, I want citizenship to everybody. People are suffering. That is why, my amendment in this Bill is for all neighbouring countries and there should not be any religion. Sir, the Citizenship (Amendment) Bill is based on religion. This is clearly unconstitutional as religion can never form the basis of the State of a nation. Whenever you are abroad you also call, "वसुधैव कुटुम्बम्", but when you are in India you are narrowed down as majority communalist. This is your basic politics that ultimately ruin the country and its secular credentials.

Sir, I would like to draw your attention that in S.R. Bommai's case, the Constitution Bench of the Supreme Court held that secularism is part of the basic structure of the Constitution. The court held, "Encroachment of religion into secular activities is strictly prohibited". This is the Judgement. The court also said that the state has a duty to ensure secularism by law and by Executive Order. Any policy of law, that is, based on religion amount to recognizing religion as part of political governance, which are expressly prohibited by the Constitution. This is the Supreme Court Judgement. By this Amendment, Parliament is compelling the state to do the same thing which is prohibited by the Constitution.

Sir, finally, I would like to ask you one thing. Today in Pakistan, Hindus are 1.6 per cent, that is, their population is 3.6 million.

Bangladesh is the third largest Hindu State. Sir, the world knows that Bangladesh is the third largest Hindu living State, after India and Nepal, where 17 million Hindus are still there, according to 2015 Census.

In Sri Lanka, 25,54,606 Hindus are there. After passing this Amendment, suppose you pass this Amendment, suppose you make this a law, what will be its repercussions in these countries on minorities and who will be responsible? This is my question to you. So, this is a very serious thing. That is why my Communist Party of India (Marxist) opposes this. Everybody call you as Chanakya. There are a lot of examples in Mahabharata and Ramayana. I don't want to show it. There are a lot of stories in Tamil. But, in conclusion, what I want to say is that this time you are going to a "विनाशकाले विपरीत बुद्धि". So, don't spoil the country, and don't spoil the Constitution. That is my request.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: So, two minutes are left for the other speaker in your party.

SHRI T.K. RANGARAJAN: There is one minute.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Two minutes only. Now, Shri Tiruchi Siva; you have seven minutes to speak. Two speakers are there, so you please speak accordingly.

SHRI TIRUCHI SIVA: Mr. Deputy Chairman, Sir, I, today, as a Member of Parliament have to perform my duty which is to protect the basic tenets of the Constitution; my Constitution, Sir, I am very firm, my Constitution. It is because the understanding of the Government's Constitution is entirely different from mine. Sir, whoever believes in pluralism, in an egalitarian society and a democratic India where religion is not a barrier to condemn some individuals perpetually as second-class citizens. I, as a Member of the DMK Party, which is working on the same basic principles, strongly oppose this Bill. This Bill seeks to provide citizenship to some illegal migrants from three countries, that is, Pakistan, Bangladesh and Afghanistan. What is citizenship? Citizenship is a legal right for a person belonging to a particular country. In other words, citizenship bestows upon individuals, membership to a national, political community. In short, national citizenship means an essential and enduring feature of modern life in terms of politics and elections, welfare and benefits and all round integration. Now, Sir, there are four questions that I would like to pose to the Government to make things clear. Everyone has pointed out that it is unconstitutional and when it is being scrutinised by the Supreme Court, naturally, everyone knows, it would not stand the scrutiny of the

[Shri Tiruchi Siva]

Supreme Court. It is against Article 14 of our Constitution, which ensures every citizen, equality before law, no one should be discriminated against, and so also the Preamble, secularity is very clear. It is against secularism. Sir, these are my four pointed questions. Number one: Why have only these three countries been selected? What is the rationale behind it? In the Statement of Objects and Reasons, it says that millions of citizens of undivided India belonging to various faiths were staying in the said areas of Pakistan and Bangladesh when India was partitioned in 1947. Where comes Afghanistan here? It was not in the undivided part of India. So Afghanistan comes in. You may call it, as the Home Minister in his introductory speech said, 'the neighbouring countries'. Taking that into consideration, I would like to know why you have spared other neighbouring countries. When Afghanistan has been included, why not Bhutan? Why not Myanmar? Why not Sri Lanka? All these countries have to be included. Why have you selected three counties which have majority in Muslim population? And you say that minorities have been persecuted from these three countries. Again it has been justified that these countries have a State religion. Yes, our founding fathers clearly said that India does not have a State religion because the doors are open to everyone, irrespective of caste, creed or religion. But, these three countries have. Of course, Sri Lanka has a State religion, *i.e,* Buddhism. Bhutan is having a State religion. For your kind information, I would like to say that the Christians pray in their houses in Bhutan. And if they want to pray in churches, they are coming to India. Are you going to discard them? Are you not going to include them? So also the Rohingyas from Myanmar. They are also persecuted; a section of the Muslims in Pakistan — the Shias, and so also the Ahmadis in Bangladesh and Hazaras in Afghanistan. Will they not be considered as human beings? These are the very pointed questions that we would like to ask. Why you cherry picked these three countries and why only on the basis of religious reasons and excluded only one religion? It is actually polarised. We feel very strongly, whatever your attempts are in the recent days, are pointing towards one particular religion in this country. A sense of apprehension has cropped into millions of Muslims in our country. Where will they go? They have also been persecuted. I would like to ask, if they have not been included in this naturalisation process, will they go back to Pakistan, Bangladesh or Afghanistan and plead that they have been persecuted in India and are coming there, or, will they be put in

detention cells? This is my very simple question. Why all these things? From Sri Lanka, more than a lakh of people have come here since 1948 because when the Citizenship Act was enacted, people were forced to come out. They were not able to enrol themselves as citizens. After Black July in 1983, people came in large numbers and, very precisely, I would like to say that for more than 30 years, they have been living here. They study medicine. They are not able to practice. They do anything but they are not entitled to be the legal citizens in this country. You are coming forward to naturalise some of the citizens. The Citizenship Act of 1955 completely provides for whoever should not be a citizen of this country. What happened since 1920, 1946; leave alone all these things. The Government notifications of 2015 and 2016 gave some exceptions and that has come as a Bill and now it is being discussed. Sir, I am afraid, if this is passed by way of majority that you are having now, that will be a blow to our secularism. When India and Pakistan were partitioned, when Muhammad Ali Jinnah extended invitation that all Muslims should come to Pakistan, Muslims have assured, "Yes, we are Muslims, but India is our nation" and they stayed here. Kindly think about those Muslims. Should we not honour their patriotism? So also, so many persecuted, now have come here. A section of the Muslims are still being persecuted; the Christians are persecuted in Bhutan, and the Tamils in Sri Lanka are persecuted, and are in Tamil Nadu. What are you going to do for them? We need justification. That is all. When you have come forward to naturalise and give citizenship to some of those people, who have been persecuted in some countries, based on religion, let it not be confined to religion only. On ethnic reasons, on linguistic reasons, if they are banished or persecuted, they should also be considered. I humbly convey to the hon. Home Minister one thing. He, in the Lok Sabha said, 'we have got a mandate.' Yes, you have a mandate. But, that mandate is to justify all the citizens of this country, not to segregate one portion, and feel them agonised, pained, anguished, and victimized.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you.

SHRI TIRUCHI SIVA: I would like to again say it is high time, and I would like to quote Arignar Anna, "Carry on, but remember, you have to hold the reins of your speeding horse, or else, it would upset the applecart." Thank you very much.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Tiruchi Siva,, you have taken the entire time of your party. Now, Shri Swapan Dasgupta.

SHRI SWAPAN DASGUPTA (Nominated): Mr. Deputy Chairman, Sir, since we have been told that personal stories are the best stories, let me tell you a story, and it concerns Choudhary Devi Lal. Choudhary Devi Lal used to say, आदमी की पहचान उनके वीपीओ यानी विलेज पोस्ट ऑफिस से होती है। So, my retort to that was, I have no pehchhan. क्योंकि हमार कोई विलेज पोस्ट ऑफिस नहीं है। हमारा जो विलेज पोस्ट ऑफिस था, वह अब पाकिस्तान में चला गया और पाकिस्तान में हमारी community के जो आदमी थे, all of them have been tuffed out. इसलिए हमारी कोई विलेज पहचान नहीं है। Sir, I think, it is very important to realize that what we are talking today, centres on two different things. One is, what is a refugee, and what is a migrant? These are categories which are distinguished in all forms of academic and other scholarly studies. The Geneva Convention of 1951, Sir, has defined very clearly what a refugee is, and I quote: "A refugee is a person, who, owing to a well-founded fear, being persecuted for reasons of race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion, is outside the country of his nationality, and is unable, or, owing to such fear, is unwilling to avail himself of the protection of that country." Sir, what this Bill has done is that it has taken this principle and put it into a specific context of India. That is what it has done. It has done nothing exceptional. It has really followed international norms. What my friends, who are objecting to this, want to say is that there are no living people; there were no communities, who actually exited from Pakistan or from Bangladesh. ...*(Time-bell rings)*... That Bangladesi Hindu. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: There are two more speakers from that Group.

SHRI SWAPAN DASGUPTA: Sir, I am not a group.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no; it is not a group. Four minutes' time is allocated for three people. No, no. I cannot give more time than that. You have already taken two minutes.

SHRI SWAPAN DASGUPTA: Sir, an attempt is being made to make the entire Bengali Hindus, who came from East Bengal, invisible citizens. They have an identity, and that identity must be recognised, and this is what I think, is very important. And I just want to tell them that this attempt to actually say that you do not exist, that you did not actually suffer from any specific form of persecution, you cannot do that.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you.

SHRI SWAPAN DASGUPTA: Sir, I would also register that it is completely unfair on a subject on which it is very important that we should get some. ...*(Interruptions)*... I register my protest.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you. I must tell Swapan Dasguptaji, there are three Nominated Members, and four minutes' time is there. So, I have to follow the time. You have taken three minutes.

श्री बिश्वजीत दैमारी (असम): सर, मैंने बीजेपी की तरफ से समय माँगा है।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri Biswajit Daimary, you have three minutes only.

श्री बिश्वजीत दैमारी: सर, आप बीजेपी का समय दीजिए।

श्री उपसभापति: हमारे पास नही है। Speak only for three minutes, please.

श्री बिश्वजीत दैमारी: सर, बीजेपी को जो समय allotted है, मैंने उसमें से समय माँगा है।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Unless they express in writing, I can't give more time. Let there be no arguments, please. Please conclude within three minutes.

श्री बिश्वजीत दैमारी: सर, इस बिल को लेकर नॉर्थ-ईस्ट के स्थानीय लोगों में, indigenous लोगों में शंका है, उस शंका को लेकर प्रतिरोध भी चल रहा है। यहाँ हाउस में चाहे बिल पास हो न हो, लेकिन वे लोग वहाँ पर प्रतिरोध कर रहे हैं और सर, उसके कुछ रीज़ंस हैं। रीज़ंस ये हैं कि वहाँ जो विदेशी लोग migrate हुए हैं, उनकी वजह से वहाँ के लोकल लोगों का marginalization हो गया। इसी के कारण, वहाँ पर स्थानीय लोगों का संग्राम हुआ था, जिसमें 855 लोग शहीद हुए थे और उसके बाद, 1985 में केन्द्रीय सरकार के साथ एक समझौता हुआ था, जिस समझौते के अनुसार वहाँ के लोगों को संवैधानिक सुरक्षा देने के लिए केन्द्रीय सरकार की तरफ से कमिटमेंट दी गई थी। लेकिन आज 35 साल तक वह कमिटमेंट, कमिटमेंट ही रही, अब तक कुछ नही हुआ और इस कारण वहाँ के लोगों का विश्वास खो गया है और इसी कारण, उन्हें इस नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2019, पर शंका हो रही है। अगर यह लागू हो गया, तो बाहर के लोग जो शरणार्थी के रूप में आए हैं, वे यहाँ के सिटिज़न बन जाएंगे, तो इससे वहाँ के बाकी लोगों की क्या हालत होगी, यह डर वहाँ के लोगों में है। सर, वहाँ के लोगों की जो कला, संस्कृति, भाषा है, वहाँ का जो व्यवहार, भावना है, वह अलग है। हमारे देश की दूसरी

[श्री बिश्वजीत दैमारी]

जगह और वहाँ के लोगों के बीच में बहुत अंतर है। वे लोग किसी के साथ assimilate नही हो सकते हैं, क्योंकि हजारों सालों से वहाँ पर, वही लोग अपनी कला, संस्कृति और भाषा को लेकर जीवित हैं। सर, वहाँ महाभारत के समय से ही लोग हैं। महाभारत के जो evidence हैं, वे वहाँ पर हैं। आज यहाँ हमारे गृह मंत्री जी ने इस सिटिज़नशिप बिल के जरिए जो आश्वासन दिया है, मैं आशा करता हूँ कि यह आश्वासन ...**(समय की घंटी)**... सर, थोड़ा और बोलने दीजिए। जितनी जल्दी हो सके, वे इस आश्वासन को वास्तविकता में रूपांतरित करें।

श्री उपसभापति: अब आप कन्क्लूड कीजिए। बिश्वजीत दैमारी जी, चार मिनट हो चुके हैं।

श्री बिश्वजीत दैमारी: वह आश्वासन यह है कि वहाँ के लोगों की जो कला, संस्कृति और भाषा है और उनकी राजनीतिक सुरक्षा के लिए जो प्रावधान करने हैं, वे किए जाएँ। इसमें पॉपुलेशन का कोई रेश्यो नही है। वहाँ के स्थानीय लोगों के नाम पर, चाहे वहाँ हमारी पॉपुलेशन 30 परसेंट हो, 40 परसेंट हो, लेकिन वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ के लोगों के नियंत्रण में चले, इस प्रकार का प्रावधान करना चाहिए। इसमें आपको वे प्रावधान करने हैं, जो आप Assam Accord की धारा-छ: के अनुसार implement करना चाहते हैं। मैं आशा करता हूँ कि गृह मंत्री जी इस हाउस के जरिए पुन: वहाँ के लोगों को विश्वास दिलाएंगे और बाकी स्टेट्स के लिए उन्होंने जो व्यवस्था की है, जैसे 371 पर यह लागू नही होगा, आईएलपी एरिया में लागू नही होगा, Sixth Schedule में लागू नही होगा, इसके लिए मैं गृह मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ कि जिन लोगों को शंका थी, वहाँ बहुत सारी जगह को उन्होंने सुरक्षित रखा। इससे वहाँ के लोगों को आज के बाद विश्वास रहेगा और उनके विश्वास को कायम रखना हमारा काम होगा। मैं यही उम्मीद रखता हूँ और इस बिल का समर्थन करता हूँ।

SHRI BIRENDRA PRASAD BAISHYA (Assam): *

SHRI BIRENDRA PRASAD BAISHYA (Assam): * Thank you sir, I am going to speak in the house today at a very crucial time Assam is passing through. Assamese people are in fear today. Assam Gana Parishad is also in fear today. We may lose our own language and culture. Assamese language might face extinction forever. Sir, I am not being emotional while saying so. I would like to say this on the basis of some facts. Since the year 1836, for about 36 years Bengali was the

* English translation of the original speech delivered in Assamese.

state language in Assam. During the Congress rule in 1960, Assamese people started movement demanding for the recognition of Assamese language as the state language. Many people had to sacrifice their lives in this movement. Again in 1972, we had to resort to agitation demanding recognition of the Assamese language as medium of instruction in Assam.

Thus, despite facing so many hurdles Assamese language has been recognized as one of the best languages in the world. Sir, I am not saying anything against any language, neither am I saying something against any person, but, most of those people who are going to get citizenship as a result of passing the CAB, speak Bengali.

When these additional people would get citizenship in Assam, the very existence of Assamese language would be threatened. That's why I would like to tell the Hon'ble Home Minister that our Assamese people want the Assamese language to remain as the state language of Assam. I request the government that if need be, the constitution should be amended so as to make Assamese language as our state language forever.

Assam Accord is a historic agreement. Assam Accord was signed as a result of Assam agitation. But no step was taken to implement the Accord. Sir, you are aware that in the entire country those who came to India before 19th July, 1948 became Indian citizen. Those who came to India after 1948 would never get Indian citizenship. But our Assamese people are very liberal. We have accepted foreigners who entered our territory upto 1971. We can't take more burden of illegal migrants.

Sir, give me some time. I am speaking in the interest of Assam. This is my request. This is my humble request. At least today, allow me to speak in the interest of the people of Assam.

SHRI BIRENDRA PRASAD BAISHYA: Sir, one more important thing I would like tell you.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Birendraji, time is limited. So, you have to speak in three minutes only. Three minutes are over. I will give you one more minute.

SHRI BIRENDRA PRASAD BAISHYA: No, Sir, I will not be able to finish. ...*(Time-bell rings)*... Sir, we can't take even a single person as our citizen now. These additional people who are going to get Indian citizenship should be made to settle in other parts of the country and not in Assam. Hon'ble Home Minister Sir, you have given relief to many North Eastern States. You have provided Inner Line Permit. But Assam does not have Inner Line Permit. Please protect Assam. For protection of Assam please introduce Inner Line Permit. Clause 6 is the most important clause of Assam Accord. But no government implemented clause 6 of Assam Accord. The present government at the Centre has come forward to implement clause 6 of Assam Accord. I therefore request you, sir, to take steps to implement clause 6 of Assam Accord. Please take steps for the protection of rights of Assamese people over their land and natural resources.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Birendraji, please conclude. ...*(Time-bell rings)*... I will call the next speaker.

SHRI BIRENDRA PRASAD BAISHYA: Please take necessary steps for the protection of land rights of local Assamese people as your have done in Meghalaya, Mizoram, Nagaland etc.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude. You have already taken more time. ...*(Time-bell rings)*... Please conclude.

SHRI BIRENDRA PRASAD BAISHYA: Sir, lot of protests are going on in Assam. Hon'ble Home Minister sir, you must be having information about it. Lakhs of protesters are on the streets of Assam. Assam people are in fear. I therefore request you not to pass the Bill in a hasty manner. I would like to request the government to grant schedule tribe status to six communities of Assam.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude now or else I will be forced to call the next speaker. You have already taken more time.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you, please sit down. Shri Kapil Sibal.

SHRI BIRENDRA PRASAD BAISHYA: One minute, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no; now it will not go on record. Shri Kapil Sibal.

SHRI BIRENDRA PRASAD BAISHYA: One minute, Sir. Give me one minute, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I have limited time. You conclude in one minute.

SHRI BIRENDRA PRASAD BAISHYA: Therefore, six communities of Assam should be granted Schedule Tribes status.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you. Now, Shri P. Chidambaram.

SHRI P. CHIDAMBARAM (Maharashtra): Mr. Deputy Chairman, Sir, I will take less than ten minutes. My colleague, Mr. Sibal, will take the rest of the time.

Sir, we have a Citizenship Act in this country. It recognizes citizenship by birth, citizenship by descent, citizenship by registration, citizenship by naturalization and citizenship by incorporation of territory. These are universal principles. Now, this Government is introducing a new category called 'citizenship by arbitrary executive fiat' and asking this Parliament to support the Government in passing what is patently an unconstitutional law. My friends have spoken about it; others will speak about it.

We are elected representatives of the people. The Constitution has asked us, in the first instance, to judge the constitutionality of a Bill. We cannot pronounce on the constitutionality. But, we have a responsibility to pass what is constitutional. Not all of us are lawyers. In fact, not all of us should be lawyers. We should be from every walk of life. And, from every walk of life, we must bring our collective wisdom and commonsense to say is this constitutional or not. What are we doing in this House? What we did in the other House and what we are doing in this House is abdicating our primary responsibility in favour of another of the three entities/end organs of the Constitution. What we are doing is: You are pushing the issue to the lap of the Judges. Do you think it will stop here? It will not stop here. It will eventually go before the Judges. And, the Judges are respectable people. But, they are unelected Judges. Unelected Judges and unelected lawyers will ultimately decide what we do is constitutional or not! This is a slap on the face of Parliament. Parliamentarians are being asked to do something unconstitutional and then the baby is passed on to the judiciary and, in the judiciary, lawyers and Judges

[Shri P. Chidambaram]

will decide what you have done is constitutional or not. Knowing this is unconstitutional, I am afraid, this Government is ramming through this Bill in order to advance its Hindutva agenda. This is a sad day. Thankfully, we are not amending the Constitution; we are only making a law. And, I am absolutely confident and I am absolutely clear in my mind that this law will be struck-off.

Sir, I have a few questions and I wanted to know who in the Government found answers to these questions. If the Law Department has advised answers to these questions, please ask the hon. Home Minister to lay the opinion of the Law Ministry on the Table of the House. If it is a Home

Ministry itself, in its wisdom, found answers to questions, let us see the final note placed by the Secretary before the hon. Home Minister. If it is the Attorney General who has been consulted — the Constitution has a provision to invite the Attorney General — please call the Attorney General to this House. We will ask him these questions. But, somebody has to take responsibility for answers to these questions. These questions are well-known. Let me read it very rapidly. How do you group three countries — Afghanistan, Pakistan and Bangladesh — and leave out the other neighbours? How do you identify only six religious groups — Hindu, Sikh, Buddhist, Jain, Parsi and Christian — and leave out others like Ahmadis, Hazaras and Rohingyas? Ibrahamic religions are three — Christianity, Judaism and Islam. Why have you included Christianity and left the other two? Why have you excluded Sri Lankan Hindus and Bhutan's Christians? Look at the exclusionary, inclusionary hyphenation. Sri Lanka is excluded, Hindus are included! Bhutan is excluded, Christians are included! When you hyphenate the effectives, Sri Lankan Hindus are excluded, Bhutan's Christians are excluded. This exclusionary, inclusionary hyphenation is beyond commonsense and logic. Why only religious persecution? Are people not persecuted for political reasons? Are people not persecuted on linguistic grounds? Are people not persecuted by unleashing internal wars against them? Why only religious persecution? Why not every kind of persecution?

Six, does or does not the Bill violate the three fundamental elements of Article 14 of the Constitution? First, equality before law; unequals cannot be treated as equals. Second, unreasonable or irrational classification. And, there is a third element,

which most people forget, Judge-made laws are the third element. Even if unequals are not treated as equals or equals are treated unequally, even if the classification is reasonable, it can be struck down on the ground that it is arbitrary. Arbitrariness is writ large on the face of this Bill. Now, I want to know who will give answer to these questions. Please let us have the answers. Why are Parliamentarians being told that you will not give answers to these questions and they can go to court and find answers? Let's have answers to the questions. Let somebody take responsibility for answers saying, "Yes, the Attorney General of India has answered these questions. These are our answers and, therefore, this Bill is here". I dare the Government to lay the opinion of the Law Department; I dare the Government to invite the Attorney General to this House to answer our questions. So, what we are doing today is wrecking the Constitution from within. A small part of the Constitution is sought to be wrecked and demolished by this insidious Bill. Fortunately, we are three organs of the State. The Executive is complicit; the Legislature is being invited to collaborate; hopefully, the Judiciary will strike it down and will save India.

SHRI K.J. ALPHONS (Rajasthan): Sir, I strongly support this Bill. For thousands of years, India has given the most profound philosophy to the world, which is, "वसुधैव कुटुम्बम्" We gave refuge to people from all over the world who were persecuted and India was the place, when Christians were persecuted after the crucification of Christ, where one of the disciples of Christ came and set up the Syrian Church. Who allowed them to thrive in India? It's the Hindu community of India. Today, the Syrian Christians in Kerala is the most prosperous community. Why? Because India has allowed them to thrive here. This is the history of India. It has been a compassionate country. Hon. Chidambaram has raised the constitutional validity of this Bill. The crux of the Constitution, all the rights that you talk about, ultimately it is all about compassion; it's all about a compassionate society. It is about how we are able to look after the marginalized, the deprived people, and the oppressed people. That is exactly what this Bill proposes to do. This is what we are trying to do.

Sir, we have people who are persecuted. Hon. Shri Nadda, in his speech said that the minority population in Pakistan, which was earlier 23 per cent, has been

[Shri K.J. Alphons]

reduced to 2.3 per cent. Does it not call for a country, like India, to intervene and say, "Yes, this country welcomes you; we are human beings; as human beings, we have always believed in this theory that this world needs to be run by compassion, therefore, you are welcome here"? I don't need to tell you the history how many thousands of people are persecuted and executed for silly reasons.

Sir, Pakistan is governed by the Shariyat law. There were 3.9 million Christians in Pakistan. Today, we don't know what the number is. I can tell you briefly the history. In 2005 at Sangla Hill a Catholic Church, a Orthodox Church and the Presbyterian Church were all brought down to the ground. The Lahore bombings of 2013, in St. Paul's Cathederial killed 100 people, doesn't the world knows about this? And, the Peshawar bombings again at a Christian church killed 70 people. Again, in the 2016, the Easter bombings in Lahore Cathedral, 70 people were killed. There, minorities are being butchered and killed. Shouldn't the voice of the oppressed people, the minorities who are butchered, be heeded? Shouldn't India give heed to those people? We need to do that. Here is a country which is trying to undo all the injustices that have been done. Take, for example, Article 370. When we undid the injustice which has been there for 70 years, a lot of people said, "No, this is anti-Islamic." I am very sorry. I come from the State of Kerala. I come from a different culture and language. Why shouldn't I have Article 370? Why shouldn't I? Why should not the Tamilians have the same? Why shouldn't the Gujaratis have? Why should my State of Rajasthan not have Article 370? What was so incredibly different for the people of Kashmir to get Article 370? We abolished it because that was a Constitutional anomaly. But what does the Opposition say? "You are un-Islamic; you are anti-Muslim." I am sorry, Sir, no. We are setting right what was wrong in history. Look at the way this country is looking after the minorities. Look at the way it is providing protection. The Hon. Prime Minister has said very clearly in the Parliament and also at Vigyan Bhavan: "You believe in whatever you want to believe and I will ensure that you are allowed to live here peacefully and prosper. I will protect you." Even though the words were not exactly the same, but that was the broader meaning. Sir, the Prime Minister has said very clearly and the Home Minister has also said so. This land has been a home to everybody, to the oppressed and the depressed; therefore, this Bill, which we are

3.00 P.M.

bringing forward in Parliament, seeks to give refuge to the people who are persecuted, who have a right to live. Shri Swapan Dasgupta has said very clearly what the international convention is. It very clearly says that whenever religious minorities are persecuted anywhere in the world, the world has a responsibility to give them a refuge and that is what this Bill does, and, Sir, I strongly support this Bill.

SHRIMATI VIJILA SATHYANANTH (Tamil Nadu): Mr. Deputy Chairman, Sir, it is a privilege for me to speak on this very important Bill. As we are supporting the Bill, I would like to bring to the notice of this august House a few apprehensions and suggestions, which our dynamic Home Minister may take into account, especially, what has been said by our All India Anna Dravida Munetra Kazhgam supremo, our great leader, Dr. Puratchi Thalaivi Amma. She had asserted that she would take continuous steps to attain a separate homeland for Tamils in Sri Lanka and asked the Centre to grant dual citizenship to refugees from the island nation living in our State. She once said, and I quote: "We will urge the Central Government to confer dual citizenship on Sri Lankan Tamils living here, so that they can easily get job opportunities." She always fought for enabling Sri Lankan Tamils to live with full freedom and self respect and also for attaining a separate Eelam. She had said that her Government and herself would, personally, take valuable steps for that. These are the people who were born to refugees and raised in the State. Some were born here to refugees and they are living in the State. "When the then Central Government tried to repatriate them, it was opposed by my Government." This was said by Amma. So, she strongly stressed that her Party's, that is, All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam, policy was that any repatriation would be voluntary and based on the choice of refugees "after the situation in Sir Lanka, including the security aspects, changes fully for the better nation, better livelihood, self-respect", then the policy will change. She recalled that the Tamil Nadu Assembly had passed several resolutions on the Sri Lankan issue moved by her.

The Madurai Bench of the Madras High Court agreed that granting citizenship was within the 'exclusive executive domain' of the Centre. According to the records

[Shrimati Vijila Sathyananth]

available with the Department of Rehabilitation of the State of Tamil Nadu, only 4,60,000 people have arrived in India and have registered themselves as repatriated Indian citizens from Sri Lanka. Other than 'refugee cards' issued at the time of entry into the country, the Tamils do not have any document in support of their status. Now, they are considered as Stateless Indian-origin Tamils from Sri Lanka, and the Stateless Indian origin Tamils from Sri Lank a are kept together with the Sri Lankan Tamil refugees in the State-organized camps in Tamil Nadu. They have no State identification and they are considered as Sri Lankan citizens. Their repeated claims for Indian citizenship were refused on legal grounds as illegal migrants. They are not illegal migrants. There are 20,000 and more children, nearly 90 per cent of them, born in India to these refugees. Most of these people are living in India for more than 25 years, maybe, 30 years. About 90 per cent of the population belongs to the Hindu religion.

So, as these Sri Lankan refugees fulfil all the required criteria other than they are mentioned as illegal migrants and also keeping in mind the experience of their persecution, and the status of being persons of Indian origin, I plead to our hon. Home Minister to kindly include and consider that the Citizenship Bill also takes into account the Sri Lankan refugees and give them Indian citizenship.

Thank you, and, with these words, I support this Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you. Shri K.K. Ragesh; not present. Shri K.T.S. Tulsi; not present. Dr. Narendra Jadhav; not present. श्री संजय राउत। आपके लिए यहां पर तीन मिनट का समय है।

श्री संजय राउत (महाराष्ट्र): सर, तीन मिनट में क्या होगा?

श्री उपसभापति: 6 घंटे के अंदर इतना ही समय है।

श्री संजय राउत : सर, The Citizenship (Amendment) Bill, 2019 जो लोक सभा में पास होकर राज्य सभा में आया है, मैं देख रहा हूं कि अलग-अलग मत प्रवाह यहां देखने को मिले। लोकतंत्र में इस प्रकार से जब अलग मत प्रवाह होते हैं, यही हमारी democracy है। मैं कल से देख रहा हूं, कल से सुन रहा हूं, यह कहा गया कि जो बिल का समर्थन नही करेंगे, वे देशद्रोही हैं और जो बिल का समर्थन करेंगे, वे देशभक्त हैं। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: मेरा सभी सदस्यों से आग्रह है कि कृपया शांति बनाए रखें। ...**(व्यवधान)**... संजय जी को बोलने दें और उनकी बात सुनें।

श्री संजय राउत: मैंने यह भी पढ़ा है और मैं यह भी सुन रहा था कि जो इस बिल का समर्थन नही करेंगे, वे पाकिस्तान की भाषा बोलेंगे। महोदय, इसका मतलब क्या है, यह पाकिस्तान की असेम्बली तो नही है? यहां के हों या वहां के हों, हम इस देश के नागरिक हैं। देश की जनता ने सबको वोट किया है। यहां भी किया है और वहां भी किया है और देश की जनता ने ही वोट किया है। मैं कहना चाहता हूं कि यह पाकिस्तान के नागरिकों की असेम्बली नही है। अगर पाकिस्तान की भाषा हमें पसन्द नही है, तो हमारी इतनी मजबूत सरकार है, पाकिस्ताना को खत्म करो। पाकिस्तान ऑक्युपाइड ...**(व्यवधान)**... हम आपके साथ हैं। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: संजय जी, चेयर को सम्बोधित कर के बोलिए।

श्री संजय राउत: हम आपके साथ हैं, पाकिस्तान हो या हिन्दुस्तान के जो हमारे भाई वहां उस देश में अल्पसंख्यक के रूप में रह रहे हैं, यदि उन्हें तकलीफ होती है और यदि उनके साथ छल होता है, तो हमारा एक मजबूत देश, हमारे मजबूत प्रधान मंत्री और हमारे मजबूत गृह मंत्री हैं, आपके ऊपर हमारी आशा है। आपने धारा 370 को हटाया, हमने जी-जान से आपको समर्थन दिया है और देते रहेंगे। आज देश के बहुत से हिस्सों में मैं देख रहा हूं कि इस बिल का विरोध हो रहा है। इसके कारण वहां हिंसा हो रही है- असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर हों। ठीक है, एक सैक्शन इसके समर्थन में है और एक सैक्शन इसके विरोध में है। वे भी देश के नागरिक हैं। वे देशद्रोही नही हैं। इसलिए हमें किसी से देश-भक्ति का प्रमाणपत्र लेने की जरूरत नही है।

महोदय, हम कितने कठोर हिन्दू हैं, इसका प्रमाणपत्र हमें नही चाहिए। जिस स्कूल में आप पढ़ते हो, हम आपको बताना चाहते हैं कि हम उस स्कूल के हैडमास्टर हैं और हमारे स्कूल के हैडमास्टर श्री बालासाहेब ठाकरे थे, श्री अटल जी भी थे, श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे। हम सबको मानते हैं। मैं आज अभी एक अखबार में पढ़ रहा था कि कश्मीर में दो जवान शहीद हुए, वे मुसलमान थे। उनके परिवारों ने भी इस बिल का विरोध किया है, वे देशद्रोही तो नही हैं। मैं मानता हूं कि यह बिल धार्मिक नही है, यह बिल मानवता के आधार पर लाया गया है और उसी आधार पर इस पर चर्चा होनी चाहिए।

महोदय, हमें यह भी पता है कि घुसपैठिया और शरणार्थी में फर्क है। क्या बिल पास होने के बाद, इस देश में जितने भी घुसपैठिए हैं, उन्हें आप बाहर निकालेंगे? ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: संजय जी, कृपया समाप्त कीजिए।

श्री संजय राउत: इस देश से उन्हें बाहर निकालना चाहिए, क्योंकि यह गृह मंत्री जी की commitment है। चुनाव की रैलियों में इस देश में उन्होंने अनेक जगहों पर कहा है, यह उनकी commitment है कि इस देश से एक-एक घुसपैठिए को हम बाहर निकालेंगे। अगर हम अपने शरणार्थियों को यहां जगह दे रहे हैं, तो घुसपैठियों को निकालना चाहिए। मैं यह मानता हूं कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बंगलादेश में जो हमारे अल्पसंख्यक भाई हैं, वे चाहे हिन्दू हों, चाहे सिख हों, चाहे ईसाई हों, उनके अधिकारों का हनन हुआ है। वहां जबर्दस्ती धर्मान्तरण होता है, बेटियों के ऊपर अत्याचार होते हैं, हत्याएं होती हैं और मानवता के आधार पर हमें उसे स्वीकार करना चाहिए।

श्री उपसभापति: संजय जी, अब conclude कीजिए।

श्री संजय राउत: उन्हें स्वीकार करना चाहिए, लेकिन हम उन्हें अगर स्वीकार करते हैं, तो उसमें राजनीति नही होनी चाहिए, वोट बैंक की राजनीति नही होनी चाहिए। उन्हें रोटी, कपड़ा, मकान और रोजगार जो आप दे सकते हैं, आप दीजिए। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: संजय जी, अब conclude कीजिए। अब मैं अगले स्पीकर को बुला रहा हूं। कृपया आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री संजय राउत: लेकिन ये सभी लोग किलने हैं? जैसे गृह मंत्री जी ने अपनी प्रस्तावना में कहा है कि यह लाखों-करोड़ों लोगों की वेदना है और उनकी बात आपने कही, अगर आप यहां लाखों-करोड़ों लोगों यहां ला रहे हैं, तो क्या उन्हें वोटिंग राइट मिलेगा ..(व्यवधान)... यदि आप 20-25 साल तक वोटिंग राइट नही देते हैं, तो ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: उनका तीन मिनट का समय है और मैंने उन्हें पांच मिनट बोलने का अवसर दिया है। Please do not tell me. प्रो. मनोज कुमार झा। ...**(व्यवधान)**...

श्री संजय राउत: सर, हमारे देश में लाखों कश्मीरी जो शरणार्थी हैं ...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude. I would call the next speaker. Sanjay Rautji, you have already taken six minutes instead of three minutes. ...*(Interruptions)*... Please conclude. ...*(Interruptions)*... I am forced to call the next speaker; Prof. Manoj Kumar Jha. ...*(Interruptions)*...

श्री संजय राउत: जब आर्टिकल 370 हटाया गया, तब उनके मन में भी आशा की उम्मीद जागी थी कि ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: संजय जी, आप conclude कीजिए। ...**(व्यवधान)**...

श्री संजय राउत: हमारे गृह मंत्री जी कश्मीरी शरणार्थियों को वापस कश्मीर भेजेंगे। ...**(समय की घंटी)**...

श्री उपसभापति: प्रो. मनोज कुमार झा, आप बोलिए। अब आपकी बात ही रेकॉर्ड पर जाएगी। ...**(व्यवधान)**...

श्री संजय राउत: *

श्री उपसभापति: श्री मनोज कुमार झा, आप बोलिए। अब आपकी बात ही रेकॉर्ड पर जाएगी। ...**(व्यवधान)**...

प्रो. मनोज कुमार झा: उपसभापति जी ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: अगर आप नही बोलेंगे, तो मैं दूसरे स्पीकर को बुलाऊंगा। ...**(व्यवधान)**...

श्री संजय राउत: *

श्री उपसभापति: अब श्री संजय राउत की बात रेकार्ड पर नही जाएगी, आपकी बात रेकॉर्ड पर जाएगी। आप बोलिए। अगर आप नही बोलेंगे, तो मैं दूसरे स्पीकर को बुलाऊंगा। ...**(व्यवधान)**... I am calling the next speaker. ...*(Interruptions)*...

प्रो. मनोज कुमार झा: सर, मैं क्या करूँ? ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: श्री प्रफुल्ल पटेल - not present. श्री सतीश चन्द्र मिश्रा, आप बोलिए। अब आपकी बात ही रेकॉर्ड पर जाएगी। ...**(व्यवधान)**...

PROF. MANOJ KUMAR JHA: Sir. ...*(Interruptions)*...

श्री संजय राउत: *

श्री उपसभापति: अब आपकी बात रेकॉर्ड पर नही जा रही है। ...**(व्यवधान)**... आप कृपया समय का पालन कीजिए। यह छह घंटे की बहस का समय आप सभी ने मिलकर तय % किया है। सतीश चन्द्र मिश्रा जी, आपकी बात ही रेकॉर्ड पर जाएगी। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: माननीय सतीश चन्द्र मिश्रा जी, आप बोलिए, आपकी बात ही रेकॉर्ड पर जा रही है। He has already exceeded his time. ...*(Interruptions)*...

प्रो. मनोज कुमार झा: सर ...**(व्यवधान)**...

---

*Not recorded

श्री सतीश चन्द्र मिश्रा (उत्तर प्रदेश) : उपसभापति जी, दो लोग कैसे बोलेंगे? ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: आप बोलिए, मैंने आपका नाम बुलाया है, चेयर ने और नाम नही लिया है। ...**(व्यवधान)**...

PROF. MANOJ KUMAR JHA: Sir. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I will call you again. ...*(Interruptions)*... You refused to speak. ...*(Interruptions)*...

PROF. MANOJ KUMAR JHA: No, Sir. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You have to take care of that. ...*(Interruptions)*...

श्री सत्तीश चन्द्र मिश्रा : आदरणीय उपसभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं अपनी बात शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप नाराज़गी छोड़कर कभी-कभी मुस्करा भी दीजिए।

श्री उपसभापति: हमेशा मुस्कराते हूं। ...**(व्यवधान)**...

श्री सतीश चन्द्र मिश्रा: इससे हम लोगों का थोड़ा मन लगा रहेगा।

श्री उपसभापति: माननीय सतीश चन्द्र मिश्रा जी, यह छह घंटे बहस का समय आप लोगों ने ही निर्धारित किया है और मुझे ही उसका पालन करना है।

श्री सतीश चन्द्र मिश्रा: उपसभापति जी, मैं समझता हूं कि आपके ऊपर टाइम का प्रेशर है। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले यह कहना चाहता हूं कि आप टाइम एक्सटेंड कर सकते हैं। पूरा हाउस चाहता है कि टाइम एक्सटेंड हो जाए।

श्री शरद पवार: टाइम एक्सटेंड कर सकते हैं।

श्री उपसभापति: आप लोगों ने समय तय किया है, मैंने नही किया है। ...**(व्यवधान)**... माननीय चेयरमैन साहब के आदेश के अनुसार मुझे इसका पालन करना है।

श्री सतीश चन्द्र मिश्रा: उपसभापति जी, हमारा टाइम अब स्टार्ट करवाइए।

श्री उपसभापति: हाँ, ठीक है।

श्री सतीश चन्द्र मिश्रा: आदरणीय उपसभापति जी, सबसे पहले तो मैं यह कहना चाहूंगा कि हम लोग इस बिल के समर्थन में नही खड़े हुए हैं, बल्कि इसे अपोज करने के लिए खड़े हुए हैं। हम अपोज करने के लिए क्यों खड़े हुए हैं? यद्यपि हम एक तरफ इस बात

के लिए माननीय होम मिनिस्टर साहब को बधाई देना चाहते हैं, उनकी तारीफ करना चाहते हैं कि जो लोग पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बंगलादेश में रह रहे हैं, जहाँ पर भी माइनॉरिटीज़ रह रही हैं, आपने उनके बारे में सोचा है और उनके बारे में सोचकर कहा है। चूंकि टाइम कम है, इसलिए कास्ट का नाम नही लूंगा, लेकिन मैं यह अवश्य कहूंगा कि आपने सिर्फ मुस्लिम्स को छोड़कर वहाँ की जो माइनॉरिटीज़ हैं, उनको लेकर यह कहा है कि हम उनको शरणार्थी के रूप में सिटिज़नशिप देंगे। यह वेलकम करने लायक बात है, लेकिन इसके साथ-साथ आपका यह भी कहना है कि आपने 31 दिसंबर, 2014 की डेट क्यों लगाई है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या उस डेट के बाद के लोगों को हक नही है कि जो लोग प्रताड़ित किए जा रहे हैं, वे यहाँ पर आकर इस देश के सिटिजन्स बन सकें? हम लोग इसका जवाब जरूर जानना चाहेंगे कि 31 दिसंबर, 2014 की कट ऑफ डेट किस कारण से, किस बेसिस पर रखी गई है? सर, इसके साथ-साथ यह भी प्रश्न उठता है कि हम लोग इसको अपोज़ क्यों कर रहे हैं? हम इसको इसलिए अपोज कर रहे हैं क्योंकि जो कांस्टीट्यूशन का प्रिएम्बल है, the Preamble to the Constitution speaks about secularism and there should not be any favouritism. Everybody has to be treated equal. जब इस पर हम लोगों ने, कई लोगों ने कहा कि यह आर्टिकल 14 का वॉयलेशन है, आर्टिकल 15 का वॉयलेशन है और आर्टिकल 21 का भी वॉयलेशन है, तब इस पर एक तर्क आया, जो कि सत्ता पक्ष की तरफ से सुनने को मिला है। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 15 को पढ़ लीजिए, उसमें "सिटिज़न" वर्ड लिखा हुआ है। इसके साथ-साथ आर्टिकल 14 को भी पढ़ लीजिए, आर्टिकल 21 को भी पढ़ लीजिए, वह "सिटिज़न" वर्ड यूज़ नही करता, बल्कि "पर्सन" वर्ड यूज करता है और "एनी पर्सन" वर्ड यूज करता है। अगर "एनी पर्सन" वर्ड को जो कांस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क करने वाले लोग थे, जिन्होंने संविधान के रचयिता बाबा साहेब डा. भीमराव अम्बेडकर के साथ मिलकर संविधान बनाया था, तब उन्होंने सोच-समझकर यह distinction रखा था। This distinction has to be kept in mind because in the same Chapter of Fundamental Rights, two different words are used in Articles 14, 15 and 21. So, why are you violating this Article 14 by excluding Muslims? Now, Muslims being excluded, is the sole problem of this entire Act and this Act is bound to fail. The soul of the Constitution, जो यह है कि आप recularism को maintain रखेंगे, धर्मनिरपेक्षता maintain रखेंगे, you have taken away that. And, by taking away that, you have brought this Bill which is not Constitutional Amendment. इसलिए मेरा आपसे यह कहना है कि आप इसके बारे में जरूर दोबारा विचार करें, क्योंकि constitutional structure of this country, otherwise, will definitely be lost, which will be a very sad day.

जैसा कई और लोगों ने भी कहा कि अभी इसका टैस्ट एक और जगह होगा। यहाँ तो संख्या बल के आधार पर या जो भी हो, यह एक्ट बन जाएगा, पास हो जाएगा, लेकिन

[श्री सतीश चन्द्र मिश्रा]

अगर यह पास हो जाता है, तो इसके बाद इसका टैस्ट होगा, Article 14 का टैस्ट होगा, Article 21 का टेस्ट होगा और Preamble का टैस्ट होगा, framework क्यों बनाया गया, 'secularism' word क्यों लाया गया, अगर basic structure तोड़ दिया जाता है, तो wheather such an Act, which is an Executive Act, जिसको आप यहाँ से बना कर ला रहे हैं, यह sustain करेगा कि नही करेगा, यह सामने आएगा। चूँकि आपने इसमें इन चीजों का violation किया है, इसलिए हमारी पार्टी इसका विरोध करती है। धन्यवाद।

श्री उपसभापति: प्रो. मनोज कुमार झा।

प्रो. मनोज कुमार झा (बिहार): उपसभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। सर, सदन में और इतिहास में कई ऐसे क्षण आते हैं, जब आसानी से यह कह दूँ कि समर्थन कर रहा हूँ या विरोध कर रहा हूँ, उससे बात नही बनेगी। माननीय गृह मंत्री जी, तीन मसलों पर मेरी आपत्ति है। पहला सैद्धांतिक, दूसरा ऐतिहासिक और तीसरा व्यावहारिक।

माननीय गृह मंत्री जी, हम तो बचपन से पढ़ते थे कि "अयं निज: परो वेति गणना लघु चेतसाम्, उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्।" कहाँ से कहाँ आ गए हम! कहाँ से कहाँ पहुँच गए। माननीय उपसभापति महोदय, मैं माननीय गृह मंत्री जी से ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि "मायूस कर रहा है यह नई रोशनी का रंग, न इसका कुछ अदब है, न कुछ एतबार है।"

सर, मैं दो-तीन चीजें कहना चाहता हूँ। JPC हुई थी, तो experts ने कहा था कि please use 'persecuted minorities' और religious lines को avoid करने की बात कही थी। माननीय गृह मंत्री जी, हाथ जोड़ कर कहता हूँ कि मैं आपके विपक्ष में हूँ, आपका राजनीतिक शत्रु नही हूँ। मैं क्रॉमवेल को paraphrase कर रहा हूँ, "I beseech you in the name of Constitution. Think once for once that you might be committing a great blunder." आप एक बार जरूर सोचिएगा। मेरा यह कहना है कि experts ने committee में कहा कि 'persecuted minority' बोलो, लेकिन उसको

[उपसभाध्यक्ष, (श्री सुखेन्दु शेखर राय) *पीठासीन हुए]*

दरकिनार कर दिया गया। उसको दरकिनार करने के पीछे क्या वजह है, समझ में नही आया। बार-बार मेरे कई साथियों ने कहा है कि persecution के मनोविज्ञान को समझना होगा। A State which persecutes does not always differentiate between 'A', 'B' and 'C' community, जो उसकी आदत होती है। जर्मनी में जब यहूदियों का persecution हो रहा था, तो सिर्फ यहूदियों का persecution नही हुआ। इतिहास गवाह है कि उन

Germans का भी persecution हुआ, जिन्होंने उन यहूदियों के साथ खड़ा होने के बारे में सोचा। सर, एक बार तो सोचना होगा। विदम्बरम साहब बोल चुके हैं, persecution कई तरह के होते हैं। सबसे ज्यादा यह political belief को लेकर होता है।

आपके बिल में atheist के लिए तो कोई व्यवस्था ही नही है। ज़रा एक बार यह भी सोच कर देखिएगा कि जिनकी ईश्वर में आस्था नही है, ऐसे बहुत लोग हैं, उनका इस वजह से भी persecution होता है, तो वे कहाँ जाएँ?

सर मेरे कई साथियों ने कहा है कि constitutionally, it is suspect and it goes against the very tenet of constitutional morality. Sir, there is something called intelligible differentiation and reasonable classification. Very frankly, hon. Home Minister Sir, it is unintelligent differentiation and unreasonable classification. जैसा मेरे कई साथियों ने कहा कि वे अपने स्टेटमेंट में persecution की बात करते हैं, लेकिन वह body of text में कही नही आता है। It is a bad law. It is morally bad. It is constitutionally bad. And, anything which is morally bad, constitutionally bad, should not be accepted. आज आपकी majority है। मैं जानता हूं कि आप यह बिल पास करवा लेंगे। इतिहास बताता है कि दस-बीस बरस की सरकार दो लाइनों में सिमट जाती है या कभी-कभी किसी फुटनोट में सिमट जाती है। Please remember history. सर, इतिहास तय करेगा ...**(समय की घंटी)**... मुझे अभी एक मिनट का वक्त और दीजिए। Sir, with heavy heart मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आज मुझे 70 संगठनों ने फोन किया और सब यही कह रहे थे कि काश आज लालू जी, जो मेरी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सदन में होते। मैं जानता हूं कि मैं उनकी कमी पूरी नही कर पाऊँगा, लेकिन बस कोशिश कर रहा हूं। माननीय गृह मंत्री जी की ओर से बार-बार कहा गया कि NRC अलग है और CAB अलग है। नही साहब, ये अलग नही हैं, क्योंकि NRC में पैदा हुई दिक्कतों ने आपको प्रेरित किया कि एक ऐसा एक बिल लेकर आओ, जिससे अपनी कमज़ोरियों को छुपा लो। कमाल का बिल है! गुरखा कहां गए? वे कौन लोग हैं? आप stateless citizen का क्या करेंगे? बंगलादेश की प्रीमियर कहती है कि हमको भारत के प्रधान मंत्री जी ने भरोसा दिया है। हम किसकी बात मानें? हम उनकी बात मानें या आपकी बात मानें? हम किसकी बात मानें?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY): Please conclude. Your time is over.

प्रो. मनोज कुमार झा: सर, मैं बस कन्क्लूड ही कर रहा हूं, मुझे आधा सैकंड का समय और दीजिए। सर, इसकी authentication cost भी बहुत है। सुना है इसमें 1600-1700

[प्रो. मनोज कुमार झा]

करोड़ रुपये लग गए हैं। जब आप पूरे देश में NRC कराइएगा, तो 4 लाख, 26 हज़ार करोड़ रुपये लग जाएंगे। इतने रुपयों में तो हम अपने यहां की एजुकेशन को इतना खूबसूरत बना लेंगे कि दुनिया की बुलंदियों तक पहुंच जाएंगे।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY): Thank you.

प्रो. मनोज कुमार झा: सर, एक आखिरी टिप्पणी कर रहा हूं, बस तीस सैकंड और दीजिए। आजकल इतिहास कल्पनाओं पर चलता है। कई बड़े-बड़े मंत्री साहब कहते हैं कि ऐसा न हुआ होता, वैसा हुआ होता। सर, अभी जब हम राज्य सभा में बैठकर इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, तो ऊपर शोकसभा हो रही होगी और अगर स्वर्ग नाम की कोई जगह है, तो वहां बापू को जिन्ना आकर कहेंगे ...**(व्यवधान)**...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY): I'm following the instructions of time. I'm helpless.

प्रो. मनोज कुमार झा: लोग पूछते हैं न कि क्या हुआ, लड़का हुआ या लड़की हुई? बापू जी को जिन्ना आकर कहेंगे कि आपको इज़राइल हुआ है, क्योंकि सर, हमने इज़राइल के मॉडल को फॉलो कर लिया है। ...**(समय की घंटी)**...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY): Tank you.

प्रो. मनोज कुमार झा: सर, यह हमारे मुल्क के लिए, इस महासागर के लिए अच्छा नही है। मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आप इसको तालाब मत बनाइए। मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि रुक जाइए। आप अपनी मेजॉरिटी का बेहतर इस्तेमाल कीजिए, धन्यवाद।

श्री प्रफुल्ल पटेल (महाराष्ट्र): वाइस चेयरमैन सर, आज हम लोग जिस विधेयक के बारे में चर्चा कर रहे हैं, इसमें सबसे पहली बात तो यह है कि इसे बहुत जल्दबाज़ी में लाया जा रहा है। जिस तरह अखबारों में हम पढ़ रहे हैं और जिस तरह से हमको पूरे देश का वातावरण नज़र आ रहा है, वह अच्छा नही है। अगर हम आज का अखबार भी उठाकर देखें, तो असम और नॉर्थ-ईस्ट में कई घटनाएं घट रही हैं। सबसे पहले तो इसमें यही सवाल उठता है कि इतने अहम बिल को लाने से पहले थोड़ी और गंभीर चर्चा होनी चाहिए थी। इसके लिए यह मांग भी उठी कि इसे सेलेक्ट कमिटी को भेजा जाए और पहले इस पर कुछ चर्चा हो। हमारी समझ में यह बात अभी भी नही आ रही है कि इसमें सरकार को क्या आपत्ति है? यह कानून 1955 में बना था और समय-समय पर इसमें संशोधन भी हुआ है। वे संशोधन पर्याप्त थे। आज तक तो हमें इसमें कोई कमी नज़र नही आई। बंगलादेश की बात कही जाती है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने अपनी कॉस्टिट्यूएंसी

गोंदिया, महाराष्ट्र में स्वयं देखा है, जब 1971 की लड़ाई हुई और बंगलादेश का निर्माण हुआ, तो वहां बंगलादेश के बहुत सारे रेफ्यूजीज़ आए, जिनमें अधिकांश हिन्दू थे। उन लोगों को वहां बहुत अच्छी तरह से जमीन दी गई, मकान दिए गए और नागरिकता सहित अच्छे से रहने की सभी सुविधाएं देने का प्रावधान किया गया। इसलिए हमारा इतिहास गवाह है कि निश्चित तौर पर हमारे पास कानून पर्याप्त हैं। उस वक्त लाखों लोग आए थे, जिनको केवल बंगलादेश से लगे हुए इलाकों में ही नही, बल्कि देश के दूर-दूराज़ के इलाकों में बसाने का भी काम किया गया था। इसलिए जिस तरह से यह बिल लाया जा रहा है, वह सही नही है। यहां हमारे बहुत सारे अधिवक्ता बोले हैं, चिदम्बरम साहब भी बोले हैं और बाकी के लोग भी बोले हैं कि इस बिल में कुछ कमियां हैं। यहां संविधान के आर्टिकल-6 की बात हो रही है, आर्टिकल-14 की बात हो रही है। निश्चित तौर पर कही न कही कानूनी तौर पर इसे चैलेंज किए जाने की संभावना है, इसलिए अगर इस बिल का अच्छी तरह से अध्ययन करके और सारी बातों को क्लीयर करके हम इस बिल को लाते, तो हम लोगों को निश्चित रूप से इसका फायदा होता। आज असम की NRC की बात बार-बार उठी है। असम में NRC में 19 लाख लोगों को गिनती में छोड़ा गया। उसमें करीब 16 लाख हिन्दू और बाकी अन्य जो नॉन-मुस्लिम्स हैं, उनका समावेश होता है। वहाँ कैम्प की बात कही गयी। वहाँ के जो जानकार लोग हैं, जो उस मुल्क में रहते हैं, वहाँ से उन लोगों ने कहा कि कैम्प्स में जिस तरह से जिस बुरे हाल में वहाँ पर लोग रह रहे हैं और जो परेशानियाँ वहाँ पर उठ रही हैं-- तो अगर हम मानवीय दृष्टिकोण को भी देखते हुए इसको विचार करें, तो कही न कही हम जल्दबाजी में, हमारा यह जो संशोधन करने का पूरा लॉग टर्म दृष्टिकोण है, उससे हम दूर जा रहे हैं।

आज संविधान ने सभी को बराबरी का दर्जा दिया है। ...**(समय की घंटी)**... कोई धर्म और जाति के भेदभाव के बिना हमें दिया है। हमने देखा है कि जब पार्टिशन हुआ, तो हिन्दू वहाँ से यहाँ आये, यहाँ से मुसलमान वहाँ गये, परन्तु ऐसे भी किस्से हैं कि मुसलमान भी वहाँ से हिन्दुस्तान में आये। ऐसे एक नही अनेक उदाहरण भी हमें देखने को मिलते हैं।

उपसभाध्यक्ष (श्री सुखेन्दु शेखर राय): धन्यवाद।

श्री प्रफुल्ल पटेल: इसलिए यह पार्टिशन और उसमें केवल हिन्दू और मुस्लिम का ही एक भेदभाव था, यह दृष्टिकोण रखना बहुत संकुचित होगा, यह बिल्कुल गलत होगा। इसी को ध्यान में रखते हुए इस बिल पर, अभी भी सरकार के सामने समय है, इस सदन की भावना को ध्यान में रख कर अगर फिर से कोई विचार किया जाए और एक सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाए, तो यह बहुत अच्छी बात होगी।

उपसभाध्यक्ष (श्री सुखेन्दु शेखर राय): धन्यवाद।

श्री प्रफुल्ल पटेल: लेकिन फिर भी हमें दूसरे हाउस की जो मंशा नजर आ रही है, सरकार के वक्तव्य में, गृह मंत्री जी के वक्तव्य में, शुरुआत में उन्होंने जो कहा, मंशा यही नजर आ रही है कि आज के आज इसको पारित करना है। इसीलिए मैं ज्यादा कुछ और न कहते हुए, क्योंकि आप घंटी दबा रहे हैं, केवल इतना ही कहूँगा कि हम इस बिल के समर्थन में बिल्कुल नही हैं। यहाँ पर मैं सदन से आग्रह करूँगा कि हम सब लोगों को मिल कर इस बिल का सामूहिक विरोध करना चाहिए।

SHRI HISHEY LACHUNGPA (Sikkim): Sir, the Citizenship Amendment Bill is before us for discussion and passing. We, in Sikkim, have many apprehensions, as the whole concept of citizenship; Indian citizenship was granted to the Sikkim Subject holders in the year 1975, when we became the 22nd State of the Indian Union. The Sikkim Subject is therefore a sacrosanct identity of those who were the citizens of Sikkim, under the erstwhile Chogyal. Today, we are deliberating on a Bill that has many ramifications nationally, as well as locally in the North East Region and within Sikkim, which is also a part of the North East Region. Sir, from the point of view of Sikkim, we oppose this Bill from the standpoint of its potential dilution of Article 371 (F). This captures the essence of the provisions under which the Sikkim kingdom was merged with the Indian Union in the year 1975, after a referendum. All that the people of Sikkim know, is the Sikkim Subject Register and under this we stand protected. Though, the assurance given by hon. Home Minister, that all the provisos of Article 371 will not be diluted by the CAB is certainly welcomed. However, this must be in both letter and spirit. The CAB, in its present form, will go against the very nature of the spirit of Article 371 (F). The rest of the North Eastern States, have been exempted either by means of Inner Line Permit system (ILP) or as the Sixth Schedule areas, whilst Sikkim stands unprotected by either of these two exemptions given. In Sikkim, we have both RAP/PAP and ILP for foreigners and hence no foreigner can come and seek the citizenship without entering Sikkim. To that extent, we are protected. I appeal to the hon. Home Minister to extend the ILP, under the Bengal Act, to Sikkim as well. Since it is also being extended to the State of Manipur, it should also not be difficult as we already have a framework in place, as already stated by me. In this regard, I seek the assurance from the hon. Home Minister, on the floor of this House, during the reply. Thank you. Jai Hind.

SHRI ABDUL WAHAB (Kerala): Sir, I stand to vehemently oppose this Bill. This Bill is fundamentally against the democratic ethos, constitutional values and against the idea of India. Indian subcontinent has always cherished our values such as *Vasudhaiva Kutumbakam* — not like what Mr. Alphons said. The whole world is one family and *Atithi Devo Bhava* means Guest is God. Our country which cherished different values and is inclusive of all faith cannot accept a legislation, which discriminates human beings in term of their faith, race, region and gender. Any such move by the Government will kill the spirit of India.

This Bill in its Statement of Objects and Reasons argues to give citizenship to all illegal immigrants from Pakistan, Afghanistan and Bangladesh except Muslims. Any such move to legalize citizenship in terms of religion is a sheer violation of constitutional values. Moreover, the Bill cannot be read in isolation. It has to be read in conjunction with Government's move towards National Register of Citizenship which is inhuman and will convert human beings into bare bodies without any rights. It is a known fact that the Government, in the background of this Bill and proposed nationwide NRC, aims to dehumanize and convert millions of Indian Muslims into the condition of statelessness.

Although India is yet to sign International Refugee Convention, but we have always welcomed refugees such as Chakmas, Tibetans, Tamils from Sri Lanka, Afghanis during their crisis, irrespective of their religion, class, caste, race, gender and region.

However, this Bill has discriminated Tamil Muslims and Hindus in Sri Lanka, and is silent about the world's largest persecuted minorities of contemporary times, Rohingyan refugees in India, and does not speak a word about non-believers who are being persecuted around the world.

How are we going to deal with Muslims and other persecuted minorities who are currently residing in India? Are we going to put them in Detention Camps that you are building? Then, it will be one another episode of holocaust under the leadership of current Home Minister, Shri Amit Shah ji. In case, if the Government is thinking to deport them, when there is a life threat to these minorities, it is against the principle of *non refoulement*.

[Shri Abdul Wahab]

As far as region and caste is concerned, millions of people of Jammu and Kashmir felt betrayed, millions of people in Assam left into statelessness, and now crores of Mulsims are being kept under constant fear of being bare bodies with no rights through this draconian legislation. If this Bill gets passed in this House with tyranny of numbers and sheer arrogance, it will be the final nail in the coffin of Indian democracy.

Therefore, I urge upon the Government to withdraw this draconian legislation which is inhuman, discriminatory and against all ethos and values that this country has stood for. Thank you very much.

मीर मोहम्मद फ़ैयाज (जम्मू-कश्मीर): सर, आज जो यह बिल लाया गया है, मैं इसके विरोध में खड़ा हूँ। जब से यह सरकार बनी, तब से हम देख रहे हैं, चाहे वह ट्रिपल तलाक बिल हो, चाहे 370 का मामला आया, चाहे आज जो यह बिल लाया गया और इस बिल को लाने का जो तरीका है, उसमें सीधे एक कम्युनिटी, जिससे मैं भी आता हूँ मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बंगलादेश से अब यहाँ कोई मुसलमान नही आएगा। इस बिल में जो बात आई, उसके अनुसार हमारे हिन्दू, सिख, बौद्ध या बाकी जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं, उनकी सिटिज़नशिप के लिए यह बिल लाया गया है। यह बहुत अच्छी बात है, हम इसका सपोर्ट करते हैं, लेकिन इसमें मुसलमानों को जो साइड में रखा गया है, ... पाकिस्तान या बंगलादेश या अफगानिस्तान से हिन्दू यहाँ नही आएंगे, क्योंकि मैं उस स्टेट से आता हूँ, जहाँ हमारे पुरखों ने यह समझ कर फैसला किया था कि हम इस सेक्युलर हिन्दुस्तान के साथ जाएँगे, बजाय मुस्लिम बहुल पाकिस्तान के। वे इसलिए आए थे कि इस सेक्युलर मुल्क में हमें बराबरी का दर्जा दिया जाएगा। सर, आज जो हम यह सुन रहे हैं, आज का जो यह दिन है, मुझे आज यह लगता है कि हमारे पुरखों ने गलती की है। आज हमें यहाँ मुसलमान अच्छा नही लगता है। आर्टिकल 370 को इसी हाउस में हटाया गया। मुझे बताइए कि देश की एक रियासत में क्या आज तक ऐसा हुआ है कि जितने भी वहाँ के एमएलए, मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर हैं, वे सब जेलों में बन्द हैं? हमारे होम मिनिस्टर साहब ने दो दिन पहले उस हाउस में या इस हाउस में कहा था कि जम्मू-कश्मीर के हालात बिल्कुल सामान्य हैं। अगर वहाँ हालात सामान्य हैं, तो मैं मुबारकबाद देता हूँ।

सर, जिन एमएलएज़ ने इस देश के लिए कुर्बानी दी, अशफाक जवाद, हमारा एक एमएलए है, जिसका बाप एमएलए था, उसे militants ने मारा। ज़हूर मीर, जिसका बाप एमएलए था, उसे militants ने मारा। क्या वह दोशद्रोही है? वह आज जेल में है। हमारा एक और एमएलए है, जिसका चौदह साल का बच्चा बीमार है, वह अब दिल्ली में मेरे घर

पर है। वह कह रहा है कि मेरे बाप ने क्या गलती की है? आज जो आप कह रहे हैं कि वहाँ से मुसलमान आएंगे, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि मुसलमान नही आएंगे, क्योंकि उनको पता चला कि इस देश में एक ही वाहिद मुस्लिम रियासत है, उनके साथ क्या हो रहा है। ...**(समय की घंटी)**...

†**جناب محمد فیاض (جموں وکشمیر):** سر، آج جو یہ بل لایا گیا ہے میں اس کے ورودھ میں کھڑا ہوں۔ جب سے یہ سرکار بنی، تب سے ہم دیکھ رہے ہیں، چاہے وہ ٹرپل طلاق بل ہو، چاہے 370 کا معاملہ آیا، چاہے آج جو یہ بل لایا گیا اور اس بل کو لانے کا جو طریقہ ہے، اس میں سیدھے ایک کمیونٹی، جس سے میں بھی آتا ہوں، مسلم کمیونٹی کو ٹارگیٹ کیا جارہا ہے۔ پاکستان، افغانستان یا بنگلہ دیش سے اب یہاں کوئی مسلمان نہیں آئے گا۔ اس بل میں جو بات آئی، اس کے مطابق ہمارے ہندو، سکھ، بودھ یا باقی جتنی بھی کمیونٹیز ہیں، ان کی سٹیزن شپ کے لیے یہ بل لایا گیا ہے۔ یہ بہت اچھی بات ہے، ہم اس کا سپورٹ کرتے ہیں، لیکن اس میں مسلمانوں کو جو سائیڈ میں رکھا گیا ہے، پاکستان یا بنگلہ دیش یا افغانستان سے ہندو یہاں نہیں آئینگے، کیوں کہ میں اس اسٹیٹ سے آتا ہوں جہاں ہمارے پرکھوں نے یہ سمجھ کر فیصلہ کیا تھا کہ ہم اس سیکولر ہندستان کے ساتھ جائیں گے، بجائے مسلم بھل پاکستان کے۔ وہ اس لیے آئے تھے کہ اس سیکولر ملک میں ہمیں برابری کا درجہ دیا جائے گا۔

سر، آج جو ہم یہ سن رہے ہیں، آج کا جو یہ دن ہے، مجھے آج یہ لگتا ہے کہ ہمارے پرکھوں نے غلطی کی ہے۔ آج ہمیں یہاں مسلمان اچھا نہیں لگتا ہے۔ دفعہ 370 کو اسی ہاؤس میں ہٹایا گیا۔ مجھے بتائیے کہ دیش کی ایک ریاست میں کیا آج تک ایسا ہوا ہے کہ جتنے بھی وہاں کے ایم۔ایل۔اے۔، منسٹر، چیف منسٹر ہیں، وہ سب جیلوں میں بند ہیں؟ ہمارے ہوم منسٹر صاحب نے دو دن پہلے اس ہاؤس میں یا اس ہاؤس میں کہا تھا کہ جموں کشمیر کے حالات بالکل نارمل ہیں۔ اگر وہاں حالات نارمل ہیں، تو میں مبارکباد دیتا ہوں۔

سر، جن ایم۔ایل۔ایز۔ نے اس دیش کے لئے قربانی دی، اشفاق جواد، ہمارا ایک ایم۔ایل۔اے۔ ہے۔ جس کا بات ایم۔ایل۔اے۔ تھا، اسے ملیٹینٹ نے مارا۔ ظہور میر، جس کا بات ایم۔ایل۔اے۔ تھا، اسے ملیٹینٹ نے مارا۔ کیا وہ دیش دروہی ہے؟ وہ آج جیل میں ہیں۔ ہمارا ایک اور ایم۔ایل۔اے۔ ہے، جس کا چودہ سال کا بچہ بیمار ہے، وہ اب دہلی میں میرے گھر پر ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ میرے باپ نے کیا غلطی کی ہے؟ آج جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں سے مسلمان آئیں گے، لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کہ مسلمان نہیں آئیں گے، کیوں کہ ان کو پتہ چلا کہ اس دیش میں ایک ہی واحد مسلم ریاست ہے، ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ---(وقت کی گھنٹی)---

†Transliteration in Urdu script.

उपसभाध्यक्ष (श्री सुखेन्दु शेखर राय): कन्क्लूड कीजिए।

मीर मोहम्मद फ़ैयाज: वे यहाँ नही आएंगे, कभी नही आएगे। सर, आज जो बात हो रही है, यहाँ हमारी सरकार को -- मैं यह इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि बाकी बातें तो तकरीबन हो गई हैं, लेकिन आज हमें हर वक्त टारगेट किया जा रहा है। यहाँ ट्रिपल तलाक का बिल आया...

†**جناب میر محمد فیّاض :** وہ یہاں نہیں آئیں گے، کبھی نہیں آئیں گے۔ سر، آج جو بات ہو رہی ہے، یہاں ہماری سرکار کو۔ میں یہ اس لئے کہہ رہا ہوں، کیوں کہ باقی باتیں تو تقریبا ہو گئی ہیں، لیکن آج ہمیں ہر وقت ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے۔ یہاں ٹرپل طلاق کا بل آیا۔

उपसभाध्यक्ष (श्री सुखेन्दु शेखर राय): अभी वह बात छोड़िए, क्योंकि आपका वक्त खत्म हो गया।

मीर मोहम्मद फ़ैयाज: सर, एक-दो मिनट और दीजिए। जब मुसलमानों का विषय होता है, तब एक-दो बातें बोलने दीजिए। ...**(व्यवधान)**... आप देखिए कि आज बलात्कार कितनी रियासतों में हुआ, लेकिन उनके बलात्कारियों को कोई सज़ा नही होगी, लेकिन हमारी...

†**میر محمد فیاض:** سر، ایک دو منٹ اور دیجیئے۔ جب مسلمانوں کا موضوع ہوتا ہے، تب ایک دو باتیں بولنے دیجئیے ---(مداخلت)--- آپ دیکھیئے کہ آج بلاتکار کتنی ریاستوں میں ہوا، لیکن ان کے بلاتکاریوں کو کوئی سزا نہیں ہوگی، لیکن ہماری---

उपसभाध्यक्ष (श्री सुखेन्दु शेखर राय): आप सुनिए। ...(व्यवधान) ... एक सेकेंड, एक सेकेंड ...**(व्यवधान)**... यह जनरल डिस्कशन नही हो रहा है। यह बिल पर डिस्कशन हो रहा है और आपका समय भी खत्म हो चुका है।

मीर मोहम्मद फ़ैयाज: मैं बिल पर ही आ रहा हूँ।

†**میر محمد فیاض:** میں بل پر ہی آرہا ہوں۔

उपसभाध्यक्ष (श्री सुखेन्दु शेखर राय): आपका समय खत्म हो चुका है। ...**(व्यवधान)**...

मीर मोहम्मद फ़ैयाज: मैं वही आ रहा हूँ। ...**(व्यवधान)**... मैं वही आ रहा हूँ। ...**(व्यवधान)**... जब से यह सरकार बनी है, सिर्फ मुसलमान के पीछे पड़े हैं।

†**میر محمد فیاض:** میں وہیں آرہا ہوں ---(مداخلت)--- میں وہیں آرہا ہوں ---(مداخلت)--- جب سے یہ سرکار بنی ہے، صرف مسلمان کے پیچھے پڑے ہیں۔

---

†Transliteration in Urdu script.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY): Please conclude. Please conclude. ...*(Interruptions)*...

मीर मोहम्मद फ़ैयाज : ट्रिपल तलाक के मुसलमान के पीछे पड़े, आज जो बिल लाया गया, मुसलमान के पीछे। ...**(व्यवधान)**... 370, वही एक मुस्लिम majority state है। ...**(व्यवधान)**... महागठबंधन महाराष्ट्र में हुआ, कुछ नहीं हुआ...

†**میر محمد فیاض:** ٹرپل طلاق سے مسلمان کے پیچھے پڑے، آج جو بل لایا گیا، مسلمان کے پیچھے ---(مداخلت)--- وہی ایک مسلم میجارٹی اسٹیٹ ہے ---(مداخلت)--- مہاگٹھبندھن مہاراشٹر میں ہوا، کچھ نہیں ہوا---

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY): Nothing will go on record.

मीर मोहम्मद फ़ैयाज: *

सरदार बलविंदर सिंह भुंडर (पंजाब): सर, आज जो यह अमेंडमेंट बिल आ रहा है, इसकी जरूरत 50 साल पहले से थी। इसका कारण बिल में भी दिया है, लेकिन मैं भी कहना चाहता हूँ कि after 47 and after 71, इसके दो रीज़न्स हैं। पहला उजाड़ा बांगलादेश, पंजाब में after 47 हुआ, दूसरा उजाड़ा 71 के बाद हुआ। 50 साल से minorities के जो लोग इन neighbouring countries से आ रहे हैं, साथ ही और neighbouring countries हैं, वहाँ उनको उनका हक नही दिया गया, वे रो रहे थे, इसलिए आज जो यह बिल लाया गया है, मैं उसका स्वागत करता हूँ कि इससे उन लोगों को रिलीफ मिला है। मैं इसके साथ ही कहना चाहता हूँ कि हम सिख कम्युनिटी को belong करते हैं। हमारे पहले गुरु, गुरु नानक देव हैं, आखिरी गुरु, गुरु गोबिंद सिंह हैं। $ "हमारे गुरु, गुरु ग्रन्थ साहिब हैं। हमारा धर्म भी सेक्युलर है, हमारे देश का संविधान भी सेक्युलर है।

सर, जनेऊ की रक्षा के लिए हमारे नौवें गुरु ने कुर्बानी दी, दसवें गुरु ने अपने बच्चे भी कुर्बान कर दिए। जब हरमिंदर साहिब का नींव का पत्थर रखा गया, वह Sai Mir Mian Mohammed से रखवाया गया। हमारे गुरु ने भी कभी जात-पात के सवाल नही किए, सभी को एक माना। "मानस की जात सभे एके पहिचानबो" आज भी इतनी मार खाने के बाद हम पाकिस्तान, हिन्दुस्तान या दुनिया में कही भी हैं, "नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबत दा भला" ये लफ्ज़ हम हमेशा कहते थे।" इसके लिए मैं होम मिनिस्टर साहब को

†Transliteration in Urdu script.

*Not recorded.

$The Hon'ble Member spoke in Punjab.

[सरदार बलविंदर सिंह भुंडर]

दो सजेशन देना चाहता हूँ। हम चूंकि सबसे ज्यादा माइनॉरिटी हैं, इसलिए सबसे ज्यादा तकलीफ और प्रॉब्लम हमें ही आती है।

सर, मैं दो-तीन प्वाइंट्स कहना चाहता हूँ। आप हर जगह कह रहे हैं कि हम किसी के साथ भेदभाव नही करेंगे और ऐसी बात इस बिल में नजर भी नही आती। सर, हमारे तीन सजेशंस हैं। पहला सजेशन यह है कि इस बिल में जहाँ communities लिखा है, वहाँ religion लिख दिया जाए। जो minority religious communities हैं, वहाँ minorities from neighbouring countries लिख दीजिए। ये दो प्वाइंट्स हुए। सर, तीसरा प्वाइंट यह है कि इसके लिए cut-off date 31 दिसम्बर, 2014 लिखा है, लेकिन जो आज आ रहे हैं, उनका क्या होगा? मैं किसी देश का नाम नही लूँगा, क्योंकि बिल में तीन देश लिखे हैं, उनका नाम बिल में भी लिया गया है और अगर मैं उनके नाम न लूँ, तो फिर भेदभाव होगा। आज भी हमारे सिख भाई बाहर की कंट्रीज़ से आ रहे हैं, ऐसी ख़बरें आप रोज़ सुनते हैं, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि cut-off date के संबंध में आप यह भी clarification दें कि जो लोग आज आ रहे हैं, उनका क्या होगा?

सर, टाइम कम होने के कारण मैं यही कहना चाहता हूँ कि यह देश, बहुधर्मी और बहुभाषी देश है। हम वे लोग हैं, जो मार खाने के बाद भी -- केवल 1947 में एक दफा ही उजाड़ा नही हुआ, बल्कि 1984 में दूसरी दफा भी उजाड़ा हुआ, फिर भी हम देश के लिए लड़ते हैं और जो देश चाहता है, वह हम करते हैं। जब इस देश में इमरजेंसी लगी, तो हमें किसी ने नही पकड़ा, तब हमें बहुत बातें कही गईं। सन् 1972 में जब मैं first time MLA था, तब हमें कई मॉगें ऑफर की गईं, लेकिन हमने कहा कि नही, हम देश के साथ जाएँगे, गुलामी दोबारा आ रही है। ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (श्री सुखेन्दु शेखर राय): कृपया समाप्त करें।

सरदार बलविंदर सिंह भुंडर: इस तरह, हम तो हर दफा देश के साथ खड़े रहे हैं। इसलिए, ऑनरेबल होम मिनिस्टर द्वारा इस बिल को लाए जाने का मैं जहाँ स्वागत करता हूँ, वही मैं सारी opposition parties से यह विनती करता हूँ कि इसके सके लिए जब extra या कोई दूसरा प्वाइंट सामने आ जाए, तो उसे कभी और ले आएँ, लेकिन आज हम सब लोग इक्ट्ठे होकर इस बिल को पास करें। इस बिल में जो कमी रह गई है और मैंने भी जो सजेशंस दिए हैं, उनको दूसरी बार डिस्कस करके फिर लाएँ, ताकि देश smoothly चले और देश आगे बढ़े।

SHRI KAPIL SIBAL (Uttar Pradesh): Mr. Vice-Chairman, Sir, I rise to oppose this Bill. I was very disturbed the other day when the distinguished Home Minister

in the other House explained as to why we need this Bill, that after independence, if the Congress had not done partition on the basis of religion, then, we would not have needed this Bill today. I don't understand which history books the learned Home Minister has read and which authors he has consulted. But I would like to remind him of what Savarkar said. The two-nation theory was not our theory. You are going to fulfil it today by passing this Bill if it is passed. Savarkar said and I quote, "As it is, there are two antagonistic nations living side by side in India. Several infantile politicians commit the serious mistake in supposing that India is already welded into a harmonious nation, or that it could be welded thus for the mere wish to do so. These, our well-meaning but unthinking friends, take their dreams for realities. That is why they are impatient of communal tangles and attribute them to communal organisations." That's not us. The two-nation theory was perpetrated by Savarkar. And this is what Ambedkar said. He said, "Strange as it may appear, Mr. Savarkar and Mr. Jinnah, instead of being opposed to each other on the one nation versus two nations issue, are in complete agreement about it. Both agree, not only agree, but insist that there are two nations in India - one the Muslim nation and the other the Hindu nation." I request the Home Minister to withdraw the allegation because we in the Congress believe in that one-nation theory. You don't believe in it.

सर, गृह मंत्री जी ने सही कहा कि यह एक बड़ा ऐतिहासिक बिल है। हाँ, यह एक ऐतिहासिक बिल है। क्योंकि आप संविधान की बुनियाद को बदलने जा रहे हैं, सलिए यह ऐतिहासिक बिल है। आप हमारे इतिहास को बदलने जा रहे हैं, इसलिए यह ऐतिहासिक बिल है। आपने यह भी कहा कि करोड़ों लोग कल एक नया सवेरा देखेंगे। मैं आपसे यह भी इल्तिजा करना चाहता हूं कि लाखों लोगों की रात खत्म नही होगी, यह काली रात खत्म नही होगी। आप कहते हैं कि आपके प्रधान मंत्री जी सबका साथ और सबका विकास पर विश्वास करते हैं। सबका विश्वास तो उन्होंने खो दिया है, क्योंकि वर्ष 2014 से लेकर अब तक सब का साथ उन्होंने कभी नही दिया। You said: 'Rise above politics.' I request you, Home Minister, you rise above politics because this is nothing but politics. You are destroying the future of this country. Sir, I have following things to say about my objections to this Bill. First, this Bill gives legal colour to the two nation theory, which I have already stated.

Secondly, religion cannot be a factor in the acquisition of citizenship. That

[Shri Kapil Sibal]

has been rejected by the Constitution of India. Sir, there are three concepts that you must understand, which is the basis of citizenship. Number one, I was born in the territory of India. Number two, my parents were born in the territory of India - descent. Number three, I am ordinarily resident in the territory of India. There is no fourth concept on the basis of which citizenship can be granted. I might tell you something very interesting. I belong to a family which used to live in Lahore. I was born here in 1948 but my brothers, my sister, my parents, my grandparents were all born in Pakistan. We were all refugees. When we came to India, we were not citizens of India. Why, because we were not born in the Republic of India. Therefore, we were not citizens of India. There was a provision in the Constitution which said that if you are born in undivided India, as defined in the Government of India Act of 1935, then, you shall be a citizen of India, but that was not the only thing. I had to become a resident of India. I should have come to India six months prior to July 19, 1948. If I had come to India six months prior to that, I would have been a citizen of India. So, resident, ordinary resident, *bona fide* resident is an essential element for being a citizen. For those who came after the 19th of July, 1948, they had to file an application before an appropriate authority. In that application, before they filed it, they should have been resident of India for the last six months. They too could not get citizenship. Sir, that is the basis and the foundation of citizenship. That is why, Mr. Chidambaram asked, who has advised you to do all this? Who has advised you? Who has given you that opinion, the Law Ministry or the Attorney General?

Let me tell you something else now, Sir. Under Article 11 of the Constitution, there is a provision which says that through another Act, through a law made by Parliament, somebody can acquire citizenship or terminate citizenship. Now, the Citizenship Act 1955 has some very interesting provisions. Let me just tell you a couple of them. The Citizenship Act says that if you are born in the territory of India between January 26, 1950 to July 1, 1987, you shall be a citizen of India. If you are born in the territory of India between July 1, 1987 and the time when the 2003 Citizenship (Amendment) Bill has been passed, which was passed in 2004 and which is the Citizenship (Amendment) Bill Act 2003, you shall be a citizen of India, if one of your parents is a citizen of India. And if you are born after 2004, you

shall be a citizen of India, if one of your parents is a citizen of India and the other is not an illegal migrant. That is the condition of the Citizenship Act. If one of the spouses is an illegal migrant, you cannot be a citizen of India.

Now, Sir, what Amendment have you brought? Just think about it. What does your Amendment say? Let me just tell you what it says. I am sure you have read it. You are making an Amendment to Section 2(1)(b). It says: "Provided that any person belonging to Hindu, Sikh, Buddhist, Jain, Parsi or Christian community from Afghanistan, Bangladesh or Pakistan, who entered into India on or before the 31st day of December, 2014 and who has been exempted by the Central Government by or under clause (c) of sub-section (2) of section 3 of the Passport (Entry into India) Act, 1920 or from the application of the provisions of the Foreigners Act, 1946 or any rule or order made thereunder, shall not be treated as illegal migrant for the purposes of this Act;" Now, please tell me, the Foreigners Act deals with people who are declared to be foreigners. The Passport (Entry into India) Act deals with people who have entered into India without a valid document. Now, in your Statement of Objects and Reasons, you have said that these are all people who have been persecuted on the grounds of religion. Where is the provision for persecution in the Act? There is no provision for persecution. If a man came from Bangladesh or from Pakistan into India in 1972 and he is being an illegal migrant after 1972 till date; how will he prove, how will you say that he has been persecuted unless he says that he was persecuted? Amongst all the people who have come to India without any legal documentation; has anybody said that they have been persecuted? Do we have a law here which says that you apply and say that you are persecuted and you shall be granted citizenship? It is very interesting, Shri Nadda, in the course of his speech, mentioned Dr. Manmohan Singh and what he said. But, he didn't mentinon what Advani*ji* said. I wish he had because Dr. Manmohan Singh had said, "Look if people have been persecuted and they have come from our neighbouring countries; you must give them citizenship." उनको नागरिकता मिलनी चाहिए। आडवाणी जी ने क्या कहा, मैं उसके बारे में आपको बताता हूं, "There were various kinds of allegations made that 'you are making discrimination between this and that' which we do not propose to do. We always say that a person who has to flee because of religious persecution is a refugee, *bona fide* refugee, and he cannot be regarded on par with the illegal immigrant who may have

[Shri Kapil Sibal]

come here for any reason, even for economic reasons. If he is an illegal immigrant, he is an illegal immigrant." This is what Advaniji said. Now, if these people are illegal immigrants on what basis, you say that they have been persecuted? Has anybody said that they have been persecuted? There are also other illegal immigrants. I won't name the religion they belong to who have also come; who are also illegal immigrants. So, how do you discriminate between one illegal immigrant and another illegal immigrant? How do you say, आप कैसे कह सकते हो कि ये लोग तो persecute हुए थे। मैं उदाहरण देता हूं- एक शख़्स यहां 1972 में आया। उसके दो-तीन बच्चे हैं और उसकी मृत्यु हो गई। आज वह जिंदा नही है, लेकिन उसके बच्चे कहते हैं कि हमें सिटिज़नशिप दो। आप कैसे देंगे? ...**(समय की घंटी)**... जिसकी मृत्यु हो गई है, उसने पहले कभी कहा ही नही कि वह persecute हुआ था। फिर उसके बच्चों को सिटिज़नशिप कहां से मिलेगी? उनको सिटिज़नशिप किस आधार पर देंगे? उसका मापदंड क्या है? ये लाखों लोग हैं, जिनकी आप बात करते हो। हम 19 लाख लोगों की बात करते हैं, उनमें कितने हिंदू हैं, 5 लाख हैं, 6 लाख हैं, 10 लाख हैं, 12 लाख हैं, मैं उसके बारे में बात नही करूंगा। किसी हिंदू ने कहा है कि मैं persecute हुआ था। आपको बहुत गलतफहमी है। उन्होंने अपने legacy papers में कहा है कि मैं तो यहां का रहने वाला हूं। ...**(समय की घंटी)**... सर, उन्होंने declaration दिया है कि मैं तो यहां का रहने वाला हूं। आप उसको इस विधेयक के द्वारा असत्य बुला रहे हो।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY): Please conclude.

SHRI KAPIL SIBAL: Sir, one second.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY): Four more speakers are left from your party.

श्री कपिल सिब्बल: जो शख़्स कह रहा है कि मैं तो हिंदुस्तान का रहने वाला हूं, आप उसको कहना चाहते हो कि नही, तुम हिंदुस्तान के रहने वाले नही हो, तुम तो बंगलादेश से आए थे और क्योंकि persecute हो रहे थे, इसलिए हम आपको सिटिज़नशिप देंगे। यह किस किस्म का कानून है? आप संविधान के साथ क्या कर रहे हो? आप संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हो। आपका मकसद क्या है? हमें मालूम है कि 2014 से आपका मकसद क्या रहा है? कभी घर-वापसी, कभी लव-जिहाद, कभी ट्रिपल तलाक, कभी सी.ए.बी., कभी एन.आर.सी, फिर दोबारा एन.आर.सी. और फिर 370, आपका लक्ष्य हमें मालूम है, आपका नज़रिया भी मालूम है। ...**(समय की घंटी)**... आप किसी के नाम से पता करना चाहते हैं कि

इस देश में वह रहेगा या नही रहेगा। आपने शुरुआत में एक बड़ी आपत्तिजनक बात की। आपने कहा कि जो मुसलमान यहां हैं, उनको डरने की जरूरत नही है। किस मुसलमान को आपसे डर है? हिंदुस्तान का कोई मुसलमान आपसे नही डरता है। न मैं डरता हूं, न इस देश के नागरिक डरते हैं और न कोई मुसलमान डरता है। अगर हम डरते हैं, तो हम संविधान से डरते हैं, जिसकी आप धज्जियां उड़ा रहे हो।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY): Mr. Sibal. ...*(Interruptions)*...

SHRI KAPIL SIBAL: Sir, I am just finishing. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY): There are four more speakers from your party. ...*(Interruptions)*...

SHRI KAPIL SIBAL: Sir, I am finishing. ...*(Interruptions)*... My third point is this. In this Bill, they are targeting a community without naming it. It violates the basic structure of the Constitution. It is divisive and exclusive. It will destabilise our polity and 18 to 20 million people will not trust us. It weakens the foundation of our culture, beliefs and ethos. It has consequences that you cannot even imagine and this is part of your political strategy. The last thing I want to say is this. This is legally tenable and morally reprehensible. Those who have no idea of India cannot protect the idea of India. Don't convert this Indian Republic into a Jurassic republic, where there are two dinosaurs. Thank you.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY): Before I call the next speaker, this is for the information of the Leader of the Congress party that only 17 minutes are left for the remaining speakers of your party. So the time will be allocated accordingly. Now, Ms. Saroj Pandey.

सुश्री सरोज पाण्डेय (छत्तीसगढ़): धन्यवाद उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आज इस नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2019 के समर्थन में खड़ी हुई हूं। आज संसद में यह एक ऐतिहासिक दिन है। इस ऐतिहासिक दिन के अवसर पर मैं इसकी भागीदार हूं और मुझे इसमें हिस्सा लेने का अवसर मिला है, यह मेरे लिए गौरव का विषय है। ...**(व्यवधान)**...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY): Excuse me. ...*(Interruptions)*... This is not the way. A lady is speaking. You should honour her.

सुश्री सरोज पाण्डेय: महोदय, पिछले 6 माह से भारत की संसद में जिस प्रकार से निर्णय हुए हैं, ये भारत को आगे बढ़ाने वाले कदम हैं। माननीय उपसभाध्यक्ष जी, मैं इस बात को कहना चाहती हूं कि बहुत से ऐसे विषय थे, जो लम्बित थे, जिनकी ओर पूरा देश आशा भरी निगाहों से देखता रहा, लेकिन ऐसे विषय कई बार पूर्ण नही हो पाए, वे राजनीति की बलि चढ़ गए और राजनीति की बलि चढ़ने के कारण जब ऐसे विषय नही हो पाते थे ...**(व्यवधान)**...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY): Mr. Bajwa, please go to your seat. ...*(Interruptions)*...

सुश्री सरोज पाण्डेय: तो जनता उन विषयों पर कुछ कह नही पाती थी, मन मसोसकर रह जाती थी। मैं आज इस सदन में आपके माध्यम से भारत के प्रधान मंत्री जी का और भारत के गृह मंत्री जी का अभिनंदन करना चाहती हूं कि हज़ारों-हज़ार देश के नागरिक, जो पीड़ित हैं, प्रताड़ित हैं, जिन्होंने बहुत आस के साथ इस देश में पनाह ली और यह सोचकर पनाह ली कि इस देश की धरती हमारी रक्षा करेगी, लेकिन उस समय इस देश के जो शासक थे, उन्होंने उन्हें नागरिकता का अधिकार नही दिया।

माननीय उपसभाध्यक्ष जी, मैं यह विषय कहना चाहती हूं कि हमारी सरकार ने तुष्टिकरण की राजनीति नही की। अगर हमने केवल तुष्टिकरण की राजनीति की होती तो आज यहां पर इस सदन में बैठकर विपक्षी दल के नेता हमसे सबूत नही मांगते। मुझे यह विषय समझ में नही आया कि इस सदन में बैठकर सबूत मांगने का विषय आखिर आया कहां से? जो आंकड़े दिखा रहे हैं, क्या वे आंकड़े यह समझने के लिए पर्याप्त नही हैं कि जो जनसंख्या ज्यादा थी, वह जनसंख्या अगर कम हुई, इस धरती पर रहने वाले लोग, जो अन्य देशों में रहते थे, वहां पर पहले अगर वह संख्या ज्यादा थी और वह संख्या कम हो गयी तो वह गयी कहां - उसे धरती निगल गयी या आसमान फट गया, उसमें समा गयी? ये आंकड़े इस बात को प्रतिपादित करने के लिए, प्रमाणित करने के लिए तय हैं, इसलिए विपक्षी दल के जिस नेता ने अभी-अभी इस विषय पर सबूत मांगा, मैं उन्हें कहना चाहती हूं कि यह बहुत पीड़ादायक है। कई बार ये परिस्थितियां पैदा होती हैं, जब कभी - अगर हम वकीलों की भाषा में कहें - लोग इस विषय को पूछते हैं कि कोई घटना घटी तो कैसे घटी, क्या हुआ, लेकिन जब किसी महिला के साथ वह घटना घटती है और उस महिला से पूछा जाता है कि घटना कैसे घटी, तो जितनी बार उससे पूछा जाता है, उतनी बार वह महिला प्रताड़ित होती है, बार-बार प्रताड़ित होती है, उतनी बार वह मरती है। यह सबूत मांगने का इस सदन में इस प्रकार का दुस्साहस करना, मेरा मानना है कि यह उसी का प्रमाण है कि ये उस प्रकार से भारत देश के नागरिकों को बार-बार प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं।

4.00 P.M.

भारत देश में हमेशा से शरणार्थियों की रक्षा की गई है। इस बात का इतिहास गवाह है। भारत का इतिहास बहुत समृद्धिशाली है और भारत की जो सरकार है, वह भारत की संस्कृति को समेटकर, भारत की संस्कृति के साथ-साथ संविधान को अपने संरक्षण में लेकर, संविधान को संरक्षित करते हुए, सबका साथ, सबका विकास करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। नागरिकता (संशोधन) विधेयक के माध्यम से, जो हजारों-हजार... मैं इस विषय में आने से पहले जब भारत का विभाजन हुआ, उस समय में ले जाना चाहती हूं। जब भारत का विभाजन हुआ, उस समय महिलाओं के सामने जो घटना घटी, वे महिलाएं जब भारत के विभाजन के समय भारत की तरफ आईं और नेहरू-लियाकत अली जी का जो समझौता हुआ, इस समझौते में भारत हमेशा ठगा गया। बहनों के साथ जिस प्रकार की घटनाएं घटी, वे घटनाएं इतिहास में माफ करने के योग्य नही हैं। इन विषयों पर हम बात कर सकते हैं, लेकिन नेहरू-लियाकत अली का वह समझौता, जिसमें हमें सरक्षण देने की बात की गई थी, भारत के वे हजारों हिंदू नागरिक, हिंदू बहनें, जिनकी छातियां काट डाली गईं, लेकिन किसी ने उस समय केवल राजनीति के कारण बोलने का दुस्साहस नही किया। आज इतने वर्षों के बाद किसी सरकार ने ईमानदारी के साथ प्रयास किया कि सच में भारत का जो नागरिक है, जो भारत की धरती में पैदा छुआ है, अगर वह हिंदू है, तो उसका संरक्षण होना चाहिए। इसलिए इस नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2019 को भारत की सरकार लाई है। मैं अपने प्रधान मंत्री जी को और अपने गृह मंत्री जी को फिर से अभिनंदन करती हूं। मैं एक बात कहना चाहती हूं। विपक्षी दल की एक प्रमुख महिला नेत्री ने एक ट्वीट किया। इस ट्वीट को पढ़कर मुझे इस बात का बेहद आश्चर्य था, उन्होंने अपने ट्वीट में कहा, यह ऑन रिकॉर्ड भी है, उन्होंने कहा कि यह कट्टरता की पराकाष्ठा है। मैं उस विषय को पूछना चाहती हूं कि उस दिन वह क्यों चुप रह गईं, जब 400 सीटों के साथ रूढ़िवादी मुक्त प्रधान मंत्री इस देश की संसद में बैठे और इस देश की संसद में जब वह बैठे, तो शाहबानो के प्रकरण पर कट्टरपंथ के आगे जब उन्होंने सिर झुका दिया, उस दिन यह ट्वीट करने वाली प्रमुख दल की वह महिला नेत्री चुप क्यों रह गईं, उनका परिवार चुप क्यों रह गया? मैं आज इस विषय को पूछना चाहती हूं। आप इस सदन में राजनीति की बात करते हैं। हमने कभी राजनीति नही की। नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2019 मानवीय आधार पर लाया गया है। यह मानवता की बात है। मैं आपको इस बात को कहना चाहती हूं कि जब हम यहां पर बैठते हैं, यह वह संसद है, जो इतिहास रचती है। यह वह संसद है, जिसमें आपकी ओर देश का हर नागरिक देखता है और अगर आपने ईमानदारी से बात कही, तो मुझे लगता है कि उन बातों को कही न कही जनता सुनती है और यह मानती है कि आप उसका हित संरक्षित कर रहे हैं। मैं धन्यवाद देती हूं, हमारे सदन में

[सुश्री सरोज पाण्डेय]

अभी मेरे पूर्व वक्ता ने इस विषय को कहा कि हमारे गृह मंत्री जी से कोई नही डरता है। हमने नही कहा कि किसी को मृह मंत्री जी से डरना चाहिए।

(उपसभापति महोदय *पीठासीन हुए)*

हमेशा और हमेशा उसी तरफ से यह आवाज आती है, अगर यह आवाज हमेशा उस तरफ से आई, आज आपने इस बात को स्वीकार किया, आपको धन्यवाद है, आपको बधाई है। अभी वे नेता सदन में नही हैं, लेकिन मैं यह बात जरूर कहना चाहती हूं कि आपके माध्यम से जब भी उन्होंने इस विषय को कहा है कि उनसे कोई नही डरता, हम नही कहते कि आप डरिए, हमने कभी नही कहा। जिस व्यक्ति ने ईमानदारी से काम किया है, उससे डरने की जरूरत नही पड़ती है, लेकिन आपके दल के जिन नेताओं ने इन विषयों को कहा है, आप कम से कम उन्हें माफी मांगने के लिए तो कह ही सकते हैं और यह बात जरूर होनी चाहिए, ऐसी मेरी अपेक्षा है। आज जब यह बिल संसद में पारित हो जाएगा, मुझे लगता है कि वह परिवार, जिसने अत्याचार, अपमान और शोषण झेला है, अब आज के बाद वह स्वाभिमान के साथ भारत के नागरिक बन जाएंगे। उन्हें वे सब सुविधाएं मिलेंगी, जो भारत के नागरिक को मिलती हैं। यह सही है कि इसके लिए किसी का कोई अधिकार नही छीना जा रहा है। माननीय उपसभापति महोदय, किसी पीड़ित और किसी शोषित को न्याय दिलाना, मानवता की सेवा है। हमने यह सेवा करने का एक संकल्प लिया है। भारत की सरकार द्वारा संकल्पित होकर इस संशोधन विधेयक को लाया गया है। यह संशोधन विधेयक आज से 50 साल पहले आना चाहिए था, लेकिन इतने लम्बे समय के राजनीतिक काल-खंड में, आज तक इस प्रकार के संशोधन विधेयक को लाने की हिमाकत उस वक्त की सरकारों ने नही की। अगर यह पहले हुआ होता, तो जो पीड़ित परिवार थे, वे कई वर्ष पहले स्वाभिमान के साथ भारत के नागरिक कहलाते।

महोदय, मैं आपके माध्यम से कुछ आंकड़े सदन के समक्ष प्रस्तुत करना चाहती हूं। पाकिस्तान, बंगलादेश और अफगानिस्तान में जिन लोगों को धार्मिक आधार पर भेदभाव और जुल्मों का सामना करना पड़ा, वहां पर रहने वाले जो नागरिक थे, यह इस बात से समझा जा सकता है कि पाकिस्तान में 1947 में 23 प्रतिशत अल्पसंख्यक थे। वर्ष 2011 में वे घटकर 3.7 प्रतिशत रह गए। बंगलादेश में 22 प्रतिशत थे, जो वर्ष 2011 में 7.8 प्रतिशत रह गए। मैंने ये आंकड़े आपके समक्ष इसलिए रखे कि ये आंकड़े इस बात को प्रतिपादित करते हैं कि वहां पर रहने वाले जो लोग हैं, उनके साथ जुल्म किया गए। जब हम कही पर रहने के लिए जाते हैं, तो हमें सुरक्षा चाहिए होती है, हमारी मूलभूत सुविधाएं चाहिए होती हैं, हमें रोजगार चाहिए होता है और जब हमें ये सब चीजें मिलती हैं, तो हम इन

विषयों पर वहां पर रहने के काबिल माने जाते हैं। लेकिन इन विषयों के साथ-साथ, जो एक सबसे बड़ा विषय है, चूंकि मैं महिला हूं, इसलिए मैं इस विषय के बारे में कहना चाहती हूं कि जब हम वहां पर रहते हैं, लेकिन जब हमारी ही बेटियां सुरक्षित नही हैं, तो लोग वहां से सीधे और सीधे पलायन करना चाहते हैं। यह विषय केवल और केवल मानवता के साथ-साथ इस बात का भी है कि हमारी बेटियों की आबरू सुरक्षित रहे। इसलिए लोगों ने वहां से पलायन किया है। मैं इस सदन में इस बिल को सर्वसम्मति से पारित करने की अपील करती हूं, धन्यवाद।

SHRI VAIKO (Tamil Nadu): Sir, the Father of the Nation, Mahatma Gandhi's bones would have turned over in the cremation ground on the banks of Yamuna seeing what is happening in Parliament. If this obnoxious, abominable, undemocratic, unreasonable, unpardonable, unjustifiable unconstitutional Bill is passed today in this Council of States, that will become a black chapter in the annals of this Upper House.

The Citizenship Amendment Bill singles out a community for hostile treatment. In short, the Bill chooses to open its citizenship door to non-Muslims from three nations with a Muslim majority—Pakistan, Bangladesh and Afghanistan.

A key argument against the CAB is that it will not extend to those persecuted in Myanmar and Sri Lanka from where Rohingya Muslims and Tamils are staying in the country as refugees. Further, it fails to allow Shia and Ahmadiyya Muslims, who also face persecution, to apply for citizenship.

This is an assault on equality, assault on secularism, assault on democracy. 1,047 scientists and scholars from India and abroad have signed an open letter on Monday condemning the Citizenship Amendment Bill, while also asking for its immediate withdrawal. The signatories include directors of major research institutions like Rajesh Gopakumar of International Centre for Theoretical Sciences, Sandip Trivedi of Tata Institute of Fundamental Research, Ramon Magsaysay Award recipient Sandeep Pandey and S.S. Bhatnagar awardee Atish Dabholkar and some other signatories like Rukmini Bhaya Nair, Zoya Hasan, Harbans Mukhia. "The idea of India that emerged from the Independence Movement, and as enshrined in our Constitution, is that of a country that aspires to treat people of all faiths equal. The use of religion as a criterion would be inconsistent with the basic structure of

[Shri Vaiko]

the Constitution. We fear, in particular, that the careful exclusion of Muslims from the ambit of the Bill will greatly strain the pluralistic fabric of the country", they say.

Sir, I accuse this Government of deliberately rejecting the Eelam Tamils. Due to * of the Sri Lankan Government, they came to Tamil Nadu and are living here for nearly 30-40 years. * are shaking hands with the Government of India which is piercing the hearts of the Tamils with poisonous sword. This Bill should be thrown into the Bay of Bengal.

SHRI K. G. KENYE (Nagaland): Sir, I rise to support the amended Citizenship Bill of 2019 and I will tell this House why I am supporting this Bill. I come from ground zero, the epicentre of this controversy. The issue has been taken off the context completely. What is real at the regional level on the ground and what is happening at the national level has taken a completely different turn, a new dimension here, whereas our people in the North-East have no religious bias. We are not communal and our sole objective of having staged this agitation is on the Centre's inaction over a period of 48 years. I would request leaders of all political parties to kindly refocus again on the core issue of this Bill. It is not about religion. It is not about any majority or minority communities. It is about those illegal immigrants who have come into our region and are threatening to over-run our population which is only about four per cent of this country. So, we have our fears and apprehensions that if the Centre does not take a closer look and consider our genuine fears early, if it continues to sit over those policies which were in place during the colonial era, and young India never takes a second look, then, it will be catastrophic where one day an irreversible situation may develop within us, *i.e.* the mainland and this region. We are inalienably attached to our land. So, there will be no exodus towards further East, North or South. Our territory will always accompany us wherever we settle. So, this is a threat to the integrity of the nation. It has serious political implications. I would request that they should take a genuine second look at this problem. We have two layers of immigrants. One, of course, is due to the East India Company's political interest. Throughout the 19th century which had percolated over to the 20th century also, they have brought in. ...*(Time-bell rings)*... Please, Sir, you must give little more time.

---

*Expunged as ordered by the Chair.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You can take one more minute.

SHRI K. G. KENYE: All right, Sir. So, to serve the commercial interest, they had brought in hoards and millions of labourers to this region. Many are unaccounted for and not recorded, but the tea plantation was taken up extensively and they cultivated one lakh hectares of land of tea at its height in Assam. You can imagine how many hands and labourers they must have brought in from outside to ensure the purpose of their commercial interests there. That is the first layer. The second layer is the War of 1971 with Pakistan for the liberation of the present Bangladesh. When the war was fought, — we did win the war — the North-Easterners acted as the arrowhead to penetrate into the first line of defence of our adversaries. We lost many soldiers and this also attributed to the victory of this country on a full-fledged war after our independence. The glory and honour has been shared by all citizens of this country. It is a crown on the hat of the people who were there.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude now.

SHRI K. G. KENYE: But when it came to the consequences and the by-products of the war, the entire burden was dumped on the heads of the North-East. The Government of India never took a second look for a half a century.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I am calling the next speaker now.

SHRI K. G. KENYE: Sir, we are supporting this Bill today, because our interest has been partially addressed. *

MR. DEPUTY CHAIRMAN: It will go on record now.

SHRI KANAKAMEDALA RAVINDRA KUMAR (Andhra Pradesh): Thank you Mr. Deputy Chairman, Sir, for giving me this opportunity to speak on this Bill.

The Citizenship (Amendment) Bill provides certain groups of illegal migrants, as per the provisions of the Citizenship Act, 1955, to become eligible for applying Indian citizenship. It also proposes to reduce the required period of residence in India under naturalisation in the principal Act.

---

*Not recorded

[Shri Kanakamedala Ravindra Kumar]

Now, before making history, history has to be looked into. I request the hon. Home Minister to clarify these issues. On 26th September, 1947, Mahatma Gandhi openly promised and declared that the Hindus and Sikhs staying in Pakistan can come to India by all means, if they do not wish to continue there. In that case, it is the first duty of the Indian Government to give them jobs and make their lives comfortable. Another issue is relating to Pandit Jawharlal Nehru's assurance in Parliament on 5th November, 1950. Likewise, Shri Guljarilal Nada made a statement on 5th March, 1954 in the Rajya Sabha. And, Shri Tarun Gogoi submitted a Memorandum demanding citizenship for Hindu migrants to Dr. Manmohan Singh. Sir, during declaration of Independence, the first Prime Minister of Independent India said on the Citizenship Amendment Bill and I quote:

> "We also think of our brothers and sisters cut off from us by political boundaries and who unhappily cannot share at present in the freedom that has come. They are of us and will remain of us whatever may happen, and we shall be sharers in their good and ill fortune alike."

Similarly, on 6th December, 2007, the then External Affairs Minister, Shri Pranab Mukherjee made a statement and I quote:

> "Reports of violence and atrocities against minorities including Hindus in Bangladesh are received from time to time. It has been conveyed at the highest levels of Government that such incidents have an adverse impact on public sentiment in India, which in turn have the potential of affecting bilateral ties, and should be strictly dealt with."

And, Sir, the then External Affairs Minister, Shri S.M. Krishna, made a statement in the Rajya Sabha on 6th May, 2010, and I quote:

> "It is the responsibility of the Government of Pakistan to discharge its obligations towards its citizens, including minorities. However, based on reports of persecution of minority groups in Pakistan, the Government had taken up the matter with the Government of Pakistan."

And, Sir, the then Minister of State for External Affairs, Shri E. Ahmad, on 22nd March, 2012, said and I quote:

"The Government has seen media reports about killing of Hindu doctors in Pakistan on November 7, 2011. President of Pakistan has stated that it was the moral and legal responsibility of the Government of Pakistan to protect the minority community against vandalism and atrocities. He has said that law would take its course and culprits will not go unpunished."

Sir, similarly, the Assam Pradesh Congress Committee passed a Resolution and I quote. ...*(Time-bell rings)*...

"We will take up the unresolved issue of citizenship for Bengali Hindus, Buddhists, Christians and people of other minority communities who came to Assam after being subjected to inhuman torture post the partition of India."

The citizens of India are now apprehending consequences of this Bill due to discrimination on two grounds — constitutional validity and legislative competency.

The question to be answered by the hon. Home Minister is, whether this Bill gives any protection and security to Muslims. And, Muslims should not be discriminated under the guise of the Citizenship Act. We have to see that there is a reasonable classification and having a rational nexus to the objectives sought to be achieved in a fair manner.

With these words, I once again thank you for giving me this opportunity and, on the whole, I support this Bill. Thank you.

श्री संजय सिंह (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली): श्रीमन्, आपने इस बहुत ही महत्वपूर्ण बिल पर अपनी बात कहने का मुझे अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद। मान्यवर, मैं इस बिल के विरोध में अपनी बात कहने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं इस बिल का विरोध इसलिए कर रहा हूं, क्योंकि यह बाबा साहेब डा. भीमराव अम्बेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान के विरुद्ध है, भारत के संविधान में लिखी गई प्रस्तावना के विरुद्ध है और साथ ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और शहीदे आज़म भगत सिंह के सपनों के भारत के विरुद्ध है।

मान्यवर, आपके सामने अभी सत्ता पक्ष के द्वारा कहा गया कि पाकिस्तान में रहने वाले हिन्दुओं की हमें चिंता है, अफगानिस्तान में रहने वाले हिन्दुओं की हमें चिंता है और जो माइनॉरिटीज़ बंगलादेश में हैं, उनकी चिंता है। मैं आपके माध्यम से इस सरकार से बड़ी विनम्रता के साथ यह पूछना चाहता हूं कि आपको गुजरांवाला में रहने वाले हिन्दुओं की चिंता है, तो कीजिए और करनी भी चाहिए, लेकिन आपके गृह राज्य गुजरात में पूर्वांचल के

[श्री संजय सिंह]

हिन्दू मारे गए, बिहार और यूपी के हिन्दू मारे गए, पीटे गए और वहां से भगा दिए गए, उनके बारे में तो आपने एक शब्द भी नही बोला। पहले आप इस सदन में इसका कारण बताइए। आप अपना स्टेटमेंट दिखाइए।

मान्यवर, आज आपने असम के अंदर NRC लागू की और 19 लाख लोगों को बाहर कर दिया, जिनमें लाखों की संख्या में पूर्वांचल के लोग हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग हैं, जिनका रिकॉर्ड आज न यूपी में है, न बिहार में है और न ही असम में है। चूंकि आपने 1971 से पहले का रिकॉर्ड मांग लिया, तो वहां भी उनका रिकॉर्ड नही है, जिसके कारण अपने ही देश में वे विदेशी घोषित हो गए हैं। आप बंगलादेश से आने वाले हिन्दुओं को तो नागरिकता देंगे, लेकिन असम में रहने वाले यूपी और बिहार के वे लाखों नागरिक, जिनकी नागरिकता इस NRC के चलते खत्म हो गई, उनका क्या करेंगे? इस बिल में आपने इसके बारे में कुछ नही कहा है। आपने कहा कि आप पूरे देश में NRC लागू करना चाहते हैं और घुसपैठियों को भगाना चाहते है। दूसरे सदन में बार-बार कहा गया कि घुसपैठियों को भगाना है, घुसपैठियों को भगाना है। मान्यवर, मैं आपको दो बयान दिखाऊँगा, जिनमें से एक माननीय प्रधान मंत्री जी का बयान है, जो 28 सितम्बर को दिया गया था। अमरीका में बंगलादेश की प्रधान मंत्री, शेख हसीना के साथ मीटिंग करने के बाद हमारे प्रधान मंत्री जी ने कहा था कि NRC will not impact Bangladesh. NRC बंगलादेश पर कोई प्रभाव नही डालेगा। दूसरा बयान विदेश मंत्री जी का है। उनका यह बयान 20 अगस्त का है। ढाका, बंगलादेश में विदेश मंत्री, एस. जयशंकर जी ने कहा है कि NRC हमारा internal matter है, आंतरिक मामला है। आप कहते हैं कि घुसपैठियों को भगाएंगे, लेकिन आप स्वयं कह रहे हैं कि यह आपका आंतरिक मामला है। इसका मतलब है कि मान लीजिए अगर आपको घुसपैठिए मिल गए, अगर आपको दो करोड़ घुसपैठिए मिल गए, तो आप हिन्दुस्तान के अन्दर एक घुसपैठिया देश बनाएंगे और घुसपैठिया देश बना कर उन घुसपैठियों को रख कर देश की जनता के टैक्स पेयर्स के पैसे से ...**(समय की घंटी)**... उनके लिए बिजली फ्री, पानी फ्री, चिकित्सा फ्री, शिक्षा फ्री करेंगे। आप करना क्या चाहते हैं? इस देश में अपनी सनक को पूरा करने के लिए आप कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। यह देश को तोड़ने की आपकी संस्कृति है। मान्यवर, हिन्दू धर्म, जिसको हम मानते हैं, जिसको हम जानते हैं, वह 'वसुधैव कुटुम्बकम्' की बात कहता है। वह कहता है कि पूरा विश्व हमारा परिवार है। हम उस अवधारणा को, उस धर्म को मानने वाले लोग हैं। हम किसी के साथ भेद और नफरत की बुनियाद पर हिन्दुस्तान को नही बनाना चाहते हैं।

श्री उपसभापति: संजय जी, आप conclude कीजिए।

श्री संजय सिंह: मान्यवर, यहां पर दो-तीन बातें कही गईं। यहां कहा गया कि hindu

minorities के साथ अत्याचार हुआ। बंगलादेश के प्रधान मंत्री के साथ इतनी मीटिंग्स हुईं, आज आप बताइए कि कब आपने या प्रधान मंत्री जी ने या विदेश मंत्री जी ने कभी एक बार भी hindu minorities के अत्याचार का मुद्दा उनके सामने उठाया हो, आप उसका ज़िक्र कीजिए। ...**(समय की घंटी)**...

अंत में मैं कहना चाहूंगा कि आपकी सरकार को साढ़े पांच साल हो गए। आप कह रहे हैं कि हम घुसपैठियों को भगाएंगे, लेकिन गृह मंत्री जी, जब आप वक्तव्य दीजिए, तो साढ़े पांच साल में अगर आपने साढ़े पाँच घुसपैठिए भी भगाए हों, तो उनके नाम बता दीजिए। ...**(समय की घंटी)**... आप उनके नाम बता दीजिए।

श्री उपसभापति: धन्यवाद।

श्री संजय सिंह: इसका मतलब आप इस देश को अपनी सनक से चलाना चाहते हैं, आप इस देश को तोड़ने की संस्कृति में यकीन रखते हैं, ...**(समय की घंटी)**... नफरत फैलाने की संस्कृति में यकीन रखते हैं। इस सोच को, इस विचार को बंद कीजिए। आम आदमी पार्टी इसीलिए इस बिल का विरोध कर रही है कि यह इस देश के संविधान की मूल आत्मा को नष्ट करने वाला बिल है।

SHRI BINOY VISWAM (Kerala): Mr. Deputy Chairman, Sir, the Sun will rise tomorrow also. The Home Minister was saying that the Sun will rise tomorrow with a ray of hope. I beg to differ from him. The Sun will rise tomorrow seeing a sword of Damocles hung over the head of secular India, and at any moment, the people would fear, it may fall down. That is why, from the Communist Party of India, I oppose this Bill. The time is too short. The reason behind the Bill is very clear. I have a quote from none other than Guruji Golwalkar. I won't suspect his ideology but I respect him for his 100 per cent honesty and his lack of hypocrisy. In 'Bunch of Thoughts, in Chapter 16, he deals with internal threats of the country. According to him, the number one threat from inside the country is the Muslims. It says, "it has been the tragic lesson of the history of many a country in the world that the hostile elements within the country pose far greater menace to national security than agressors from outside." I request the hon. Minister to clarify whether he stands with that view or not. It is very important because we often hear about the Hindu *rashtra,* which is going to be started by the RSS ideology in this country. On this also, Golwalkar*ji* has narrated to the minorities that they need not to have any worry about that. He says nothing to worry about this provided — there is a proviso —

[Shri Binoy Viswam]

you minorities subscribe to the religion, language and culture of the country. I may ask: What is the religion of the country of India? This country has no religion of its own. That is why we are all taught to say that this is a secular country. The country has no religion; people may have religion. Their faith may vary, but the country supports all of us. That is the beauty of India.

That is the greatness of India. The moment we say about the religion for the country, that means the end of India.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude.

SHRI BINOY VISWAM: I remember the words of Pandit Nehru. He wrote, "If India lives, no one will die; if India dies, all will die." I fear this Bill will lead to the death of India. So, don't kill India. Let the people of India live for ever. Let this great country march forward. This Bill will be a hindrance to that march in future. So, I object to this Bill. I conclude. Thank you, Sir.

SHRI RITABRATA BANERJEE (West Bengal): * Sir, I rise to oppose the Bill. During 1970-71, a large number of people were compelled to flee from East Pakistan. They did not come to India because of reasons related to religion. The Bengalis, the Bengali-speaking people, had to cross the barbed fencing out of fear for life as the rulers of Pakistan, the Khan Sena and the Razakars of Pakistan had declared a war against Bengal and the Bengali-speaking population. More than one crore people had come across from East Bengal to West Bengal as refugees at that time. Sir, it has now been said in this Bill that the period of validity of Passport and other such documents would be extended. But think of this, how could the people fleeing away for fear of life were expected to carry with them the documents during those trying times? It was simply not possible. Sir, the then Prime Minister of India, Smt. Indira Gandhi, played a significant role in 'Mukti-juddho' — the freedom struggle of Bangladesh by extending a helping hand. At that time, a large number of relief camps and refugee camps were established in West Bengal. The numerous refugees staying in these camps were subjected to persecution back in East Pakistan merely because they spoke Bengali; they became the target for speaking in Bengali. The fact of the

*English translation of the original speech delivered in Bengali.

matter is that the rulers of East Pakistan had attacked the Bengali-speaking people many times, even in 1952. The Bengalis fought against these atrocities and shed blood to save their language. The Bengali-speaking population raised the slogan: "They want to snatch away the language spoken by our forefathers." Bengalis had shed blood in the fight for language and to save the honour of their language. Again in 1970s, people sacrificed their lives in the freedom struggle in East Pakistan — Bangladesh was not formed till that time - and many had to flee across the border to settle in the refugee camps in West Bengal. Those who came to West Bengal have sadly passed away and now their third generation is living in the camps. How can they procure their proof and certificates now? I want to know about it from the Government.

And, I, Sir, want to take this opportunity. Everybody has spoken about the idea of India and I will definitely quote Tagore because our National Anthem actually is a five stanza poem. We use the first stanza as our National Anthem but the rest of the four stanzas are equally emphatic. In the second stanza, Tagore categorically says,

"Your call is announced continuously,
We heed your gracious call.
The Hindus, Buddhists, Sikhs, Jains, Muslims, and Christians.
The East and the West come
To the side of your throne
And weave the garland of love.

...*(Time-bell rings)*... Half a minute, Sir. Victory be to you, victory be to you, victory be to you.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you.

SHRI RITABRATA BANERJEE: Half a minute. Sir, I crave your indulgence.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Time is over.

SHRI RITABRATA BANERJEE: Sir, thirty seconds.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude.

SHRI RITABRATA BANERJEE: Sir, this idea of Tagore is under attack today. The idea of India is under attack today. We are facing the burns of Partition. Bengalis are still facing the consequences of Partition to this day. We have partitioned our soil; we must not partition our soul. We should not let our soul be split into two. I hereby oppose this Bill once again.

SHRI V. VIJAYASAI REDDY (Andhra Pradesh): Sir, I, on behalf of my Party, rise to support the Bill. However, YSR Congress Party believes in respecting all religions and our Leader, Shri Y.S. Jagan Mohan Reddy Garu, heads a State which looks beyond religion, caste and political affiliations in his transparent governance.

Mr. Deputy Chairman, Sir, the Citizenship (Amendment) Bill, 2019, we believe, is to give citizenship to those who have come here as victims of persecution, asylum-seekers and are here as the conditions back home were not conducive for a peaceful living. To that extent, we accept the Bill in its letter and spirit.

Sir, at the same time, the move to encourage influx with ulterior motives which could be a threat to the national security cannot be tolerated at any cost.

Sir, I have a few suggestions to make to the hon. Home Minister.

Sir, Clause 2(1) of the Bill seeks to incorporate a proviso creating a special window for the class of individuals enumerated thereon, primarily based on the religion, which should be avoided.

The Statement of Objects and Reasons of the Bill indicates that the special provision was needed due to the theological neighbouring nations. However, it is in the public domain that the minorities among the Islamic faith are persecuted in their countries. Sir, there are minorities among the minorities like Bohra Muslims and then Ahmadiyyas who are also being persecuted there, and if they seek asylum, the Government of India should positively consider their request in case they want to settle down in India. Therefore, eliminating Muslim migrants from the provisions of amendments might be taken up for consideration in furtherance of human gestures.

Sir, Clause 3A, introducing Section 6B, delegates the entire function of framing

the parameters to the Government for considering the applications for registration. Sir, it would be better if the Act lays down the rules and broad policy insofar as framing of rules is concerned.

Sir, the Third Schedule is being amended reducing the tenure of stay from eleven years to five years. Stringent rules of evidence and proof must be in place.

Sir, I wish to bring to your kind notice a few aspects in this regard. Sir, I wish to bring to your kind notice a few aspects in this regard, my last two points. Although India is not a signatory to the 1951 UN Refugee Convention granting refuge based on humanitarian considerations, it is arguably a norm and a customary international law. Every developing or developed country shares certain responsibilities in providing shelter to migrants. It is very unfortunate — I would like to reiterate, it is very unfortunate — that the Congress Party doesn't want to understand the plight of minority migrants. ...*(Interruptions)*... It is a fact that it has been the Congress culture to foist false cases against its political opponents and suppress them in India itself. It is the Congress culture. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude now.

SHRI V. VIJAYASAI REDDY: Sir, it is ironical that the Congress is talking about values in politics. It is very much ironical. The entire politics of Congress has been based on appeasement. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude now.

SHRI V. VIJAYASAI REDDY: For example, when Rajiv Gandhi turned down the decision taken by the Supreme Court in the Shah Bano case, injustice was done by the Congress Party towards Muslim women. Sir, we support the Bill. Thank you.

SHRI D. KUPENDRA REDDY (Karnataka): Sir, thank you for giving me the opportunity to speak on this Bill in this august House. On behalf of my Party, JD(S), I oppose this Bill.

Sir, this Bill divides people on the basis of religion. It is against the values of our Constitution. It targets mainly the Muslim brethren of our country. Since many generations, they have been residing in India and yet, they have been left out in

[Shri D. Kupendra Reddy]

the proposed amendments to Section 2. The proposed amendment to Section 2 includes illegal migrants from amongst six specific religious minorities. Other religious people suffer persecution in their countries and seek refuge from persecution. These amendments differentiate people on the grounds of religion. It is a violation of article 14 of the Constitution of India. Further, thousands of Sri Lankan people belonging to different communities entering into the country as refugees have also been left out in the proposed Amendment Bill. This would also be a deviation from and dilution of the policy of secularism of our country.

Therefore, I strongly oppose the Bill and urge the Government to refer this Bill to a Select Committee of the Parliament for scrutiny, and withdraw the proposal of amendments in the interest of secularism. Thank you, Sir.

DR. SASMIT PATRA (Odisha): * Hon'ble Chairman Sir, the Citizenship Amendment Bill, 2019 that is being discussed here, should not be viewed with a communal or religious perspective. Rather it should be viewed with a larger national perspective. The impact of this bill is being felt not only in India, but also in Bangladesh, Pakistan and Afghanistan. Odisha is a peace leaving and secular state. Our Chief Minister Shri Naveen Patnaik is well known as a secular Leader.

After analyzing the Bill, our party BJD feels that this bill has no link with NRC. NRC is a different issue and needs to be discussed at length. Citizenship Amendment Bill, 2019 has included Bangladesh, Pakistan and Afghanistan but excluded Sri Lanka. Earlier refugees were getting citizenship of the 11 years of habitation but now it has been reduced to 5 years which will benefit many people. BJD supports the bill and would like to after 3 suggestions to the government.

Firstly, Sri Lanka should be included in the bill. For decades people of Hindu and Muslim communities are being persecuted there and subjected to atrocities. They should not be deprived of this opportunity.

Secondly, this bill should not be linked to NRC. NRC is a vast subject and government must be ready to discuss it in future.

---

*English translation of the original speech delivered in Oriya.

Thirdly, since the Muslim community has not been included in the bill, they are apprehensive about the intention of the government. Hence, government must clarify its stand that it's not anti-Muslim as projected by some political parties.

Above all the bill should not be politicized. In the larger national interest the government should clearly express that it has no anti-Muslim agenda and dispel the misgivings of our Muslim brothers and sisters. We hope that the government would accept these suggestions of BJD and prove that it has no ill–intentions for the Muslim community and would work for the betterment of all communities like the Hindus, Sikhs, Jains, Buddhists and Christians etc.

Thank you Sir.

SHRI RIPUN BORA (Assam): Mr. Deputy Chairman, Sir, I am standing, with a heavy heart, to oppose this Bill. But I am not sure how far we will be successful in stalling this Bill. I am opposing this Bill. The whole country knows that Assam is burning, the North-Eastern Region is burning and lakhs of people are on the streets for days together. You have already finished Assam; you have finished the North-Eastern Region, but you have not learnt the lesson. Now, you are going to finish the entire country by the Citizenship (Amendment) Bill. It is not a question of Hindus. Are we not Hindus? Are the very people, who are agitating in Assam, not Hindus? They are all Hindus. It is a question of future and security of our country. I want to draw your attention to my Question No.2432, dated 23rd March, 2017, replied by the then External Affairs Minister in Rajya Sabha. I asked, "Whether it is a fact that there is a report of religious persecution taking place in Afghanistan and Pakistan after 1947 and in Bangladesh after 1971."

What is the reply of the Government? The reply is, "There are no authoritative statistics in this matter." Not only that, through my Question No.875, dated 23rd November, 2016, I asked, "How many Hindus infiltrated from Bangladesh and Pakistan up to 31st December, 2014." What is the reply of the hon. Home Minister? He replied, "No record is maintained." The hon. Home Minister, in his introductory speech, said that crores and crores religiously persecuted people have come and are living in India, but they have not been given citizenship under the Citizenship Act, 1955 because there is no such provision in the Act and that is why this

[Shri Ripun Bora]

Amendment Bill is brought. In my Question No.885, dated 25th July, 2018, I asked, "How many religiously persecuted people have applied for Indian citizenship?" What is the reply? Hon. Home Minister said, "Only 4044 applications are with the Government." Then, where are crores of people? Not only that, when I asked about the country-wise detail, he replied, "687 from Afghanistan; 84 from Bangladesh and 2508 from Pakistan." And, when I asked the religion-wise break-up, he replied that religion-wise break-up is not maintained. If you do not have information and if you do not have data, on what basis are you going to give citizenship to these people? On what basis, are you going to give citizenship to these people? What is your hidden agenda? Not only that, Sir. In my another question, I asked, post 1971 and pre-1971, how many people, how many Hindus migrated to Assam from Bangladesh? And, what is the reply? The Government said that there is no authentic figure available. I am quoting all these questions, you can check and verify. It is in the public domain. Not only that, the most surprising thing is that in NRC, Assam, names of 19.6 lakh people have been dropped. Now, the Home Minister is saying that these people will be given citizenship under CAB. But, how is it possible? These people are living in Assam for years together. They have been exercising their voting rights. They are doing Government jobs. They are holding lands. They are Indian citizens. In NRC applications, they have given documents as Indian citizens. And, in NRC hearing, they have given documents as Indian citizens. Now, how these people will say that they have come from Afghanistan; that they have come from Pakistan; that they have come from Bangladesh? That means by this CAB, you are going to force our Indians, our Hindu people to tell them as foreigners. You are going to do this. Not only that, you will be surprised to know in the Joint Parliamentary Committee meeting, — it is in para 2.14 of page no. 18 of the Report —, what the Director, IB submitted. The Director, IB said that it is not possible to verify that these persons have come due to religious persecution. To prove this is not possible. It is the statement of Director, IB statement. Not only that, Director, IB further said that those who have submitted any affidavit, those who have submitted any documents that they have come on religious persecution, that will have to be proved by Foreigners' Regional Registration Office. He further said that those who do not have any document, their cases will be referred to foreigners'

tribunal. Now, Sir, you see in the name of CAB, we are going to only push these people from pillar to post. Nobody will get citizenship. This is only a hidden agenda. This is only for political purpose, political polarization. The most surprising thing is what the Joint Director, RAW, said when he deposed before the Joint Parliamentary Committee. I am reading only the relevant portion, para 2.18 of page 19. He said, "...within which, they can exploit our secrets and infiltrate their own people into our own country." That is the matter of great concern for us. This is the apprehension of RAW. The Home Minister is saying now that we are doing the citizenship. But, the Director, RAW has said that it will pose threat, danger to the security of our country in the days to come.

Sir, finally, I want to say a few words in my mother tongue.

* "Hon'ble Deputy Chairman Sir, Assam is burning today. With this Citizenship Amendment Bill, 2019, the government of India is going to destroy Assam once again. They are going even to destroy the soul of Assam, the Assam Accord. After 40 years of constant struggle the people of Assam got NRC. But the government is going to modify NRC by passing the Bill. Hon'ble Deputy Chairman Sir, we have told the Home Minister that Assam is one such a state which even the British could not occupy, though they occupied the entire country. After having occupied all the parts of our country, the British could occupy Assam on 24th February, 1826. Not only that, Mughals attacked Assam 17 times, but they could not annex it. Brave Assamese generals Bir Lachit Borphukan, Bir Chilarai thwarted the Mughals' attempt to annex Assam. That's why I would like to say today that this Bill may be passed in the House, but Assamese people will never accept it. People of the North East would never accept it.

The blood of Bir Lachit Borphukan and Bir Chilarai is still flowing in our veins. We all Lachit people are giving slogans, "we will die, we will fight, but we won't accept CAB". Jai Aai Asom, Jai Aai Asom, Jai Aai Asom."

DR. SUBRAMANIAN SWAMY (Nominated): Mr. Deputy Chairman, Sir, I think, the principal Opposition party, the Congress Party, seems to be confused between this Amendment Bill and the NRC, and most of them have argued against the NRC.

---

*English translation of the original speech delivered in Assamese.

[Dr. Subramanian Swamy]

Those few, who have argued against this Amendment Bill, have, in fact, misled the House in some ways. Mr. Sibal was here and he said that the Citizenship Act does no reference whatsoever to religious persecution, but he ought to know that in the Constitution, there is Article 11, which says, "Parliament to regulate the right of citizenship by law - Nothing in the foregoing provisions of this Part shall derogate from the power of Parliament to make any provision with respect to the acquisition and termination of citizenship and all other matters relating to citizenship."

The Bill, in fact, in Clause 2 says, "In the Citizenship Act, 1955, in section 2, the following proviso shall be inserted, namely:- "Provided that any person belonging to Hindu, Sikh, Buddhist, Jain, Parsi or Christian community from Afghanistan, Bangladesh or Pakistan, who entered into India on or before the 31st day of December, 2014 and who has been exempted by the Central Government by or under clause (c) of sub-section (2) of Section 3 of the Passport (Entry into India) Act, 1920 or from the application of the provisions of the Foreigners Act, 1946, or any rule or order made thereunder, shall not be treated as illegal migrant for the purposes of this Act". So, the whole Amendment, that has been brought, is to bring this consideration that a fairly large number of people are running away from Pakistan and they are the Hindus, the Sikhs, the Buddhists, the Christians and the Parsis; not only Hindus and the associated Indic religions of Buddhists and Sikhs, but also those who are not of the Hindu faith, namely, Christians and Parsis. 'Zoroastrians' would be the correct word. Now, that has been brought in as an Amendment and the reason is that if you look at the percentage of population of Hindus, Sikhs, Buddhists, Christians and Parsis in the 1952 figures of Pakistan and today, there has been a very sharp decline in all these various religious groups. We have seen newspaper items about great deal of genocidal action in Pakistan against these people. Same thing is there in Bangladesh. There are daily occurrences against the Hindus there. In Afghanistan, one hardly needs to say what the Taliban has been doing. So, this Bill is most appropriate and the hon. Home Minister deserves congratulations for bringing it after years and years of recognition of this problem.

Now, on 25th November, 1947, the Congress Working Committee met and

passed a resolution urging citizenship for the refugees of Pakistan and said, "The Congress is bound to afford full protection for all those non-Muslims from Pakistan who have crossed the border and come over to India, or may do so, to save their life and honour." Now, they are saying, "You can't do this." But, their own Party, as far back...*(Interruptions)*... They have said it. They said, "You can't do it." They have referred to Article 14. I will come to Article 14 also. The amount of illiteracy in Congress is unbelievable. In Rajya Sabha, Dr. Manmohan Singh, it was just read out by someone, I again want to remind you what he said, he said "the minorities in countries like Bangladesh, have faced persecution, and it is our moral obligation that if circumstances force people, these unfortunate people, to seek refuge in our country, our approach to granting citizenship to these unfortunate persons should be more liberal." Dr. Manmohan Singh was here in the morning, when somebody read this out, after that, he has gone, he has not come back. I hope, they did not send him away. Then, the Chief Minister of Assam, Mr. Tarun Gogoi had submitted a memorandum to the then Prime Minister, Dr. Manmohan Singh on April 20th, 2012, pleading that Indian citizens who had to flee due to discrimination and religious persecution at the time of partition, should not be treated as foreigners and given citizenship. Later on, he filed an affidavit in Guwahati High Court and said that 'this is something our Government would like to do, we have approached the Central Government'. So, in all and all, all we can say is that the BJP Government has acted instead of giving speeches and passing Resolutions, which is what has been done by the Opposition, particularly by the Congress Party. I will deal with one last question, and then I will conclude. Sir, Article 14 does not bar this particular amendment. There have been a number of judgements. You cannot just blindly read what Article 14 says. Article 14 has undergone many scrutinies in many Court cases. One of the best presentations of Article 14, and what it means is the Antulay Case, where the Government had created a Special Court, and this was challenged in the Supreme Court that how can a Special Court be created for an individual? This is a violation of Article 14. Then, a nine-judge bench gave a judgement, which is a classic judgement of 1988, where they said that only where people who are equal in terms of entitlement, only there you can invoke Article 14. Today, for instance, on SPG, we have a separate security force for the Prime Minister. That is permitted because Prime Minister comes in a separate category. But, for the rest, the Members

5.00 P.M.

[Dr. Subramanian Swamy]

of Parliament and others, we have gone on the basis of not only the gradations, but, the security risks also. So, Article 14 says that you can make this distinction. We have made this distinction because in Pakistan, Bangladesh and Afghanistan, these groups, who have been identified, have been singled out for ill-treatment and oppression. As far as the Ahmadiyyas are concerned or the Shias are concerned, they would prefer any day going to Iran, which is a Shia country, or, to Bahrain, where the Ahmadiyyas are accepted as Muslims. Both of these communities declare themselves as Muslims. They do not say that they are distinct religious groups. It is the Wahhabi group in Pakistan, which says that these communities are not Muslims. But, the world in general, accepts them as Muslims. So, they cannot come into this category because these countries are Darul Islam. They have a religious constitution, where Islam has been accepted as the State religion. Therefore, to bring that in the Bill, is rubbish. In fact, many Muslims have come to our country to seek refuge. Tarek Fatah is one of the examples. Another example is Taslima Nasrin from Bangladesh. Then what happened? They said that this is only our intermediate point. Taslima Nasrin went and got the citizenship from Sweden, and Tarek Fatah got the citizenship from Canada.

I do not think a Pakistani Muslim wants to leave his nation and come to our country. There is no need to include them also in this bogus concept of Article 14 being Equality for All. Finally, I would say that Sri Lankan Tamils did not come to our country because of religious persecution. There was a war there. Because in the Tamil areas of Sri Lanka, there was a full-fledged war, they came here. After that, after our Government came, they have all been regularly going back. The Government of India has built houses for them. Now, it has dwindled from one crore to something like 15,000. In another six months, they will be no. ...*(Interruptions)*... This business of genocide and all is LTTE propaganda. ...*(Interruptions)*... Our Parliament cannot be used for LTTE propaganda.

SHRI T.K. RANGARAJAN: *

SHRI VAIKO: *

*Not recorded

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Nothing is going on record. ...*(Interruptions)*... Please sit down. ...*(Interruptions)*... Please take your seat, Mr. Vaiko.

DR. SUBRAMANIAN SWAMY: Therefore, I would say that this Bill is something which we need to protect ourselves. Thank you.

MESSAGE FROM LOK SABHA — *Contd*

The Personal Data Protection Bill, 2019

SECRETARY-GENERAL: I have to report to the House the following message received from the Lok Sabha, signed by the Secretary-General of the Lok Sabha.

"I am directed to inform you that Lok Sabha, at its sitting held on Wednesday, the 11th December, 2019, adopted the enclosed motion in regard to the Personal Data Protection Bill, 2019.

2. I am to request that the concurrence of Rajya Sabha in the said motion, and also the names of the Members of Rajya Sabha appointed to the Joint Committee, may be communicated to this House.

MOTION

"That the Bill to provide for protection of the privacy of individuals relating to their personal data, specify the flow and usage of personal data, create a relationship of trust between persons and entities processing the personal data, protect the rights of individuals whose personal data are processed, to create a framework for organisational and technical measures in processing of data, laying down norms for social media intermediary, cross-border transfer, accountability of entities processing personal data, remedies for unauthorised and harmful processing and to establish a Data Protection Authority of India for the said purposes and for matters connected therewith or incidental thereto be referred to a Joint Committee of the Houses consisting of the following 20 Members from this House, namely:-

1. Smt. Meenakshi Lekhi

2. Shri P.P. Chaudhary